सुविचार
जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो।
-हरिवंशराय बच्चन

Daily
THE PHOTON NEWS
सच के हक में...
द फोटोन न्यूज Published from Ranchi

Ranchi ● Monday, 05 January 2026 ● Year : 04 ● Issue : 349 ● Ranchi Edition ● Page : 12 ● Price : ₹3 ● www.thephotonnews.com
E-Paper : epaper.thephotonnews.com

12
Sara Ali Khan Shares Glimpses Of Her...

SHARE		
संसेक्स	:	75,364.69
निफ्टी	:	22,904.45

SARAFA		
सोना	:	8,575
चांदी	:	108.00

(नोट : सोना 22 कैरेट प्रति ग्राम)

BRIEF NEWS

दिल्ली ब्लास्ट : हर आतंकी डॉक्टर के पास थी घोस्ट सिम

NEW DELHI : दिल्ली में 10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट से जुड़े व्हाइट-कॉलर टेरर मॉड्यूल के आतंकी डॉक्टरों ने घोस्ट सिम कार्ड का इस्तेमाल किया था। इसके जरिए वे पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते थे। पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों ने रविवार को दावा किया कि आतंकी सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए डुअल-फोन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे। हर आरोपी के पास दो से तीन मोबाइल थे। शक से बचने के लिए इनके नाम पर रजिस्टर्ड एक क्लीन फोन होता था। दूसरा टेरर फोन था जिसके जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ वॉट्सऐप और टेलीग्राम पर बात करते थे। डिवाइस में फिजिकल सिम के बिना मैसेजिंग ऐप्स चलाने की सुविधा का फायदा उठाकर ही ये लोग डॉक्टरों को यूट्यूब के जरिए आइईडी बनाना सिखाते और हमले का निर्देश दे रहे थे। जांच के खुलासे के बाद ही टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट ने पिछले साल 28 नवंबर को निर्देश था कि वॉट्सऐप, टेलीग्राम और सिगनल के लिए एक्टिव सिम कार्ड का नियम लागू किया है।

जेल से 15वीं बार बाहर आएगा राम रहीम

CHANDIGARH : रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वियों के यौन उत्पीड़न और पत्रकार हत्या के मामलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहा डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर 40 दिन की पैरोल मिल गई है। इस दौरान राम रहीम डेरा सच्चा सौदा हेडक्वार्टर सिरसा में रहेगा। राम रहीम अभी अपनी दो साथी साध्वियों के साथ रेप के जुर्म में 20 साल की जेल की सजा काट रहा है। अगस्त 2017 में रेप केस में दोषी ठहराए जाने के बाद गुरमीत राम रहीम सिंह इस बार 15वीं बार जेल से बाहर आएगा। इससे पहले 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया था। 25 अगस्त 2017 को 2 साध्वियों के यौन शोषण केस में राम रहीम को 20 साल कैद हुई। इसके बाद 17 जनवरी 2019 को पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में उम्र कैद हुई।

रनवे पर फिसला बुद्ध एयर का प्लेन, बचे 55 यात्री

NEW DELHI : नेपाल के झापा जिला स्थित भद्रपुर एयरपोर्ट पर काठमांडू से आ रहा बुद्ध एयर का विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसल गया। विमान में सवार 51 यात्री और चार क्रू मेंबर सुरक्षित हैं, कुछ को मामूली चोटें आईं। घटना के बाद एविएशन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। बुद्ध एयर ने बताया कि घटना की विस्तृत जांच में नेपाल सिविल एविएशन अथॉरिटी (सीएएन) के साथ पूरा सहयोग किया जा रहा है। सीएएन के अनुसार लैंडिंग के समय विमान अपेक्षा से अधिक एंगल पर रनवे को छू गया, जिससे संतुलन बिगड़ गया।

न्यूयॉर्क के डिटेंशन सेंटर में हैं निकोलस मादुरो, चलाया जाएगा मुकदमा

कुछ समय के लिए वेनेजुएला को चलाएगा अमेरिका : डोनाल्ड ट्रंप

NEW DELHI @ PTI : अमेरिकी सैनिकों द्वारा दो जनवरी की रात वेनेजुएला पर हमला कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस को अगवा कर लिया गया था। इसके बाद उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखा गया है। उन पर हथियार-ड्रग्स से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सार्वजनिक रूप से कहा था कि अमेरिका कुछ समय के लिए वेनेजुएला को चलाएगा और वहां के तेल संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार को कहा कि वेनेजुएला को चलाने के लिए एक स्पेशलटीम बनाई गई है। इसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो, रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और अन्य शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। यह टीम वेनेजुएला में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सरकारी संस्थानों को दोबारा कामकाजी बनाने, तेल, ऊर्जा और सुरक्षा जैसे अहम सेक्टर को स्थिर करने, और ट्रांजिशन पीरियड को संभालने में मदद करेगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका इसके लिए वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मिलकर काम कर रहा है।

बनाई गई स्पेशल टीम, इसमें अमेरिकी विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री व कई अधिकारी शामिल

- वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ मिलकर किया जा रहा काम
- चीन बोला- अमेरिका मादुरो को तुरंत रिहा करे, राष्ट्रपति को अगवा करना गलत
- न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने भी मादुरो की गिरफ्तारी पर जताई नाराजगी

हमले में तबाह वेनेजुएला का मिलिट्री बेस

भारत के फंसे 9 हजार करोड़ की वापसी की उम्मीद

वेनेजुएला में हालात बदलने से भारत का अटका पैसा वापस आ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की सरकारी कंपनी ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के करीब 1 अरब डॉलर (लगभग 9,000 करोड़ रुपये) लंबे समय से फंसे हुए हैं, जो अब मिलने की संभावना है। फिलहाल वेनेजुएला के सैन क्रिस्टोबल तेल क्षेत्र में बहुत कम (5,000 से 10,000 बैरल रोज) तेल निकल रहा है। अमेरिका के नियंत्रण और प्रतिबंधों में ढील के बाद वहां नई मशीनें और ड्रिलिंग रिग लगाए जा सकेंगे, जिससे तेल उत्पादन बढ़ेगा। अमेरिकी हमले के बाद भारत ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार, भारत सरकार वेनेजुएला की बदलती स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। भारत ने वेनेजुएला के लोगों की सुरक्षा और भलाई के प्रति अपना समर्थन दोहराया है।

अंतरराष्ट्रीय व अमेरिकी कानून का उल्लंघन

चीन ने अमेरिका से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को तुरंत रिहा करने की मांग की है। दोनों इस समय अमेरिका की हिरासत में हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने रविवार को जारी बयान में कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह अपने देश ले जाना गलत है। इस मुद्दे का हल बातचीत से होना चाहिए। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे अच्छा काइंड एक्ट ऑफ वॉर बताया और कहा कि यह कदम अंतरराष्ट्रीय और अमेरिकी कानून दोनों का उल्लंघन है। उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई को गुंडागर्दी बताया है। उत्तर कोरियाई विदेश मंत्रालय का कहना है कि अमेरिका की यह कार्रवाई किसी भी देश की आजादी और संप्रभुता पर किया गया सबसे गंभीर हमला है।

निलंबित आईएएस विनय चौबे के घर के स्टाफ के नाम पर करोड़ों की बेनामी संपत्ति

PHOTON NEWS RANCHI : शराब और जमीन संबंधी घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच में निलंबित आईएएस अधिकारी विनय चौबे के विषय में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता चला है कि भ्रष्टाचार की रकम छिपाने के लिए न केवल रिश्तेदारों, बल्कि घर में काम करने वाले निजी स्टाफ को भी बेनामी संपत्तियों का मालिक बनाया गया। जानकारी के मुताबिक, एसीबी की तफ्तीश में मिले मनीट्रेल के सबूत एक सुनियोजित साजिश की ओर इशारा कर रहे हैं। जांच में यह सामने आया है कि रांची के सबसे महंगे और पॉश इलाकों में स्थित बेशकीमती संपत्तियां विनय चौबे के घरेलू स्टाफ के नाम पर दर्ज हैं। एसीबी की जांच में यह भी पाया गया कि इन कर्मचारियों की आय इतनी नहीं है कि वे शहर में एक छोटा फ्लैट तक खरीद सकें, इसके बावजूद, उनके नाम पर करोड़ों रुपये की जमीनें ली गईं। यह पूरी प्रक्रिया अवैध रूप से अर्जित धन को सफेद करने और वास्तविक स्वामित्व छिपाने के उद्देश्य से की गई। प्रारंभिक जांच में यह मामला सीधे तौर पर बेनामी लेनदेन और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा प्रतीत होता है। अब तक की जांच में जिन लोगों के नाम पर संपत्तियां खरीदी गई हैं, उनमें विनय सिंह, स्निग्धा सिंह, स्वप्ना संचिता, शिपिज त्रिवेदी और प्रियंका त्रिवेदी के नाम शामिल हैं।

- शराब और जमीन घोटाले में एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में हुआ बड़ा खुलासा
- तफ्तीश में मिले मनीट्रेल के सबूत कर रहे सुनियोजित साजिश की ओर इशारा
- अवैध रूप से अर्जित धन को सफेद करने के लिए छिपाया गया वास्तविक स्वामित्व

अनवर ढेबर के इशारे पर लागू हुआ छत्तीसगढ़ मॉडल

छत्तीसगढ़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में यह खुलासा हुआ है कि अनवर ढेबर के निर्देश पर झारखंड में छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मॉडल को लागू किया गया। छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट से जुड़े अभियुक्तों ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत दर्ज अपने बयानों में इस तथ्य को स्वीकार किया है। छत्तीसगढ़ ईडी ने अदालत में दाखिल अपनी रिपोर्ट में इन तथ्यों का उल्लेख किया है। ईडी ने जांच के दौरान सामने आए इन तथ्यों के आधार पर झारखंड सरकार से कुछ जानकारियां मांगी हैं, लेकिन अब तक संबंधित सूचनाएं ईडी को उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में यह बात सामने आई है कि अनवर ढेबर इस शराब सिंडिकेट का किंगपिन है। भारतीय दूरसंचार अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी को ढेबर के कहने पर ही छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का प्रबंध निदेशक बनाया गया था। छत्तीसगढ़ के तत्कालीन उत्पाद सचिव अनिल टुटेजा और अरुणपति त्रिपाठी शराब की बिक्री और कमीशन वसूली से जुड़ी रिपोर्ट सीधे अनवर ढेबर को देते थे। ढेबर ने छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले को अंजाम देने के लिए एक संगठित और सुनियोजित सिंडिकेट तैयार किया था।

ब्रिज का पिलर क्षतिग्रस्त, इंटरसिटी व राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों का परिचालन प्रभावित

लोहरदगा में बड़ा हादसा टला, समय रहते रोक ली गई मेमू ट्रेन, सैकड़ों यात्रियों की बची जान

PHOTON NEWS LOHARDAGA : रविवार को लोहरदगा में एक बड़ा रेल हादसा होते-होते टल गया। रांची से लोहरदगा आ रही मेमू ट्रेन को समय रहते रोक लिया गया, जिससे सैकड़ों यात्रियों की जान बच गई। कोयल नदी पर बने भक्सो रेलवे पुल के पांच नंबर पिलर में दरार आने की जानकारी मिलते ही रेलवे कर्मियों ने सतर्कता दिखाते हुए ट्रेन को पुल से पहले ही रोक दिया। जानकारी के अनुसार, रांची से टोरी की ओर जाने वाली मेमू ट्रेन संख्या 68027 निर्धारित समय पर रवाना हुई थी। रविवार होने के कारण ट्रेन में यात्रियों की भीड़ सामान्य दिनों से अधिक थी। जैसे ही ट्रेन लोहरदगा स्टेशन से कुछ दूरी पहले कोयल नदी रेलवे पुल के समीप पहुंची, वहां मौजूद रेलवे कर्मियों को पुल के पिलर और गार्डर में क्षति की सूचना मिली। इसके बाद बिना देरी किए ट्रेन को तत्काल रोक दिया गया।

रविवार होने के कारण अधिक थी भीड़

रेलवे ट्रैक के रास्ते पुल पार कर नदी के किनारे पहुंच कई यात्री, इसके बाद अपने-अपने गंतव्य के लिए हुए रवाना

अचानक ट्रेन रुकने से मच गई अफरातफरी

अचानक ट्रेन रुकने से यात्रियों में अफरातफरी मच गई। पुल के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी फैलते ही यात्री घबरा गए। सुरक्षा को देखते हुए यात्रियों को ट्रेन से नीचे उतारा गया। कई यात्री रेलवे ट्रैक के रास्ते पुल पार कर नदी के किनारे पहुंचे, जहां पहले से मौजूद ऑटो, टेंपो और अन्य निजी वाहनों से अपने-अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। रेलवे पुल के क्षतिग्रस्त होने के कारण लोहरदगा-रांची रेलखंड पर रेल परिचालन बाधित हो गया है। मेमू ट्रेन के अलावा सासाराम पैसेंजर, इंटरसिटी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस सहित अन्य ट्रेनों के परिचालन पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेनों को रोक दिया गया, जबकि कुछ के मार्ग में परिवर्तन किया गया है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पहुंचे झारखंड

DEOGHAR : रविवार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का देवघर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस दौरान मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, डीआईजी अंबर लकड़ा, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी सौरभ ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। इसके अलावा एयरपोर्ट के बाहर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आगमन पर पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दो दिवसीय प्रवास के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त बीएलओ से भी मिलेंगे।

गोबिंद प्रमाणिक ने गोपालगंज-3 सीट से भरा था पर्चा

बांग्लादेश में हिंदू नेता के चुनाव लड़ने पर रोक, नामांकन खारिज

AGENCY NEW DELHI : बांग्लादेश में एक हिंदू नेता को चुनाव लड़ने से रोक दिया गया है। बांग्लादेश में 12 फरवरी को चुनाव होने वाले हैं। गोबिंद चंद्र प्रमाणिक ने संसदीय चुनावों के लिए गोपालगंज-3 सीट से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर ने उनका नामांकन वापस कर दिया। पूर्व पीएम शेख हसीना गोपालगंज-3 से सांसद थीं। यहां 50% से ज्यादा हिंदू वोटर्स हैं। गोबिंद निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते थे। वह पेशे से वकील हैं और बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत (बीजेएचएम) नामक संगठन के महासचिव भी हैं। बीजेएचएम कुल 23 संगठनों का हिंदुत्ववादी गठबंधन है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोबिंद ने कहा कि बांग्लादेश में एक प्रावधान है जिसके हिसाब से एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपने इलाके के 1% वोटरों के साइन लाने होते हैं।

टी-20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आएगी बांग्लादेश की टीम

NEW DELHI : बांग्लादेश की टीम टी-20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी। यह जानकारी बांग्लादेशी अखबार द डेली स्टार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के एक अधिकारी के हवाले से दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को बीसीसीआई के आदेश पर आईपीएल से बाहर करने के बाद बीसीबी ने यह फैसला लिया है। बोर्ड ने आईसीसी से कहा है कि उसके मैच श्रीलंका में कराए जाएं। अब आईसीसी तय करेगा कि बांग्लादेश के मैच श्रीलंका में होंगे या नहीं। हालांकि बीसीबी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन यूनुस सरकार में खेल सलाहकार (खेल मंत्री) आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए बीसीबी के फैसले का स्वागत किया है।

सुबह में छाया रहा कोहरा, तापमान में वृद्धि के बाद भी महसूस हुई कनकनी

13 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट, कल तक स्कूल बंद

PHOTON NEWS RANCHI : रविवार को राजधानी रांची सहित झारखंड के कई क्षेत्रों में सुबह में कोहरा छाया रहा। हल्की धूप निकली। तापमान में वृद्धि के बावजूद कनकनी महसूस की गई। इस बीच रांची मौसम विभाग की ओर से झारखंड के 13 जिलों में 6 जनवरी तक सुबह में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। लातेहार में सबसे कम 6.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकार्ड किया गया। विभाग के अनुसार राज्य के जिन जिलों में शीतलहर चलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, उनमें उत्तर पश्चिम और मध्यवर्ती जिले शामिल हैं। कड़ाके की ठंड और शीतलहरी को देखते हुए रांची जिला प्रशासन ने केजी से लेकर कक्षा 12वी तक के सभी कक्षाएं दो दिन बंद रखने का निर्देश जारी किया है।

लातेहार में सबसे कम 6.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया मिनिमम टेंपरेचर

अगले तीन दिनों में चार डिग्री तक गिरेगा पारा

मौसम विभाग ने अगले तीन दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में तीन से चार डिग्री की गिरावट होने की जानकारी दी है। मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, उत्तर पश्चिम जिले गढ़वा पलामू छात्र लातेहार के अलावा मध्यवर्ती जिले रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, खूंटी, गुमला, लोहरदगा कोडरमा और धनबाद शीतलहर की चपेट में रहेंगे। रविवार को रांची में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10.7 सात डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। इसी प्रकार जमशेदपुर में अधिकतम 26.3 और न्यूनतम 12.7 डिग्री, डाल्टनगंज में अधिकतम 21.8 और 12.7 डिग्री, बोकारो में अधिकतम 23.5 और न्यूनतम 11.6 डिग्री और चाईबासा में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया।

नया संकेत अब टेक्नोलॉजी के साथ डेटा कैपेबिलिटी को बढ़ाने का बड़ा प्लान

इंडियन आर्मी के काम करने की स्टाइल में आया बड़ा बदलाव

PHOTON NEWS @ RESEARCH DESK : पिछले कुछ वर्षों से इंडियन डिफेंस सिस्टम यानी भारतीय रक्षा प्रणाली को पेशेवर तरीके से डेवलप करने पर सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना के तीनों विंग- थल सेना, जल सेना और वायु सेना ने आपसी समन्वय का बेहतरीन परिचय देते हुए सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ करारा जवाब दिया। पूरी दुनिया के सामने नई स्टाइल में काम करने का संदेश दिया गया। इस दौरान तकनीकी दृष्टि से उत्पन्न चुनौतियों का गंभीरता से अध्ययन किया गया। भविष्य के लिए नई रणनीति अख्तियार करने का बड़ा प्लान तैयार किया गया है। आगे के युद्ध लिए खुद को तैयार करने में जुटी सेना ने साल 2026 और 2027 को नेटवर्किंग और डेटा सेंट्रिसिटी वर्ष के तौर पर मनाने का फैसला किया है। जैसा कि हमने देखा, साल 2024 और 25 में अत्याधुनिक उपकरण व तकनीकें तेजी से सैनिकों तक पहुंचीं। अब इस साल फोकस इन सभी तकनीकों और प्रणालियों को आपस में जोड़ने पर होगा। इस मुहिम का लक्ष्य ड्रोन, सैटेलाइट, शूटर (टैंक, मिसाइल आदि) और कमांडरों को एक सुरक्षित रीयल टाइम नेटवर्क से जोड़ना है। साथ ही विशाल डेटा सेट का विश्लेषण कर दुश्मन की चालों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता विकसित की जाएगी।

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ दिया करारा जवाब

भविष्य की स्थितियों का सामना करने के लिए नई रणनीति के साथ हो रही तैयारी

- साल 2024 और 2025 में हमारे सैनिकों तक पहुंचे अत्याधुनिक उपकरण व तकनीकें
- ड्रोन, सैटेलाइट, शूटर व कमांडरों को सुरक्षित रीयल टाइम नेटवर्क से जोड़ना है लक्ष्य

सटीक एनालिसिस से दुश्मन की चालों का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता हो रही विकसित

खड़े किए जा चुके हैं कई सॉफ्टवेयर सिस्टम

आधुनिक युद्ध में लड़ाई सीमा के अलावा सूचना, डेटा और सोच के स्तर पर होती है। ऐसे में वही सेना आगे रहती है, जिसके पास सही समय पर सही जानकारी हो, ताकि तेजी से फैसले लिए जा सकें। इसलिए सेना पहले ही देशभर में मजबूत डिजिटल नेटवर्क, डेटा सेंटर और कई सॉफ्टवेयर सिस्टम खड़े कर चुकी है।

एआई और ऑटोमेशन की ली जाएगी मदद

जानकारी के अनुसार, आने वाले दो वर्षों में सभी प्रणालियों को आपस में जोड़ा जाएगा, ताकि अलग-अलग जगह से आने वाली जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो सके। इससे कमांडरों को हालात की साफ तस्वीर मिलेगी, जिससे फैसले तेज व सटीक हो सकेंगे। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और ऑटोमेशन की मदद ली जाएगी। इस पहल का मकसद नौसेना और वायुसेना के साथ और बेहतर तालमेल बनाना भी है। जब सभी सेनाएं एक ही नेटवर्क और जानकारी पर काम करेंगी, तो संयुक्त अभियानों की क्षमता और प्रभाव दोनों बढ़ेंगे। भविष्य के बदलाव की नींव तीन मुख्य बातों पर निर्भर है- डेटा, नेटवर्क और लोग। डेटा को अब एक रणनीतिक संसाधन के रूप में देखा जाएगा। इसके लिए साफ नियम बनाए जाएंगे कि कौन सा डेटा कहां से आएगा, कौन उसका इस्तेमाल करेगा और कैसे सुरक्षित रखा जाएगा।

इंदौर के बाद गांधीनगर में दूषित पानी पीने से 104 बच्चे हो गए बीमार

GANDHINAGAR : इंदौर के बाद अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में गंदा पानी पीने से पिछले तीन दिनों 104 बच्चे बीमार हो गए। इनमें से 50 प्रतिशत बच्चों को टाइफाइड हुआ है। हालात इतने बिगड़े कि सिविल अस्पताल में बच्चों भर्ती करने के लिए नया वार्ड खोलना पड़ा। इंदौर की तरह यहां भी पीने के पानी की पाइप लाइन में सीवेज की गंदगी मिल रही थी। शहर के सेक्टर-24, 28 और आदिवाड़ा इलाके के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रशासन ने पानी की सप्लाई जांची तो 10 जगह लीकेज मिले। स्मार्ट सिटी योजना के तहत करोड़ों की लागत से बिछाई गई नई पाइपलाइन में यह लीकेज थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए 40 स्वास्थ्य टीमें तैनात की गई हैं, जो 10 हजार से ज्यादा घरों की जांच कर चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने भी मामले का संज्ञान लिया है।

वॉलीबॉल चैंपियनशिप का पीएम ने किया उद्घाटन, कहा

बनारस में जोश हाई, जेन-जेड के हाथों में तिरंगा देख होता है गर्व

VARANASHI @ PTI : रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 72वीं नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का वर्चुअली उद्घाटन किया। अपने संबोधन में मोदी ने कहा कि देश के 28 राज्यों की 58 टीमें यहां जुटी हैं। आप सभी एक भारत-श्रेष्ठ भारत की बहुत सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में बनारस का जोश हाई रहेगा। हमें बहुत गर्व होता है, जब जेन-जेड को खेल के मैदान में तिरंगा फहराते देखते हैं। इस दौरान उन्होंने प्लेयर्स को काशी की कहावत भी सुनाई। कहा कि हमारे बनारस में कहा जाता है, बनारस के जानय के चाहत हऊवै तो बनारस आवै के पड़ी यानी बनारस को जानना है, तो आपको बनारस आना पड़ेगा। आप सब अब बनारस आ गए हैं, तो बनारस को जान भी जाएंगे। इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि पिछले 11 सालों में सबने एक नए भारत को देखा है, भारत को बदलते देखा है। देश में एक नई खेल संस्कृति को पनपते देखा है।

प्रतियोगिता में 28 राज्यों की 58 टीमें ले रहीं भाग

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पत्नी के साथ की पूजा

RANCHI : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार रविवार को झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इसी क्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का देवघर एयरपोर्ट पर आगमन हुआ। इस दौरान मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, डीआईजी संथाल परगना अंबर लकड़ा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा पुलिस अधीक्षक सौरभ, अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार के जरिये पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया गया। इसके अलावा एयरपोर्ट के बाहर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आगमन पर पुलिस जवानों की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त दो दिवसीय प्रवास पर झारखंड के देवघर पहुंचे है। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करेंगे और बीएलओ से मिलेंगे।

यात्री शेड में मिले शव की हो गई पहचान हत्या में शामिल महिला सहित तीन अरेस्ट

ओझा-गुनी के चक्कर में हुई थी घटना, मानमती पहले भी जा चुकी है जेल

PHOTON NEWS GARHWA : भवनाथपुर-केतार मुख्य पथ पर दुधमनिया घाट के पास यात्री शेड में 3 जनवरी को जो शव मिला था, उसकी पहचान हो गई है। शव की पहचान पलामू जिले के पांडू थाने के मुरमाकला गांव निवासी रुखी रजवार के रूप में हुई है। रखी रजवार की कनपटी में गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने 10 घंटे के अंदर मामले का खुलासा करते हुए हत्या में शामिल एक महिला सहित तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यही नहीं, इनकी निशानदेही पर दो देसी कट्टा, एक 3'15 बोर की गोली और एक खोखा भी बरामद किया गया है। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सत्येंद्र नारायण सिंह ने रविवार को प्रेसवार्ता में बताया कि भवनाथपुर-केतार मुख्य मार्ग पर यात्री शेड में एक व्यक्ति की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संदर्भ में मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में पाए गए कागजातों के आधार पर मृतक की पहचान की गई। अनुसंधान के क्रम में आए तथ्यों का विश्लेषण करने के पश्चात सीता रजवार, ग्राम सेमरी, टोला परती मांझी, थाना उंटारी रोड, पलामू को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि मनोज रजवार, ग्राम बेंदुआ, थाना उंटारी रोड, पलामू ने रुखी रजवार को गोली मारी थी। गिरफ्तार मनोज रजवार ने हत्या करने की बात स्वीकार कर ली और हत्या में प्रयुक्त हथियार के अलावा एक अन्य हथियार बरामद किया गया।

जानकारी देते एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह (बाएं से दूसरे) व गिरफ्तार आरोपी

मानमती ने रुखी रजवार पर मढ़ा था आरोप

एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सीता रजवार की बेटी की मौत कुछ दिन पहले हुई थी। गांव वालों ने सीता को बताया कि भवनाथपुर के सिंघिताली गांव में मानमती कुंवर ओझा-गुनी का काम करती है। वह बता देगी कि तुम्हारी बेटी की मौत का कारण क्या था। 25 दिन पूर्व सीता रजवार मानमती कुंवर के घर गई। मानमती ने उसे बताया गया कि तुम्हारे घर के दक्षिण दिशा की तरफ जो घर है, उसी आदमी ने भूत चढ़ाकर तुम्हारी बेटी को मार दिया है। रुखी रजवार भी पहले ओझा-गुनी का काम करता था, इसलिए सीता को मानमती की बात पर भरोसा हो गया। सीता ने अपने ममेरे साले मनोज रजवार के साथ मिलकर रुखी की हत्या करने की योजना बनाई। एसडीपीओ ने बताया कि पूर्व में सीता व मनोज माओवादी संगठन में एकसाथ काम करते थे। उसी समय पार्टी की ओर से इन्हें सुरक्षा के लिए हथियार दिया गया था।

इस तरह घटना को दिया अंजाम : 2 जनवरी को सीता व मनोज मृतक रुखी को अपने लूना मोपेड से लेकर गांव से निकले और कंडी में दुकान से शराब खरीद कर केतार के रास्ते यात्रीशेड में रुके। यहां तीनों ने शराब पीया। जब रुखी रजवार नशे में धुत्त हो गया, तब सीता ने रुखी की कनपटी में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद मनोज ने घटनास्थल से थोड़ी दूर पर कट्टा छिपा दिया और दोनों अपने गांव चले गए। पुलिस ने रविवार को सीता रजवार, मनोज रजवार व मानमती कुंवर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इससे पूर्व भी मानमती कुंवर जून में ओझा-गुनी के मामले में भवनाथपुर थाना से जेल जा चुकी है। छापामारी दल में एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह, भवनाथपुर के थाना प्रभारी रजनी रंजन, अवर निरीक्षक परवेज आलम, हवलदार सुनील कुमार पासवान, आरक्षी पंकज कुमार पासवान, सूरज कुमार, चंदा कुमारी व चौकीदार अंकित कुमार गुप्ता शामिल थे।

BRIEF NEWS

बरवादाग गांव में युवती ने की खुदकुशी

KHUNTI : जरियागढ़ थाना क्षेत्र के बरवादाग गांव में शनिवार शाम 18 वर्षीय युवती रानी परवीन ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। वह उसी गांव के कलीम खान की बेटी थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, शनिवार को रानी परवीन धनिया पत्ती तोड़ने के लिए बड़ी जाने की बात कहकर घर से निकली थी। देर शाम तक जब वह घर नहीं लौटी, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। काफी तलाश के बाद जब परिजन नवनिर्मित घर पहुंचे, तो वहां दुपट्टे के सहारे फंदे से लटका रानी परवीन का शव देखा। यह दृश्य देख परिजनों में कोहराम मच गया और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी जरिया गढ़ थाना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर पुलिस तुरंत बरवादाग गांव पहुंची और शव को कब्जे में लेकर थाना लाई। रविवार को सदर अस्पताल खूंटी में पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया। रविवार को ही रानी परवीन को बरवादाग कब्रिस्तान में सुपुर्द-ए-खाक किया गया।

फायरिंग मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

DHANBAD : निरसा थाना क्षेत्र के कालीमाटी गांव में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपित को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त देशी पिस्टल भी बरामद कर लिया है। उल्लेखनीय है कि 1 जनवरी 2026 को निरसा थाना प्रभारी को कालीमाटी गांव में फायरिंग की सूचना मिली थी। सूचना के सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए दिवा गश्ती पदाधिकारी को घटनास्थल भेजा गया। पुलिस टीम के मौके पर पहुंचने पर जांच में पाया गया कि वादी निरंजन कुमार चौहान और अभियुक्तों के बीच पैसे के लेनझेदन को लेकर विवाद हुआ था, जो गाली-गलौज एवं मारपीट में बदल गया। इसी दौरान अभियुक्त युवराज सिंह ने पिस्टल से कई राउंड फायरिंग की। रविवार को निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला ने बताया कि घटनास्थल से पुलिस ने 6 खोखा बरामद किया। वादी के लिखित आवेदन के आधार पर निरसा थाने में पांच आरोपितों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। कांड दर्ज होने के बाद पुलिस की ओर से लगातार छापामारी की जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने मुख्य आरोपित युवराज सिंह (20), निवासी माताडीह कॉलोनी, थाना निरसा को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक देशी पिस्टल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार आरोपित का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। युवराज सिंह के विरुद्ध पूर्व में निरसा थाना में अन्य मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य फरार आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

लापता बच्चे का मिला शव, हत्या की आशंका

घर के पीछे कुएं में दोस्तों के साथ खेलते-खेलते गिर गया था बच्चा, परिजन रहे अनजान

AGENCY PALAMU : जिले के पंडवा में तीन दिनों से लापता बच्चे का घर के पीछे कुएं से शव रविवार को मिला। बच्चा अन्य बच्चों के साथ खेलने के क्रम में गायब हो गया था और उसका कोई अता-पता नहीं चल पा रहा था। सूचना मिलने पर पड़वा पुलिस मौके पर पहुंची और कुएं से शव को निकालकर एमएमसीएच में पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने बच्चे को गायब कर हत्या करने के बाद कुएं में डाल देने की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बच्चे की पहचान पड़वा निवासी प्रमोद कुमार मेहता के एकलौते अंकुश राज (2) के रूप में हुई है। पिता के अनुसार 1 जनवरी की दोपहर से अंकुश लापता था। पंडवा थाना को लिखित जानकारी दी थी। परिवार के लोग भी भी बच्चे की अपने स्तर से खोजबीन कर रहे थे। इसी क्रम में गांव की एक महिला ने रविवार सुबह घर के पीछे के कुएं में झांक कर देखा तो अंकुश का शव पानी में तैर रहा था। पंडवा थाना प्रभारी अंचित कुमार ने कहा कि बच्चे की मौत कुएं में गिरने से हुई या किसी अन्य कारण से, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पायेगा। कुएं के पानी को पुलिस ने जांच के लिए लिया है। मामले में पुलिस डायटम टेस्ट करायेगी।

घटनास्थल पर लगी लोगों की भीड़

इधर, आस-पास के लोगों ने दबी जुबान से अशांका जतायी कि पहले बच्चे को गायब किया गया। दो दिन बाद हत्या कर शनिवार रात शव कुएं में डाल दिया। जहां से बच्चे का शव पुलिस ने बरामद किया है, वहां बच्चा जा ही नहीं सकता है। मौके पर एसआई चिंटू कुमार, शिव गोविंद मेहता, बसपा नेता राजन मेहता, उप मुखिया सुरजीत कुमार मेहता उर्फ टिंकू सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे।

रेलवे पुल बंद होने से टोरी की जगह नगजुआ से चलेगी मेमू

LOHARDAGA : लोहरदगा में दक्षिण कोयल नदी पर बने रेलवे पुल में तकनीकी खराबी आज जाने के कारण रांची व टोरी के बीच ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है। सांसद सुखदेव भगत के आग्रह पर डीआरएम ने बताया कि दक्षिण कोयल रेलवे पुल में कुछ तकनीकी त्रुटियां पाई गई हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए फिलहाल लोहरदगा स्टेशन तक आने वाली ट्रेनों को रोका गया है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत प्रतिदिन मेमू ट्रेन नगजुआ स्टेशन से रांची के बीच संचालित की जाएगी। वहीं राजधानी एक्सप्रेस को बरकाकाना-टोरी रूट से चलाने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा रांची-सासाराम ट्रेन का भी वैकल्पिक मार्ग से परिचालन किया जाएगा। ट्रेन परिचालन बंद होने की सूचना मिलते ही सांसद सुखदेव भगत ने रांची रेल मंडल के डीआरएम से फोन पर बात कर वस्तुस्थिति की जानकारी ली। सांसद ने कहा कि लोहरदगा मेमू ट्रेन जिले की लाइफलाइन है। प्रतिदिन हजारों यात्री इसी ट्रेन से आवागमन करते हैं। अचानक परिचालन बंद होने से छात्र, कर्मचारी और आम यात्रियों को गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। डीआरएम ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व ही रेलवे पुल का निरीक्षण किया गया था। तकनीकी विशेषज्ञों को मौके पर बुलाया गया है और जांच के बाद मरम्मत कार्य कराया जाएगा। सांसद सुखदेव भगत ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि नगजुआ स्टेशन पर टेंपो और बसों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था की जाए, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

हजारीबाग में कल तक सभी विद्यालयों में कक्षाएं स्थगित

HAZARIBAG : भारत मौसम विज्ञान विभाग, भारत मौसम विज्ञान केंद्र, झारखंड (रांची) द्वारा जारी विशेष बुलेटिन के अनुसार, राज्य में भारी ठंड एवं शीतलहरी की चेतावनी दी गई है। उक्त चेतावनी के तहत हजारीबाग जिले को येलो जोन की श्रेणी में चिह्नित करते हुए अत्यधिक ठंड एवं शीतलहरी की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम की इस प्रतिकूल स्थिति को देखते हुए तथा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 की धारा-34 के अंतर्गत हजारीबाग जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, गैर-सरकारी एवं निजी विद्यालयों में कक्षा केजी से 12वीं तक की पठन-पाठन गतिविधियां 5 व 6 जनवरी तक स्थगित रखने का आदेश दिया गया है। सभी

विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का शत-प्रतिशत अनुपालन करेंगे। हालांकि, यदि उक्त अवधि में किसी विद्यालय में कक्षा 10वीं अथवा 12वीं की प्री-बोर्ड परीक्षा पूर्व से निर्धारित है, तो ऐसी स्थिति में परीक्षा का संचालन पूर्वाह्न 10 बजे के बाद ही किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा अभिभावकों, विद्यालय प्रबंधन एवं आमजन से अपील की गई है कि बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आवश्यक सतर्कता बरतें एवं प्रशासन द्वारा जारी निदेर्शों का पालन करें।

टुंडी प्रखंड में कर दी गई बीएसओ की पदस्थापना आपूर्ति विभाग असमंजस में

DHANBAD : सरकारी अनदेखी का नया मामला धनबाद जिले में सामने आया है। यहां आपूर्ति विभाग ने बिना पद सृजन के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी (बीएसओ) की पदस्थापना कर दी है। ऐसे में जिला आपूर्ति विभाग भी असमंजस में है कि बिना पद सृजन के पदस्थापित अधिकारी अपना योगदान कैसे देंगे। पूर्व में यहां पूर्वी टुंडी, कलियासोल और एग्यारकुंड नए प्रखंड बने हैं। इन प्रखंडों में अभी तक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी का पद सृजित नहीं किया गया है। इसके बावजूद कार्मिक विभाग ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी टुंडी के पद पर पदस्थापना कर दी है। पदस्थापना की सूचना मिलने के बाद से यहां का आपूर्ति विभाग असमंजस में पड़ गया। इस संबंध में जिला अपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि यह मामला राज्य मुख्यालय का है। मुख्यालय से जैसा आदेश मिलेगा, उसी प्रकार कार्रवाई की जाएगी। विभाग की मानें तो बिना पद सृजित किए किसी भी पदाधिकारी की पदस्थापना भूलवश हुई होगी। ऐसी स्थिति में पदस्थापना वापस होगी। पहले प्रखंड आपूर्ति का पद सृजित किया जाएगा। इसके बाद ही पदस्थापना की जाएगी।

महिला को बंधक बना जेवर दुकान से लाखों की लूट, जांच में जुटी पुलिस

AGENCY DHANBAD : धनबाद में एक बार फिर से अपराधियों ने एक जेवलरी दुकानों को निशाना बनाया है। एक महिला को बंधक बनाकर अपराधियों ने ज्वेलरी दुकान से लाखों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने महुदा थाना से महज चंद मीटर की दूरी पर लूट की इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला धनबाद-रांची मुख्य मार्ग के महुदा थाना अंतर्गत महुदा बाजार की है। जहां लक्ष्मी ज्वेलर्स में बीती रात अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। ज्वेलरी दुकान के मालिक अमित कुमार वर्मा ने बताया कि उन्हें लोगों ने तड़के सुबह घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अपराधियों के पास तलवार जैसा

जांच करते पुलिस पदाधिकारी

हथियार था। लुटेरों ने घटना को अंजाम देते वक्त दुकान के पीछे घर में रहने वाले एक परिवार को बंधक बना लिया था। इसके बाद दुकान में लगे चार ताले को तोड़कर करीब 6 लाख रुपये की ज्वेलरी लूट कर ले गए। उन्होंने बताया कि इस दौरान लुटेरों ने ज्वेलरी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी काट कर अपने साथ ले गए। वहीं, अपराधियों की ओर से बंधक बनाई गई महिला कुंती देवी ने बताया कि उनके पति काम पर गए हुए थे, घर में वह और उनके बच्चे ही थे। उन्होंने बताया कि देर रात उन्हें कुछ आवाज सुनाई दी। वह जब बाहर निकली तो उन्हें दो लोग नजर आए जो अपना चेहरा ढके हुए थे। उन्होंने बताया कि इसके बाद लुटेरों ने हथियार दिखा कर उन्हें और उनके बच्चे को घर के अंदर खामोश रहने की चेतावनी दी। इसके बाद अपराधी लूट की घटना को अंजाम देकर चलते बने। उन्होंने बताया कि इसके बाद जब उनके पति घर आए तो वह थाना भी गई, लेकिन थाने में उन्हें कोई नही मिला। तब उन्होंने मुहल्ले वालों को इसकी सूचना दी। वहीं, घटना की जांच के दौरान डॉग स्क्वायड को भी लाया गया, लेकिन पुलिस के हांथ अबतक खाली है।

राजनीति विस्थापन व मुआवजे को लेकर पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक ने खड़े किए हेमंत सरकार पर सवाल

राज्य सरकार पर कांग्रेस नेताओं को भरोसा नहीं, जाएंगे कोर्ट

PHOTON NEWS HAZARIBAG : झारखंड में झामुमो, कांग्रेस व राजद के गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन यहां के कांग्रेस नेताओं को अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है। जिले के केरेडारी में विस्थापन और मुआवजे को लेकर चल रहा विवाद तूल पकड़ रहा है। राज्य के पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता योगेंद्र साव और उनकी बेटी व पूर्व विधायक अंबा प्रसार ने हेमंत सरकार से भरोसा उठने की बात कही है। अंबा प्रसाद कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव भी हैं। दोनों पिता-पुत्री ने अब न्याय के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने की बात कही है।

ज्ञात हो कि कुछ दिनों पूर्व योगेंद्र साव ने न्याय की मांग करते हुए रातों-रात सड़क पर दीवार खड़ी कर दी थी और वहीं धरना देकर बैठ गए थे। दूसरे दिन जब जिला प्रशासन को कोयला परिवहन बंद होने की जानकारी मिली, तो दंडाधिकारी की अगुवाई में पुलिस बल ने योगेंद्र साव को धरनास्थल से हटा दिया था। इस घटना के बाद योगेंद्र साव और उग्र तेवर में दिख रहे हैं। योगेंद्र साव ने रविवार को एक बयान में कहा कि उन्हें इस सरकार पर भरोसा नहीं है। अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि यह सरकार उनकी नहीं है। सरकार जनता की होनी चाहिए। अब जनता को अपनी मांगों और न्याय के लिए सड़क पर आना होगा। योगेंद्र साव ने अपनी हत्या की आशंका भी जताई है।

योगेंद्र साव

अंबा प्रसाद

विस्थापितों के लिए मरने को भी तैयार हूं : अंबा प्रसाद

पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि इस सरकार से लड़ाई लड़ना जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। सरकार की आंखें खुलें, इसके लिए प्रयास कर रही हूं। विस्थापितों को न्याय मिलना चाहिए और 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून पूरी तरह लागू होना चाहिए। अंबा प्रसाद ने कहा कि विस्थापितों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। विस्थापितों के लिए अगर मरना भी पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं।

विस्थापन लंबे समय से बड़ा मुद्दा

यहां बता दें कि हजारीबाग जिले में कोल माइनिंग परियोजनाओं के कारण विस्थापन लंबे समय से बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पिछले लोकसभा व विधानसभा चुनाव में भी यह मुद्दा उठा था, लेकिन ज्यादा तवज्जो नहीं पा सका। हाल में केरेडारी में -अतिक्रमण हटाओ और उचित मुआवजा दो- की मांग को लेकर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और जिला प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। अंबा प्रसाद भी विस्थापन के मुद्दे पर सरकार से सवाल उठा रही हैं। झारखंड में गठबंधन की सरकार होने के बावजूद पार्टी के इन दोनों नेताओं का अपनी ही सरकार पर भरोसा नहीं होना, बड़ी बात कही जा रही है। देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस का प्रदेश या राष्ट्रीय नेतृत्व इनके पक्ष में खड़ा होता है कि नहीं।

अब 21 नहीं, 11 तारीख को मनाया जाएगा परिवार कल्याण दिवस

DHANBAD : सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में अब हर महीने की 11 तारीख को परिवार कल्याण दिवस मनाया जाएगा, जबकि पहले 21 तारीख को मनाया जाता था। जिले के सरकारी अस्पताल सहित अन्य स्वास्थ्य केंद्रों और आयुष्मान आरोग्य मंदिर में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत परिवार नियोजन से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इस संबंध में सभी 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सिविल सर्जन डॉ. आलोक विश्वकर्मा ने बताया कि न केवल तिथि में बदलाव किया गया है, बल्कि कई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। यदि 11 तारीख को किसी तरह का अवकाश होगा, तो अगले दिन परिवार कल्याण दिवस मनेगा। धनबाद जिले की कुल जनसंख्या 32 लाख हो गई है। ऐसे में परिवार नियोजन को लेकर विभाग की ओर से यहां अभियान चलाया जा रहा है। परिवार कल्याण दिवस के तहत जिले के विशेष क्षेत्र चिह्नित किए जा रहे हैं। इसमें अधिक प्रजनन वाले क्षेत्र, दो बच्चों में कम अंतर नहीं होने वाले क्षेत्र, किशोरावस्था में गर्भधारण करने वाले क्षेत्र और कम गर्भधारण करने वाले क्षेत्र की पहचान की जाएगी। इसके बाद यहां विशेष अभियान और कैंप आयोजित किए जाएंगे।

कोडरमा में महिला से दुष्कर्म बच्चे को मारने की दी धमकी

KODERMA : डोमचांच थाना क्षेत्र में एक पोकलेन मालिक ने अपने ही चालक की पत्नी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। डोमचांच थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसके पति पोकलेन मशीन चलाते हैं। जब उसके पति किसी काम से बरकट्ठा गए थे। वह अपने बच्चों के साथ घर पर सो रही थी, तभी पोकलेन का मालिक नंदलाल पंडित घर में घुसा और चाकू का डर दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने कहा कि किसी को बताया तो बच्चे को जान से मार दूंगा। उस वक्त उसकी सास और ननद आलू के खेत में काम करने गई थी, लेकिन जब आरोपी घर से निकल रहा था, इसी बीच दोनों आ गईं। उन्हें देखकर मैंने पकड़ो-पकड़ो का शोर मचाया। मेरी सास और ननद ने आरोपी को पकड़ने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह किसी तरह पैदल भाग गया। हड़बड़ी में आरोपी ने अपनी बाइक मेरे घर के पास ही छोड़ दिया था। डोमचांच के थाना प्रभारी अभिमन्यु कुमार ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी।

BRIEF NEWS

सम्मानित किए जाएंगे हिंदी और भोजपुरी के साहित्यकार

RANCHI : हिंदी साहित्य संकल्प संधान पीठ की ओर से हिंदी, भोजपुरी व नागपुरी के एक-एक साहित्यकार को सम्मानित किया जाएगा। संस्था के अध्यक्ष हरेराम त्रिपाठी चेतन ने बताया कि लोकपूज्य रामछविला त्रिपाठी वाग्देवी सम्मान-2026 रांची की साहित्यकार वीणा श्रीवास्तव, मां राजमणि स्यमंतकमणि सम्मान-2026 नागपुरी में साहित्यिक अवदान के लिए रांची की शकुंतला मिश्रा और शहीद श्रीराम तिवारी कौस्तुभमणि सम्मान-2026 भोजपुरी साहित्य में महत्वपूर्ण अवदान के लिए आरा (बिहार) के जितेंद्र कुमार को प्रदान किया जाएगा। यह सम्मान समारोह न्यू मोराबादी स्थित स्वाध्याय परिसर में मार्च में आयोजित किया जाएगा।

250 जरूरतमंदों में किया गया कंबल वितरण

PITHORIYA : रविवार को श्री कृष्ण धामी सदानंद प्रणाली ट्रस्ट द्वारा कांके प्रखंड के ग्राम हेठ कोनकी किसान चौक के समीप 250 जरूरतमंद लोगो के बीच कंबल का वितरण किया गया। मौके पर मौजूद पूर्व जिप सदस्य सह इचापीड़ी पंचायत समिति सदस्य ऐनुल हक अंसारी ने बताया कि रांची जिले के सबसे ठंडा इलाका कांके का होता है। बहुत से गरीब लोगों के पास ठंड से बचने के लिए उनके पास पर्याप्त गर्म कपड़े नहीं हैं। ऐसे में हर वर्ष कि भांति इस वर्ष भी श्री कृष्ण धामी सदानंद प्रणाली ट्रस्ट के द्वारा कंबल का वितरण किया गया है। मौके पर मुख्य रूप से ट्रस्ट के विजय कुमार अग्रवाल, समीर अंसारी, गणेश प्रसाद साहू, अशोक सिंह, चंद्रदीप साहू, मुखिया लाला महली, सदर मतिउर रहमान, मौलाना अनीसुर रहमान, लेयाकत हुसैन, शौकत अंसारी, मो खालिद सैफुल्लाह, हसीब अंसारी, राजेश कुमार साहू, तौफीक अंसारी और अनेक गणमान्य समाजसेवी बुद्धिजीवी उपस्थित थे।

मकर संक्रांति पर किया जाएगा मेला का आयोजन

KANKE : पिठोरिया थाना क्षेत्र के मालश्रृंग गांव में रविवार को ग्रामीणों की बैठक ग्राम प्रधान अकलू पाहन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मकर संक्रांति के अवसर पर 14 जनवरी को मोहे पहाड़ में टुसू मेला सह सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम की सफलता को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया। अध्यक्ष अजित कुमार कश्यप, सचिव देवीचरण महतो व कोषाध्यक्ष कृष्णा कुमार बनाए गए। कमेटी में संरक्षक जनक कुमार गुप्ता, किशोर राम,भानु कुमार,बनु कश्यप चुने गए। मौके पर गांव के दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे।

मुख्यमंत्री से मिलीं फुटबॉलर अनुष्का, रुक्का में बनेगा खेल का मैदान

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड की उभरती हुई अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित अनुष्का कुमारी ने रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने अनुष्का को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना की और उज्ज्वल भविष्य के लिए हौसलाअफजाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नया वर्ष आपके लिए उपलब्धियों से भरा हो और आप अपने खेल से देश-दुनिया में झारखंड की अलग पहचान बनाएं। मुख्यमंत्री ने अनुष्का को सम्मानित करते हुए स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की। अनुष्का ने खेल अनुभव और संघर्ष की कहानी मुख्यमंत्री के साथ साझा की। मुख्यमंत्री ने रुक्का में खेल का मैदान बनने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार खिलाड़ियों को बेहतर मंच, संसाधन और अवसर उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठा रही है, ताकि कि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी भी खिलाड़ी की प्रतिभा दबनी नहीं चाहिए।

- हेमंत सोरेन ने खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए प्रदान की स्पोर्ट्स किट
- खिलाड़ियों को बेहतर मंच व अवसर उपलब्ध कराने को ठोस कदम उठा रही सरकार
- आर्थिक कठिनाइयों के कारण दबनी नहीं चाहिए किसी भी खिलाड़ी की प्रतिभा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करतीं अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलर अनुष्का कुमारी

परिवार को कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ें

मुख्यमंत्री ने रांची जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि अनुष्का कुमारी के गांव रुक्का में एक खेल मैदान विकसित किया जाए। साथ ही उनके परिजनों को राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के परिवारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है।

फुटबॉल की दुनिया में बनाई पहचान

गौरतलब है कि अनुष्का कुमारी ने गरीबी और कठिन परिस्थितियों के बीच संघर्ष करते हुए फुटबॉल की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। उनके पिता दिलेश मुंडा दिव्यांग हैं, जबकि माता दिहाड़ी मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करती हैं। दो भाइयों में एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है और दूसरा पढ़ाई कर रहा है। आज वह 'द गोल मशीन' के नाम से जानी जाती हैं।

राष्ट्रपति ने किया था सम्मानित

अनुष्का को 26 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय वीर बाल दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने उन्हें फुटबॉल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। सितंबर 2024 में भूटान में आयोजित सैफ अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता में उन्होंने सर्वाधिक सात गोल कर 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' का खिताब जीता था। इसके अलावा वह नेपाल में हुई अंडर-16 सैफ चैंपियनशिप की उपविजेता भारतीय टीम की भी सदस्य रह चुकी हैं। आगामी मार्च में वह चीन में होने वाली एशियाई अंडर-17 फुटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। वर्तमान में अनुष्का हजारीबाग स्थित आवासीय बालिका फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण ले रही हैं। साथ ही इस वर्ष दसवीं की परीक्षा में शामिल होंगी।

निगम प्रशासक ने निरीक्षण के बाद संबंधित अधिकारियों को दिया आदेश

अब पहाड़ी मंदिर के पास से हटेगा अतिक्रमण, कराई जाएगी मापी

PHOTON NEWS RANCHI : रांची नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थित शहर के प्रमुख धार्मिक स्थल पहाड़ी मंदिर और उसके आसपास से अतिक्रमण हटाने को लेकर रेस हो गया है। जल्द ही पहाड़ी के 27 एकड़ एरिया की मापी करने का आदेश नगर आयुक्त ने दिया है। हाईकोर्ट की फटकार के बाद रविवार को उन्होंने पहाड़ी व आसपास का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने टीम को पहाड़ी एरिया को अवैध कब्जे से मुक्त कराने का आदेश दिया। इतना ही नहीं अवैध रूप से कब्जा करने वालों पर बुलडोजर भी चलेगा। प्रशासक सुशांत गौरव ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जा रहा है। लगभग 27 एकड़ क्षेत्र में फैले इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में क्षेत्र की व्यवस्था को बेहतर बनाना निगम की प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान मंदिर के मुख्य द्वार के दोनों ओर फैले अतिक्रमण और अव्यवस्थित रूप से खड़े वाहनों को गंभीरता से लेते हुए प्रशासक ने संबंधित पदाधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने पूरे क्षेत्र की मापी कराने तथा मंदिर परिसर के बाहर आवंटित दुकानों के अलावा अस्थायी रूप से लगने वाली दुकानों की स्थिति का जायजा लेने को कहा। साथ ही पूजन सामग्री को निर्धारित सीमा से बाहर सड़क तक फैलाकर रखने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि मंदिर के मुख्य द्वार के आसपास सुबह से ही ट्रक और मालवाहक वाहन खड़े रहते हैं, जिससे श्रद्धालुओं और आम नागरिकों के आवागमन में भारी परेशानी होती है। गोदामों की मौजूदगी से उत्पन्न इस समस्या पर संज्ञान लेते हुए प्रशासक ने संबंधित वाहनों पर जुर्माना लगाने, गोदामों और अवैध दुकानों की जांच करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

- 27 एकड़ में फैला है पहाड़ी मंदिर का एरिया

पहाड़ी मंदिर और उसके आसपास के अतिक्रमण का निरीक्षण करते प्रशासक सुशांत गौरव व अन्य

युद्धस्तर पर सफाई जारी

रविवार को भी हरमू नदी में युद्ध स्तर पर सफाई जारी रहा। निगम के 100 से अधिक सफाई मित्रों द्वारा लगातार सफाई कार्य किया गया। आधुनिक मशीनों और कर्मियों की मदद से नदी में वर्षों से जमे ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक, गाद और अन्य कचरे को हटाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य न केवल नदी की स्वच्छता सुनिश्चित करना है, बल्कि उसके प्राकृतिक प्रवाह को पुनः स्थापित करना है। नगर निगम ने शहर के सभी नागरिकों से अपील की है कि हरमू नदी में किसी भी प्रकार का कचरा, गंदा पानी या अपशिष्ट न डालें।

बनाई जाएंगी दो पार्किंग

श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रशासक ने दो अलग-अलग पार्किंग स्थलों के निर्धारण का भी निर्देश दिया। जिससे वाहन केवल निर्धारित स्थानों पर ही खड़े होंगे और मंदिर क्षेत्र को जाम मुक्त रखा जा सकेगा। प्रशासक ने कहा कि पहाड़ी मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए रांची नगर निगम पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

आईटीआई बस स्टैंड का भी किया मुआयना

वार्ड 33 स्थित आईटीआई बस स्टैंड लगभग 4 एकड़ 22 डिसमिल में फैला हुआ है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं, सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने तथा क्षेत्र के वेंडर्स को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रशासक ने आईटीआई बस स्टैंड परिसर का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, अतिक्रमण की स्थिति, शौचालयों की साफ-सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं का अवलोकन किया गया। जुडको के पदाधिकारियों द्वारा बस स्टैंड के प्रस्तावित नए स्वरूप की विस्तृत जानकारी प्रशासक महोदय को दी गई। इस दौरान प्रशासक ने निर्देश दिया कि यात्रियों के सुचारु आवागमन, सुव्यवस्थित प्रतीक्षालय, पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था और सुलभ व स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।

ममता हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा

अवैध संबंध बनी मौत की वजह पति को किया गया गिरफ्तार

PHOTON NEWS RANCHI : राजधानी के अनगड़ा में हुए ममता हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। ममता का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका ही पति निकला। ममता को उसके पति दिनेश्वर करमाली ने ही मार डाला था। दिनेश्वर को शक था कि उसकी पत्नी का उसके ही भांजे के साथ अवैध संबंध है। जिसके बाद इस जघन्य घटना को अंजाम दिया। एक दिसंबर 2025 को करीब दोपहर तीन बजे रांची के अनगड़ा थाना को सूचना मिली की एक घर में पति और पत्नी का गला रेत दिया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। जांच के क्रम में ममता कुमारी मृत पाई गई। लेकिन ममता का पति दिनेश्वर जिंदा था। पुलिस ने आनन फानन में उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घायल अवस्था में ही दिनेश्वर ने पुलिस को बयान दिया की उसकी पत्नी की हत्या करने वाला और उसे घायल करने वाला कोई और नहीं उसका ही भांजा है। खून से लथपथ दिनेश्वर की बात पर उस समय पुलिस ने विश्वास भी कर लिया और संदेह के आधार पर सुदामा करमाली को हिरासत में ले लिया था। लेकिन पुलिस की जांच में कहानी कुछ और ही निकली। रांची के ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर ने बताया कि अवैध संबंध के शक में ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। एसपी ने बताया कि पत्नी की हत्या करने के बाद दिनेश्वर करमाली ने अपने गले का चमड़ा काट लिया था। जिससे पुलिस को लगे कि उस पर भी हमला किया गया है। दरअसल करमाली को शक था कि उसके घर में रहने वाले उसके भांजे के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है।

आरोपी ने स्वीकार किया अपना अपराध

ग्रामीण एसपी ने बताया कि भाजे के साथ अवैध संबंध को लेकर दोनों में अक्सर मारपीट होती थी। इसी क्रम में दिनेश्वर ने एक ऐसी साजिश रची जिसमें उसका भांजा भी फंस जाए और उसकी पत्नी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। दिनेश्वर ने अपने भांजे को फंसाने और पत्नी की हत्या की प्लानिंग बहुत बेहतर की थी। लेकिन कानून के हाथ से वह नहीं बच पाया। पुलिस पूछताछ में रांची के अनगड़ा थाना अंतर्गत हेसल टोल प्लाजा के रहने वाले 42 वर्षीय मुख्य अभियुक्त दिनेश्वर करमाली उर्फ लालू ने अपना अपराध स्वीकार किया। दिनेश्वर ने बयान में बताया कि उसकी पत्नी ममता कुमारी का उसके भांजा सुदामा करमाली के साथ अवैध संबंध था। जिसे लेकर वह पत्नी को बार-बार समझाता था कि सुदामा से मेलजोल बंद कर दे। लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। 1 दिसंबर 2025 को इसी बात को लेकर दोनों में बहस हुई और गुस्से में आरोपी ने सब्जी काटने वाले हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक रांची और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रांची के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस उपाधीक्षक सिल्ली के नेतृत्व में तकनीकी शाखा रांची और गुप्तचरों की मदद से त्वरित कार्रवाई करते हुए दिनेश्वर करमाली उर्फ लालू को विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से सब्जी काटने वाला एक हथियार बरामद किया। जिसका उपयोग हत्या में किया गया था।

बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के विरोध में निकाली गई तिरंगा यात्रा

PHOTON NEWS NAMKUM : बांग्लादेश मे दीपू चंद्र दास, खोखन चंद्र दास सहित अन्य हिंदुओं की निर्मम हत्या के विरोध मे रविवार को अखिल भारतीय

ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन के प्रदेश प्रमुख और राज्यसभा सांसद प्रतिनिधि मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व मे नामकुम बाजार महाराणा प्रताप चैक से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद रांची के जिलाध्यक्ष नारायण प्रसाद सहित कई भूतपूर्व सैनिक भी शामिल हुए। महाराणा प्रताप चैक होते हुए सदाबहार चैक होते हुए वापस नामकुम बाजार मैदान तक पहुंचे और क जनसभा का आयोजन किया गया। मनोज कुमार सिंह ने बांग्लादेश की सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर करवाई की मांग की, साथ ही केंद्र सरकार से इस पर कठोर कदम उठाकर सुरक्षा के लिए कार्रवाई की मांग की। नारायण प्रसाद ने भारत सरकार से इस पर हस्तक्षेप की मांग की। मौके पर सूबेदार नारायण प्रसाद, संदीप सिंह, रूपा चैहान, सूबेदार मनोज राय, सूबेदार धनेश चंद्र वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे।

हहाप पंचायत में हुई खेलकूद प्रतियोगिता

PHOTON NEWS NAMKUM : हहाप पंचायत के जामुन टोली में ग्रामसभा की ओर से प्रत्येक वर्ष की भांति नए वर्ष के अवसर पर सामूहिक पिकनिक सह खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन किया गया। इस दौरान 100 मीटर बालक-बालिका दौड़, छोटे बच्चों की चम्मच रेस, घड़ा फोड़ महिलाओं की कुर्सी रेस व पुरुषो के लिए रस्साकसी, बोरा दौड़ फुटबॉल खेल व अन्य खेल का आयोजन किया गया। मौके पर आदिवासी मूलवासी संघर्ष समिति की ओर से सभी विजेताओं को पुरस्कार व जरूरमंदों में कपड़ा व कंबल का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से हहाप मुखिया नन्हे कच्छप वा वार्ड सदस्य विनोद कच्छप वा मादी टोप्पो का भूमिका रही। नन्हे कच्छप ने कहा कि इस तरह के खेल आयोजन से बच्चों में साहस, रुचि वा कोई कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डर दूर होना साथ ही बच्चों में आत्मविश्वास वा प्रोत्साहन बढ़ने के लिए किया जाता है।

पेसा नियमावली को लेकर हेमंत सरकार पर बरसे अर्जुन मुंडा, बोले-

एक्ट की आत्मा के साथ की गई छेड़छाड़ आदिवासी समाज को दिया गया धोखा

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार द्वारा अधिसूचित पेसा (पंचायत विस्तार अनुसूचित क्षेत्र) नियमावली को लेकर सियासत गरमा गई है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने पेसा एक्ट 1996 की मूल भावना और आत्मा को ही बदल दिया है। उन्होंने कहा कि पेसा नियमावली की मांग लंबे समय से हो रही थी और इसके लिए कई लोग अदालत भी गए थे। सरकार को बाध्य होकर कैबिनेट से नियमावली पारित करनी पड़ी,

लेकिन जो नियमावली सामने आई है, वह न तो दुरुस्त है और न ही एक्ट की भावना के अनुरूप। उन्होंने कहा कि यह एक तरह से पेसा एक्ट का कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और जनजाति समाज के साथ धोखाधड़ी के समान है। प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री व सांसद डॉ. प्रदीप वर्मा, मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक, सह मीडिया प्रभारी अशोक बड़ाइक और प्रवक्ता राफिया नाज भी मौजूद रहीं।

भाजपा फैला रही भ्रम : विनोद पांडेय

RANCHI : झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)के महासचिव विनोद पांडेय ने पेसा नियमावली को लेकर भाजपा और पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि पेसा नियमावली में ग्रामसभा सर्वोच्च है और आगे भी सर्वोच्च रहेगी। भाजपा के आरोप निराधार, भ्रामक और राजनीतिक हताशा से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को आज आदिवासी हितों की चिंता दिख रही है, जबकि उसके लंबे शासनकाल में पेसा कानून को लागू करने की नीयत तक नहीं थी। उन्होंने कहा कि अर्जुन मुंडा स्वयं कई वर्षों तक झारखंड के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार में मंत्री रहे।

जमीन विवाद में महिला पर जानलेवा हमला

RANCHI : जमीन विवाद को लेकर नामकुम थाना क्षेत्र के लावाडीह गांव में एक महिला पर ईंट से जानलेवा हमला किया गया। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद रूरल एसपी ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला नामकुम थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली प्रियंका कुजूर नाम की महिला अपने पुश्तैनी जमीन पर निर्माण कार्य कर रही थी। इसी दौरान रवि कुजूर ने महिला पर ईंट से हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल महिला प्रियंका कुजूर का इलाज रांची के सदर अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार, महिला के चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों ने बताया कि प्रियंका अपनी पुश्तैनी जमीन पर मकान का निर्माण करा रही थी। जहां पिछले लगभग 40 वर्षों से बाउंड्री वॉल और मकान मौजूद है। इसके बावजूद आरोपी ने जमीन पर अपना दावा ठोकते हुए हमला कर दिया। प्रियंका की बहन ने बताया कि अब तक इस जमीन को लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ था।

निगम की सख्ती ट्रेड लाइसेंस भी होगा कैंसिल, निगम की दुकानों का आवंटन भी कर दिया जाएगा रद्द

सिंगल यूज प्लास्टिक मिलने पर सील की जाएगी दुकान

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड की राजधानी रांची में सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ नगर निगम सख्त हो गया है। रांची नगर निगम ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी दुकान, प्रतिष्ठान या निगम द्वारा आवंटित दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक पाया गया तो उस दुकान को तत्काल सील कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं संबंधित दुकानदार का ट्रेड लाइसेंस भी रद्द किया जाएगा। इसके अलावा निगम की दुकान का आवंटन भी रद्द कर दिया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार, झारखंड राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रोडक्शन, भंडारण, खरीद-बिक्री और उपयोग पर पहले से ही पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में इसका खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पर्यावरण और आमजन के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसी को देखते हुए नगर निगम ने अब सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। वहीं निर्माण करने वाली फैक्ट्री की भी तलाश की जा रही है। अपर प्रशासक बताया कि नगर निगम ने म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश जारी किया है। इसके तहत निगम की एनफोर्समेंट टीम शहर भर में अभियान चलाकर दुकानों, होटल, रेस्टोरेंट, ठेला-खोमचा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच करेगी। जांच के दौरान यदि सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक कैरी बैग, कप, प्लेट, स्ट्रॉ या अन्य प्रतिबंधित सामग्री पाई जाती है तो बिना किसी चेतावनी के कार्रवाई की जाएगी।

- सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, खरीद-बिक्री पर है झारखंड में रोक
- म्युनिसिपल एक्ट के तहत कार्रवाई का दिया गया है आदेश
- नगर निगम की ओर से आवंटित दुकानों में भी टीम को जांच का मिला निर्देश

कपड़े, जूट या कागज से बने विकल्प का करें उपयोग

खास बात यह है कि यह कार्रवाई सिर्फ निजी दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी। नगर निगम द्वारा आवंटित दुकानों में भी सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं। यदि निगम की दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग या भंडारण पाया गया तो संबंधित आवंटी के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई होगी और दुकान का आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। नगर निगम के अधिकारियों ने दुकानदारों से अपील की है कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का पूरी तरह बहिष्कार करें और इसके स्थान पर कपड़े, जूट या कागज से बने पर्यावरण अनुकूल विकल्पों का उपयोग करें।

ऑल इंडिया जजेज बैडमिंटन चैंपियनशिप में न्यायाधीशों ने किया शानदार प्रदर्शन

PHOTON NEWS RANCHI : झारखंड हाईकोर्ट के तत्वावधान में आयोजित सेकेंड ऑल इंडिया जजेज बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का रविवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता 3 से 4 जनवरी तक रांची के खेलगांव परिसर स्थित ठाकुर विश्वनाथ शहदेव इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई। प्रतियोगिता में देश के 9 उच्च न्यायालयों से आए 31 न्यायाधीशों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के दौरान मेन सिंगल्स, वीमेन सिंगल्स, मेन डबल्स और मिक्स्ड डबल्स कुल चार वर्गों में मुकाबले खेले गए। इनमें प्रतिभागियों ने उच्च स्तरीय खेल भावना, अनुशासन और उत्कृष्ट खेल कौशल का परिचय दिया। शानदार प्रदर्शन किया। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया। अतिथियों ने सभी प्रतिभागियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।

- देश के 9 उच्च न्यायालयों के 31 जजों ने प्रतियोगिता में लिया भाग
- झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने विजयी प्रतिभागियों को किया सम्मानित

मेन सिंगल्स

विजेता : जस्टिस फरहान परवेज दुबास (बॉम्बे हाईकोर्ट)
उपविजेता : जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस (केरल हाईकोर्ट)
तृतीय स्थान : जस्टिस तेज प्रताप तिवारी (इलाहाबाद हाईकोर्ट)

वीमेन सिंगल्स

विजेता : जस्टिस सावित्री राठो (उड़ीसा हाईकोर्ट)
उपविजेता : जस्टिस रेखा बोराना (राजस्थान हाईकोर्ट)
तृतीय स्थान : जस्टिस नूपुर भाटी (राजस्थान हाईकोर्ट)

समाचार सार

हो समाज का उपरुम-जुमूर 11 को

CHAIBASA : आदिवासी हो समाज युवा महासभा 11 जनवरी को मनाएगा, जबकि 17-18 जनवरी को किरीबुरू में महासभा का वार्षिक अधिवेशन होगा। इसे लेकर रविवार को जगन्नाथपुर अनुमंडल कार्यालय परिसर में बैठक हुई। इसमें महासभा की केंद्रीय कमेटी के महासचिव सोमा कोड़ा ने अधिवेशन के लिए महासभा के पदाधिकारियों को निर्देश दिया। दिउरी, मुंडा-मानकी, सामाजिक कार्यकर्ता व बुद्धिजीवियों को आमंत्रित करने की जिम्मेदारी सौंपी। उपरूम-जुमूर में पारंपरिक परिधान में भाग लेने का अनुरोध किया गया। बैठक में महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इपिल सामड, महासचिव गब्बर सिंह हेम्ब्रम, प्रदेश सांस्कृतिक सचिव जगन्नाथ हेस्सा, जिलाध्यक्ष शेर सिंह बिरूवा, जगन्नाथपुर अनुमंडल अध्यक्ष बलराम लागुरी, उपाध्यक्ष पुतकर लागुरी, जयप्रकाश हेम्ब्रम आदि भी उपास्थित थे।

माघे पर्व 4 फरवरी को मनाने का निर्णय

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड अंतर्गत बड़ानन्दा पंचायत के साननंदा में ग्राम दिऊरी नाजिर लागुरी की अध्यक्षता में माघे पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। रविवार को हुई ग्रामसभा की बैठक में आपसी सहमति से 4 फरवरी को माघे पर्व मनाने का निर्णय लिया गया। बैठक में अध्यक्ष राजाराम लागुरी, सचिव मंगल सिंह लागुरी, कोषाध्यक्ष कैरा कायम, लक्ष्मीनारायण लागुरी, बंसत कुमार लागुरी, राजू लागुरी, शिवशंकर लागुरी आदि भी उपस्थित थे।

याद की गईं सावित्रीबाई फुले

JAMSHEDPUR : सावित्रीबाई फुले सेवा दल, जमशेदपुर ने रविवार को कदमा स्थित केएफ-1 क्लब हाउस, जीपी स्लोप में देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 195वीं जयंती मनाई। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि समाजसेवी पूरबी घोष, कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सोनकर, झामुमो नेता लालटू महतो, निर्मल सेवासदन के महासचिव गौतम बोस, माली मालाकार कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष चंदेश्वर भगत आदि ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विभा कुमारी (केपीएस बर्मा माइंस), सोनी प्रभाकर (किताडीह), कविता कुमारी (भालूबासा) आदि शिक्षिकाओं के अलावा कोल्हान विश्वविद्यालय की गोल्ड मेडलिस्ट स्वीटी सैनी को सम्मानित किया गया। उधर, कालिंदी कल्याण समिति ने भी टुइलाडुंगरी में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई।

रघुवर ने नचाया लट्टू, बैडमिंटन व क्रिकेट भी खेला

JAMSHEDPUR : जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा के भाजपा कार्यकर्ताओं ने रविवार को डिमना लेक के पास वार्षिक मिलन समारोह-सह- वनभोज का आयोजन किया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने हिस्सा लिया। यहां रघुवर दास ने कार्यकर्ताओं के साथ क्रिकेट व बैडमिंटन खेता, तो लट्टू भी नचाया। इस दौरान गीतों की मनमोहक प्रस्तुति एवं संगीत पर विधायक पूर्णिमा साहू एवं कार्यकर्ता थिरकते दिखे। आयोजन के लिए रघुवर दास ने वरिष्ठ नेता पवन अग्रवाल, सुशांत पांडा एवं टुनटुन सिंह को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर रघुवर दास ने कहा कि भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं, एक परिवार है। यहां प्रत्येक कार्यकर्ता परिवार के सदस्य की भांति एक-दूसरे से आत्मीय रूप से जुड़े हुए हैं। वनभोज जैसे आयोजनों से संगठनात्मक ऊर्जा मिलती है और कार्यकताओं से सीधे संवाद का अवसर मिलता है। यह अनुभव सुकून देता है। उन्होंने नववर्ष पर शहरवासियों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के सुख, समृद्धि, उन्नति और खुशहाली की शुभकामनाएं व्यक्त की। वहीं, विधायक पूर्णिमा साहू ने कहा कि कार्यकर्ता हमारे संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं। उनका उत्साह, अनुशासन और समर्पण ही भाजपा को मजबूती देता है।

साइकिल सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत

CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में शनिवार शाम तेज रफ्तार पिकअप वैन ने दो साइकिल सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें 60 वर्षीय केदार केराई की इलाज के दौरान रविवार को सदर अस्पताल चाईबासा में मौत हो गई। जबकि, 50 वर्षीय परशुराम केराई इलाजरत है। यह हादसा तब हुआ, जब दोनों अलग-अलग साइकिल से कराईकेला स्थित गांव बाइहातु जा रहे थे। रास्ते में विपरीत दिशा से आ रही एक पिकअप वैन ने उन्हें धक्का मार दिया। इससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें घटनास्थल से चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए चाइबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था। घायल परशुराम केराई ने बताया कि वे दोनों अलग-अलग साइकिल से गांव लौट रहे थे। तभी पिकअप वैन ने उन्हें धक्का मार दिया। केदार केराई के परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी हैं। परशुराम केराई का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है।

दंतैल हाथी ने ली महिला की जान, पति और बेटा जख्मी

वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने को दिए पटाखे

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम में दंतैल हाथी ने एक और महिला की जान ले ली। गोइलकेरा के संतरा वन क्षेत्र के अमराई कितापी गांव के तोपनोसाई टोला में हाथी ने हमला कर 47 वर्षीय एक महिला की जान ले ली और उसके पति रंजन टोपनो और बेटा 10 वर्षीय काहिरा टोपनो को घायल कर दिया।

घटना रविवार सुबह की है, जब परिवार के लोग अपने घर के पास थे। बताया जाता है कि हाथी ने महिला को सूंड से उठाकर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला को बचाने के चक्कर में पति और बच्चा घायल हो गया। परिवार के अन्य लोग भी हाथी के हमले में बाल-बाल बच गए। घटना के बाद घायल पिता-पुत्र को चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए चाईबासा रेफर कर दिया गया।

हाथी के हमले में फसल का भी नुकसान हुआ है। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और उन्हें पटाखे दिए हैं ताकि वे हाथी को दूर रख सकें। वन क्षेत्र पदाधिकारी ने बताया कि हाथी के हमले की सूचना मिलते ही वनरक्षी और पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया। हाथी को भगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और ग्रामीणों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

घर में घायल पिता-पुत्र ● फोटोन न्यूज

पांच लोगों की चली गई जान, चार घायल

बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पिछले चार दिनों में इस हाथी ने पांच लोगों की जान ले ली है। जबकि, चार लोगों को घायल कर दिया है। उनकी स्थिति काफी नाजुक है। इसके पहले हाथी ने टोन्टो, मुफस्सिल और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में हमला कर चार लोगों की जान ली थी।

खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के पीछे बाइक सवार ने मारी टक्कर, युवक की मौत

GHATSILA : थाना क्षेत्र के पावड़ा गांव के समीप एनएच-18 फोरलेन के सर्विस रोड पर रविवार की दोपहर खड़ी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पीछे बुलेट सवार 25 वर्षीय युवक अरबाज अली ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान फूलपाल गांव निवासी नौसार अली के पुत्र के रूप में की गई। सूचना मिलते ही घाटशिला थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग करते हुए शव उठाने से मना कर दिया। पुलिस के काफी समझाने के बाद भी परिवार तथा गांव के लोग एक नहीं सुने। ग्रामीण उग्र होने लगे तो अंचलाधिकारी निशांत अंबर घटनास्थल पर पहुंचीं और परिजनों को समझाया। अंचलाधिकारी ने कहा कि सरकारी प्रावधान के अनुसार जो भी उचित मुआवजा होगा, मृतक के परिवार को दिया जाएगा। इसके साथ ही इंश्योरेंस क्लेम भी मिलेगा। वह भी परिवार को दिलाने का हरसंभव प्रयास प्रशासन करेगा। इसके बाद ग्रामीण माने, तो पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भेजा। बताया गया कि मृतक की शादी डेढ़ वर्ष पूर्व दोलकी गांव में हुई थी। वह पत्नी को लाने जा रहा था। सर्विस रोड पर काफी मात्रा में मोबिल गिरा हुआ था, जिससे ब्रेक मारते ही बुलेट स्किट कर ट्रैक्टर के पीछे जोर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मृतक बुलेट सहित ट्रॉली के पीछे घुस गया था। इससे उसका सिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

टेल्को में चापड़ से एक युवक की हत्या, दूसरा गंभीर रूप से घायल

JAMSHEDPUR : टेल्को थाना क्षेत्र में रविवार को अज्ञात अपराधियों ने चापड़ से हमला कर मोहम्मद सोहेल नामक युवक की हत्या कर दी। वहीं, हमले में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक मोहम्मद सोहेल जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत खजांची मोहल्ला का निवासी था। बताया जाता है कि अपराधियों ने अचानक चापड़ से हमला कर दिया था, जिसमें मोहम्मद सोहेल गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस घटना में बाबू फ्लैट के समीप रहने वाला एक अन्य युवक हमले का शिकार हुआ है। डॉक्टरों के अनुसार घायल की स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए एमजीएम अस्पमाल भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से कई साक्ष्य बरामद किए हैं। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी पुलिस खंगाल रही है। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश या पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है। वैसे पुलिस सभी बिंदुओं पर गहन जांच कर रही है।

दुष्कर्म व हत्या मामले में युवक गिरफ्तार युवती की स्कूटी व मोबाइल हुई बरामद

PHOTON NEWS CHAIBASA : पश्चिमी सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा में 25 वर्षीय कुंती पिंगुवा की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगीदारु गांव स्थित तोडांग टोला से गिरफ्तार युवक प्रधान पुरती उर्फ पल्टू है। वह तोडांग टोला का ही रहने वाला है। पुलिस के अनुसार पल्टू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अभियुक्त ने बताया कि उसने कुंती पिंगुवा के साथ शारीरिक संबंध बनाए, फिर गला दबाकर और पत्थर से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने मृतका का मोबाइल फोन और लाल रंग की स्कूटी भी बरामद कर ली है। उसका शव 29 दिसंबर 2025 को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ग्राम जोगीदारा जंगल के समीप एक खेत में पुआल से ढंका हुआ मिला था। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को जानकारी के अनुसार, बड़ाजामदा निवासी 25 वर्षीय कुंती पिंगुवा की दुष्कर्म के बाद हत्या कर देने के बाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बड़ा लगिया गांव निवासी जयकिशन होनहागा के खेत में फेंक दिया था। घटना के बाद 30 दिसंबर को होनहागा ने ही पुलिस को शव मिलने की सूचना दी थी। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। युवती की हत्या मामले में पुलिस अधीक्षक अमित रेनू ने एक विशेष टीम का गठन किया था। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। छापामारी टीम में चाईबासा सदर एसडीपीओ बहामन टुटी, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनोद कुमार, मिथुन कुमार, अरविंद कुमार शर्मा, नागेंद्र सहित पुलिस के रिजर्व गार्ड शामिल थे।

पत्रकारों को जानकारी देते एसडीपीओ बहामन टुटी ● फोटोन न्यूज

ठंड के कारण आज-कल बंद रहेंगे सभी स्कूल

JAMSHEDPUR : बढ़ते ठंड को देखते हुए पूर्वी सिंहभूम जिले के सभी स्कूल बंद रहेंगे। उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी द्वारा रविवार को जारी आदेश में कहा गया है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त मौसम पूवार्नुमान के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक ठंड एवं शीतलहर के कारण तापमान न्यूनतम होने की संभावना है। इसे देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सभी सरकारी, अल्पसंख्यक व निजी विद्यालयों में वर्ग नर्सरी से 12वीं तक की कक्षाओं में पठन-पाठन का कार्य 05 से 06 जनवरी तक स्थगित किया गया है। सभी विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि वे इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

यदि उक्त अवधि में किसी विद्यालय में परीक्षा आयोजित है, तो अपने विवेकानुसार विद्यालय में परीक्षा का संचालन करेंगे। 6 जनवरी को सरकारी विद्यालय शिक्षकों के लिए खुले रहेंगे, जिसमें शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी विद्यालय में उपस्थित होकर अपनी इलेक्ट्रानिक सिस्टम से हाजिरी दर्ज करेंगे एवं विद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्यों का निष्पादन करेंगे।

जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट में शामिल हुए 1 हजार छात्र

परीक्षा केंद्र में जुटे परीक्षार्थी ● फोटोन न्यूज

JAMSHEDPUR : जेवियर एप्टीट्यूड टेस्ट (जैट-2026) की परीक्षा रविवार को जमशेदपुर, रांची समेत देश के 100 से अधिक शहरों में हुई। दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक हुई ऑनलाइन परीक्षा में इस वर्ष जैट के लिए रिकॉर्ड 1,45,235 विद्यार्थियों ने आवेदन किया था, जिनमें से करीब 1.27 लाख ने परीक्षा दी। परीक्षा के बाद छात्रों की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई। जमशेदपुर के मानगो में एनएच-33 स्थित आयन डिजिटल परीक्षा केंद्र में कुल 1,024 छात्र-छात्राओं ने परीक्षा दी, जबकि 125 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। यहां बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से एक्सएलआरआई जमशेदपुर सहित देश के करीब 250 बिजनेस स्कूलों में दाखिला लिया जाता है। परीक्षा का परिणाम इस माह के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। जैट के इतिहास में यह अब तक की सबसे अधिक परीक्षार्थियों वाली परीक्षा रही। पिछले वर्ष लगभग एक लाख छात्रों ने इसमें भाग लिया था।

महिला शिक्षिका से पर्स की छिनतई, अपराधी फरार

JAMSHEDPUR : साकची थाना क्षेत्र के शीतला मंदिर के समीप रविवार को अपराधियों ने ऑटो से यात्रा कर रही एक महिला शिक्षिका से बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने पर्स छीन लिया और मौके से फरार हो गए। पीड़िता की पहचान साकची निवासी शिक्षिका हेमलता ठाकुर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मानगो निवासी हेमलता ठाकुर अपने बच्चे और सहेली के साथ साकची बाजार में शादी से संबंधित खरीदारी करने आई थीं। बाजार से लौटते समय वह एक सवारी ऑटो में बैठी थीं। जैसे ही ऑटो शीतला मंदिर के पास पहुंचा, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आई बाइक पर सवार दो युवक ऑटो पास पहुंचे और अचानक हेमलता ठाकुर के हाथ से पर्स झपटकर फरार हो गए। घटना इतनी तेजी से हुई कि ऑटो में सवार अन्य लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपित बाइक सहित भीड़ में ओझल हो गए। पीड़ित शिक्षिका ने बताया कि छीने गए पर्स में करीब 20 हजार रुपये नकद, एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड सहित कुछ जरूरी कागजात थे। घटना के बाद वह काफी घबरा गईं और आसपास के लोगों की मदद से साकची थाना पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई।

साकची थाना में पीड़िता

रेडक्रॉस ने किया 26 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन

JAMSHEDPUR : रेडक्रॉस के पैट्रन व समाजसेवी केके सिंह की स्मृति में आयोजित नेत्र ज्योति महायज्ञ के दूसरे दिन रविवार को 26 नेत्र रोगियों का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन सत्र का उद्घाटन स्व. केके सिंह की पत्नी व केके एजुकेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी उर्मिला सिंह, उनकी पुत्री उषा सिंह के साथ आश्विन आडेसरा, नेत्र चिकित्सक डॉ. बीपी सिंह, समाजसेवी चंद्रमोहन सिंह व राकेश मिश्र ने संयुक्त रूप से किया।

नेत्र चिकित्सक डॉ. बीपी सिंह, डॉ. भारती शर्मा, डॉ. पूनम सिंह, डॉ. मलय द्विवेदी, डॉ. विवेक केडिया, डॉ. आनंद सुश्रुत, डॉ. विनायक एवं उनकी सहयोगी चिकित्सीय टीम ने ऑपरेशन व लेंस प्रत्यारोपण किया। शिविर में 160 नेत्र रोगी ऑपरेशन के योग्य पाए गए हैं, शेष का ऑपरेशन 10 व 17 जनवरी को किया जाएगा।

गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर निकला नगर कीर्तन, जमकर हुई आतिशबाजी

PHOTON NEWS JSR : गुरु गोविंदसिंह की जयंती पर रविवार को धूमधाम से नगर कीर्तन निकाला गया। इस मौके पर सिख समुदाय के लोग पूरे उत्साह के सथ इस नगर कीर्तन में शामिल हुए। गोलमुरी के रिफ्यूजी कालोनी से निकला नगर कीर्तन टिनप्लेट होते हुए साकची गुरुद्वारा आकर संपन्न हुआ। साकची गुरुद्वारा के सामने जमकर आतिशबाजी हुई।

बताया जा रहा है कि गुरुगोविंद सिंह की जयंती 27 सितंबर को थी। मगर, किसी कारणवश यहां प्रकाश पर्व का आयोजन अब किया गया।

प्रकाश पर्व को लेकर निकला यह नगर कीर्तन पहली बार गोलमुरी के रिफ्यूजी कालोनी से निकाला गया। नगर कीर्तन निकालने का मौका मिलने पर रिफ्यूजी कालोनी के सिख समुदाय के लोग काफी खुश नजर आए। यहां से निकला नगर कीर्तन टुइलाडुंगरी होते हुए गोलमुरी मस्जिद रोड पहुंचा। यहां से यह नगर कीर्तन टिनप्लेट गोलचक्कर पहुंचा और फिर वहां से सीधे गोलमुरी चौक और आरडी टाटा गोलचक्कर होते हुए नगर कीर्तन में शामिल लोग साकची गुरुद्वारा पहुंचे। नगर कीर्तन में सिख समुदाय की महिलाएं भी शामिल थीं। नगर कीर्तन आगे बढ़ जाता तो समुदाय की महिलाएं सड़क साफ करते हुए चल रही थीं। नगर कीर्तन में युवा गतका का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। गतका का प्रदर्शन लोगों को खूब भाया। साकची पहुंचने पर गुरुद्वारा के सामने नगर कीर्तन पर पुष्पवर्षा की गई। नगर कीर्तन में गुरुग्रंथ साहिब की पालकी साहब भी साथ थी।

नगर कीर्तन में आगे चलते पंजप्यारे ● फोटोन न्यूज

डहरे टुसू डिमना से साकची तक निकली भव्य सांस्कृतिक शोभायात्रा, चौड़ल बने आकर्षण के केंद्र, पारंपरिक गीतों से गूंजा क्षेत्र

सड़कों पर उतरा लोक संस्कृति का सैलाब, मांदर की थाप पर झूमी लौहनगरी

PHOTON NEWS JSR : लौहनगरी रविवार को झारखंड की समृद्ध लोक कला और परंपराओं के रंग में सराबोर नजर आई। वृहद कला संस्कृति मंच के तत्वावधान में आयोजित 'डहरे टुसू' (सड़क पर टुसू उत्सव) ने आज शहर की सड़कों पर आस्था और उत्साह का अनूठा विहंगम दृश्य प्रस्तुत किया। वृहद झारखंड कला-संस्कृति मंच सहित विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक संगठनों की ओर से निकली विशाल शोभायात्रा डिमना चौक से साकची के आमबगान मैदान तक पहुंची, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु और संस्कृति प्रेमी शामिल हुए। उत्सव का नजारा बेहद मनमोहक और अनुशासित था। शोभायात्रा की शुरूआत में सुरक्षा के मद्देनजर एक फर्स्ट एड वाहन चल रहा था, जिसके ठीक पीछे महिलाएं मंच का बैनर थामे पूरी मयार्दा के साथ आगे बढ़ रही थीं। इस वर्ष के आयोजन में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही।

हाथों में भव्य और आकर्षक चौड़ल लिए श्रद्धालु मांदर और ढोल की थाप पर पारंपरिक टुसू गीत गाते हुए थिरक रहे थे। अपनी जड़ों और संस्कृति के प्रति गौरव का यह भाव पूरी शोभायात्रा में साफ झलक रहा था।

मानगो में निकली शोभायात्रा में शामिल लोग ● फोटोन न्यूज

आमबगान में सांस्कृतिक सभा और प्रतियोगिता

मानगो होते हुए जब पदयात्रा साकची पहुंची, तो वहां का आमबगान मैदान मिनी झारखंड के रूप में तब्दील हो गया। मैदान में एक विशाल सांस्कृतिक सभा का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों से आए टुसू चौड़ल के बीच प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। स्थानीय कलाकारों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह आयोजन न केवल मनोरंजन बल्कि युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम साबित हुआ।

यातायात पर पड़ा असर प्रशासन ने बदले रूट

हजारों की भीड़ और लंबी पदयात्रा के कारण शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। प्रशासन ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से डिमना रोड के एक हिस्से को पूरी तरह बंद कर दिया था। डिमना से साकची की ओर आने-जाने वाले वाहनों को एक ही लेन में डायवर्ट किया गया, जिसके कारण मानगो चौक और डिमना रोड पर भीषण जाम की स्थिति बन गई। घंटों लगे इस जाम से राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

मानगो से साकची तक उमड़े श्रद्धालु

इस भव्य सांस्कृतिक दृश्य को देखने के लिए मानगो और डिमना रोड के दोनों किनारों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। आलम यह था कि लोग अपने घरों की छतों और दुकानों के बाहर खड़े होकर इस विहंगम दृश्य को निहार रहे थे और अपने मोबाइल कैमरों में इन यादगार लम्हों को कैद कर रहे थे।

झाड़ी कटिंग के दौरान ट्रैक मेंटेनर की मालगाड़ी से कटकर हुई मौत

CHAIBASA : नए साल के चौथे दिन चक्रधरपुर रेल मंडल में एक बार फिर ट्रैक मेंटेनर की ड्यूटी के दौरान मौत की घटना सामने आई है। चाईबासा पीडब्ल्यूआई के अंतर्गत पांड्राशाली और राजखरसवां के बीच रेलवे ट्रैक पर झाड़ी कटिंग का कार्य करते समय ट्रैक मेंटेनर लंका पुरती की मौत हो गई। यह हादसा रविवार को हुआ। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ट्रैक मेंटेनर लंका पुरती (45), ग्रेड पे 1900 में कार्यरत थे। वे 301-17ए/19ए थर्ड लाइन पर डाउन दिशा में झाड़ी कटिंग का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान डाउन लाइन से आ रही मालगाड़ी की चपेट में आने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। रेलवे अधिकारियों ने उन्हें झाड़ी कटिंग का कार्य सौंपा था। घटना के बाद ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन ने गहरा दुख प्रकट किया है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक ट्रैक मेंटेनर रेलवे ट्रैक पर अपनी जान गंवाते रहेंगे और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कब सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि साल की शुरूआत में ही यह दर्दनाक घटना हुई है, जबकि पिछले एक वर्ष में 11 ट्रैक मेंटेनर शहीद हो चुके हैं। लंका पुरती झींकपानी थाना क्षेत्र के टुटुगुटू गांव के निवासी थे। उनके परिवार में पत्नी सावित्री पुरती, एक बेटी चांदमुनी पुरती (16) और दो पुत्र मनीष पुरती (14) एवं सावन पुरती (12) हैं। उनकी पांच संतानें हैं, जिनमें से दो बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटी और दो बेटे वर्तमान में पढ़ाई कर रहे हैं। घटना के बाद पोस्टमार्टम हाउस के पास रेलवे विभाग और यूनियन से जुड़े कई लोग उपस्थित थे।

BRIEF NEWS

उपमुख्यमंत्री आज भागलपुर में करेंगे शिकायतों की सुनवाई

BHAGALPUR : बिहार के उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा 5 जनवरी को भागलपुर के टाउन हॉल में पूर्वाह्न 11:00 बजे पहुंचेंगे। उनके आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला प्रशासन की ओर से शिकायत दर्ज कराने वाले लोगों की सूची तैयार की जा रही है। वहीं आमजनों की आवाजाही को सुचारू बनाए रखने के लिए यातायात एवं अन्य व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ किया गया है, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने बताया कि उपमुख्यमंत्री पहले शिकायतकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, इसके बाद संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने बताया कि दूसरी पाली में सभी अपर समाहर्ता, डीसीएलआर, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, बंदोबस्त पदाधिकारी, सीईओ, राजस्व अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारियों के साथ विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी।

डीएसपी कार्यालय में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित

EAST CHAMPARAN : जिले के रक्सौल डीएसपी कार्यालय में रविवार को मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता डीएसपी मनीष आनंद ने किया। बैठक में आनंद ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि गांजा, शराब सहित अन्य तरह के मादक पदार्थों कि तस्करी व बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगाया जाए , अन्यथा आपलोगों के विरुद्ध कारवाई के लिए लिखा जाएगा। अनुमंडल के अलग-अलग थाना में दर्ज कांड की समीक्षा की, लंबित कांडों के समय से निष्पादन के साथ-साथ अलग-अलग मामले में फरार चल रहे अभियुक्तों, कोर्ट वारंटियों की गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया। उन्होंने नेपाल की सीमा से लगे सीमावर्ती थाना के थानाध्यक्षों को शराब तस्करी पर लगाम लगाने के लिए सूचना को मजबूत करने का निर्देश दिए। बैंको में लगे सीसीटीवी कैमरे की नियमित जांच करने, संदिग्धों पर नजर रखने तथा नियमित वाहन जांच करने का निर्देश दिया।

महिलाओं की राजनीति में हिस्सेदारी बढ़ाएगा शक्ति अभियान : राजेश

PATNA : बेगूसराय जिले में आयोजित कांग्रेस के दो दिवसीय शक्ति अभियान के बुनियादी शिविर में आज दूसरे दिन प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने शिरकत की। अपने अध्यक्षीय संबोधन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी महिलाओं में राजनीतिक नेतृत्व और समझ को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी प्रतिबद्धता और महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी के लिए शक्ति अभियान के तहत बड़े पैमाने पर कांग्रेस महिलाओं को लेकर बुनियादी शिविर का आयोजन कर रही है।

आभूषण-कैश छिपाने का आरोप, चोरी के मामले में गए थे छापेमारी करने

सोना गबन मामले में लालगंज थाना के थानाध्यक्ष-दारोगा निलंबित

AGENCY MUZAFFARPUR : बिहार में सुशासन के दावों के बीच पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला एक बड़ा मामला सामने आया है। वैशाली जिले में 'रक्षक ही भक्षक' बन गए, जहां छापेमारी के दौरान बरामद हुए सोने-चांदी के जेवर और नकदी को पुलिसकर्मियों ने सरकारी रिकॉर्ड में चढ़ाने के बजाय खुद ही डकार लिया।

इस गंभीर अनुशासनहीनता और भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख अपनाते हुए तिरहुत रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने बड़ी कार्रवाई की है। डीआईजी के निर्देश पर वैशाली एसपी ने लालगंज के थानाध्यक्ष (एसएचओ) संतोष कुमार और सब-इंस्पेक्टर (एस आई) सुमन कुमार झा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह सनसनीखेज मामला वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार, बीते 30 दिसंबर को लालगंज पुलिस को बिलनपुर गांव में रहने वाले रामप्रीत सहनी के घर के संबंध में कुछ गुप्त सूचना मिली थी। इसी आधार पर थानाध्यक्ष संतोष कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वहां छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस को घर से भारी मात्रा में सोने-चांदी के जेवर और नकदी बरामद हुई। नियमतः पुलिस को इन सामानों की जब्ती सूची बनाकर उन्हें मालखाने में जमा करना चाहिए था और वरीय अधिकारियों को सूचित करना था। लेकिन आरोप है कि थानाध्यक्ष संतोष कुमार और सब-इंस्पेक्टर सुमन कुमार की नीयत डोल गई। उन्होंने बरामदगी को छिपा लिया और कीमती सामानों को आपस में बंदरबांट कर लिया।

संतोष कुमार थानाध्यक्ष

सुमन झा दारोगा

घूस लेते पकड़े गए थे सब-इंस्पेक्टर सुमन झा

वर्ष 2024 के 04 सितंबर को मुजफ्फरपुर में पोस्टिंग के दौरान सब-इंस्पेक्टर सुमन झा को 11 हजार रुपये घूस लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार किया गया। टेंगरारी गांव में एक जमीन विवाद में 144 की रिपोर्ट बनाने के लिए घूस मांग रहे थे। निगरानी टीम को इस बारे में सूचना मिली और उसने जाल बिछाकर सब इंस्पेक्टर को रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया था। सूत्रों के अनुसार अभी वह मामला कोर्ट में है।

'जीरो टॉलरेंस' का संदेश

डीआईजी चंदन कुशवाहा ने इस कार्रवाई के जरिए पूरे पुलिस महकमे को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग में किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्तमान में दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई से वैशाली पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि इस मामले में जल्द ही प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी शिकंजा और कसा जा सकता है। फिलहाल, वैशाली एसपी को निर्देशित किया गया है कि वे पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट सौंपें ताकि दोषियों पर कठोरतम सजा सुनिश्चित की जा सके।

आरोपी के रिश्तेदार ने पुलिस पर लगाया आरोप

हालांकि, इस गिरोह के उद्भेदन के बाद आरोपी रामप्रीत सहनी के रिश्तेदार गेना लाल सहनी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गेना लाल सहनी के अनुसार, पुलिस ने चोरी के आरोप लगाकर घर में घुसकर छापेमारी की और 50 से 60 लाख रुपए कैश, 2 किलोग्राम सोना और 6 किलोग्राम चांदी ले गई, जिसे पुलिस ने कहीं भी जब्त सूची में नहीं दिखाया। उन्होंने दावा किया कि गांव के लोगों ने पुलिस को सामान ले जाते देखा था।

डीआईजी की गोपनीय जांच में खुली पोल : भ्रष्टाचार की यह बात जब मुजफ्फरपुर रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा तक पहुंची, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। डीआईजी ने मामले की अत्यंत गोपनीय तरीके से जांच कराई। जांच रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि बरामदगी तो हुई थी, लेकिन उसे आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज नहीं किया गया। प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर डीआईजी ने इस कृत्य को 'वर्दी को शर्मसार करने वाली घटना' बताया। लालगंज थानाध्यक्ष संतोष कुमार पर यह पहला आरोप नहीं है। पुलिस द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, इससे पहले भी उनके कामकाज की शैली संदिग्ध रही है। उन पर मध्य प्रदेश की एक महिला के साथ हुए ठगी और यौन उत्पीड़न के मामले में लीपापोती करने और सही तरीके से कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगे थे। बार-बार मिल रही शिकायतों और ताजा भ्रष्टाचार के मामले ने उनकी विदाई तय कर दी।

25 हजार के इनामी कुख्यात विजय पांडे को बक्सर पुलिस ने किया गिरफ्तार

AGENCY BUXAR : जिले के टॉप-10 कुख्यात अपराधियों में शामिल 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी विजय पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रविवार को डुमरांव अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पोलस्त कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार अपराधी विजय पांडे, पिता स्वर्गीय शिव प्रसाद पांडे, ग्राम पोखरहा, थाना बगेन गोला, जिला बक्सर का रहने वाला है। वह हत्या, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट सहित कई संगीन आपराधिक मामलों में वांछित था और लंबे समय से पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। उसके खिलाफ विभिन्न मामलों में न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट भी जारी हो चुके थे।

पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य के निर्देश पर गिरफ्तारी के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचनाओं के आधार पर लगातार उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। गिरफ्तारी से बचने के लिए अपराधी बार-बार अपना ठिकाना बदलता रहा, लेकिन पुलिस की सतर्क निगरानी और निरंतर प्रयासों के चलते शनिवार को पुख्ता सूचना के आधार पर उसे ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी अभियान का नेतृत्व डीएसपी पोलस्त कुमार ने किया। टीम में डीआईओ प्रभारी सुधीर कुमार, बगेन गोला थाना अध्यक्ष अभय शंकर सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी और सशस्त्र बल शामिल थे।

जमीन विवाद में मारपीट, एक की मौत

AGENCY ARARIA : फारबिसगंज थाना क्षेत्र के रमई गांव के वार्ड संख्या 5 में जमीन विवाद में घर में घुसकर एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की। जिसमें 35 वर्षीय दिनेश झा पिता परमेश्वर झा का पूर्णिया ले जाने के क्रम में मौत हो गई। जबकि उनका भाई धनंजय कुमार बुरी तरह जख्मी हो गया, जिसका फारबिसगंज अनुमंडलीय अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद पूर्णिया रेफर कर दिया गया। पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में घायल धनंजय कुमार का इलाज चल रहा है। तीन साल पहले जमीन बिक्री करने के नाम पर दस लाख रुपैया ले लेने और जमीन रजिस्ट्री नहीं करने पर दवाब बनाने को लेकर जमीन मालिक के पक्ष के द्वारा घर में घुसकर हथियार और तलवार के साथ हमला करने का आरोप लगाया गया है। सूचना के बाद फारबिसगंज थाना पुलिस अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। मृतक दिनेश झा की पत्नी आरती देवी ने मारपीट करने का आरोप टुनटुन झा उर्फ प्रवेश झा, चंद्रेश्वरी झा, खुद्दी झा, सरपंच झा, दिलीप झा, कुंदन कुमार, कन्हैया कुमार, अंजली कुमारी, सुशीला देवी, विकास झा, सुमन झा आदि पर घर में बंदूक और तलवार के साथ घुसकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। आरती देवी ने बताया कि 2022 में ही जमीन के लिए टुनटुन झा और अन्य के द्वारा दस लाख रुपैया ले लिया गया था। लेकिन वे लोग जमीन रजिस्ट्री नहीं कर रहे थे। जमीन रजिस्ट्री को लेकर दवाब बनाया जा रहा था,उसी आक्रोश में मारपीट कर घायल कर देने का आरोप लगाया गया।इससे पहले भी जमीन मालिक द्वारा मारपीट करने और गाली गलौज करने पर फारबिसगंज थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी। जिस पर गांव में पुलिस और बीडीओ सीओ भी गए थे, लेकिन किसी तरह का कोई नतीजा नहीं निकला और आज घर में घुसकर मारपीट की गई।

सिकरहना नदी के ध्वस्त बांध का विधायक ने किया निरीक्षण, कहा-

जल्द कराया जाएगा बांध का पुनर्निर्माण

AGENCY EAST CHAMPARAN : जिले के सुगौली प्रखंड के सुकुलपाकड़ पंचायत अंतर्गत धूमनी टोला स्थित सिकरहना नदी के ध्वस्त और जर्जर बांध का सुगौली विधायक राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक ने बांध की वर्तमान स्थिति,कटाव की गंभीरता और उससे आसपास के गांवों पर पड़ने वाले संभावित खतरे की बारीकी से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने उपस्थित विभागीय अधिकारियों के साथ बांध के पुनर्निर्माण और कटावरोधी कार्यों को लेकर विस्तृत मंत्रणा की। मौके पर सिकरहना नहर प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता आलोक कुमार सहित विभाग के अन्य तकनीकी अधिकारी मौजूद थे। अधिकारियों ने विधायक को बांध की तकनीकी स्थिति,पूर्व में हुए नुकसान और आवश्यक मरम्मत व निर्माण कार्यों के बारे में अवगत कराया। विधायक श्री गुप्ता ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए बांध निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए,ताकि आसपास के ग्रामीणों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। विधायक ने बताया कि बीते माह उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं जल संसाधन मंत्री से मुलाकात कर सिकरहना नदी के जर्जर बांध और कटावरोधी कार्यों को लेकर गंभीरता से चर्चा की थी। उसी का परिणाम है कि अब विभागीय स्तर पर कार्रवाई तेज हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांध का पुनर्निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा और कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा।

आयुष हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने की मांग

SAHARSA : जिले के सत्तर कटैया प्रखंड के सिहौल निवासी होनहार छात्र आयुष कुमार हत्याकांड को घटित हुए सात महीने बीत चुके हैं लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई ठोस सफलता नहीं लगी है। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित परिवार एक बार फिर शांतिपूर्ण तरीके से लगातार तीसरे दिन आमरण अनशन पर बैठा है। इकलौते पुत्र को खो चुके माता-पिता का कहना है कि वे अब तक न्याय की प्रतीक्षा में दर-दर भटक रहे हैं। पीड़ित मां नीतू कुमारी ने भावुक होते हुए कहा कि देर से मिला न्याय, न्याय नहीं बल्कि एक और अन्याय है। उन्होंने प्रशासन से अविलंब मामले का खुलासा कर दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की।

घोड़ासहन थाना परिसर में एसपी ने की जनसुनवाई, 52 मामलों में दिए दिशा-निर्देश

AGENCY EAST CHAMPARAN : जनसुनवाई कार्यक्रम के तहत पुलिस अधीक्षक एसपी स्वर्ण प्रभात ने रविवार को घोड़ासहन थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया। यह कार्यक्रम दोपहर से शाम तक चला, जिसमें 70 फरियादियों ने आवेदन दिए। इनमें से 52 फरियादियों की सुनवाई की गई।इस दौरान कुण्डवा चैनपुर थाना क्षेत्र के लगभग तीन वर्ष पुराने 307 के एक अभियुक्त भिखारी यादव को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने एक-एक कर फरियादियों की बात गंभीरता से सुनी और कई मामलों में मौके पर ही संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।जनता दरबार में भूमि विवाद, आपसी मारपीट, पारिवारिक विवाद, पुलिस से जुड़ी शिकायतें, अनुसंधान में विलंब तथा सामाजिक मामलों से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए। एसपी स्वर्ण प्रभात ने स्पष्ट किया कि आम जनता की समस्याओं का त्वरित और निष्पक्ष समाधान पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है।उन्होंने फरियादियों को भरोसा दिलाया कि जिन मामलों में तत्काल कार्रवाई संभव है, उनमें बिना देरी के कदम उठाए जाएंगे। वहीं, जटिल मामलों की जांच कर समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। एसपी ने थाना प्रभारी और उपस्थित पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता से संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करें तथा शिकायतों की अनदेखी किसी भी सूरत में न हो। उन्होंने यह भी कहा कि जनता दरबार का उद्देश्य पुलिस और आम नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करना है, ताकि लोग बिना भय के अपनी समस्याएं साझा कर सकें।

पहल नौकरीपेशा और व्यवसायी वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत

रविवार और छुट्टियों के दिन भी खुले रहेंगे निबंधन कार्यालय

AGENCY PATNA : बिहार सरकार ने राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए रविवार और छुट्टी के दिन भी निबंधन कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर पूरे राज्य में अब निबंधन कार्यालय सभी दिन खुलेंगे। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार का लक्ष्य केवल राजस्व बढ़ाना नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए निबंधन की प्रक्रिया को आसान बनाना है। नए साल में यह व्यवस्था जनवरी के लिए फिलहाल किया गया है लेकिन जो जानकारी मिल रही है, इस वित्तीय वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिसूचना में जो जानकारी दी गई है कि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दफ्तरों की छुट्टी के कारण संपत्ति का निबंधन टलता है। अब सरकार ने जो व्यवस्था की है, उसके कारण नौकरी पेशा और व्यावसायिक लोगों को बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि वह रविवार और छुट्टी के दिन भी आराम से निबंधन करा सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि नई व्यवस्था से निबंध के लिए लगने वाली भीड़ कमेगी और राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

बिहार सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले कई बड़े फैसले लिए हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डेढ़ करोड़ से अधिक महिलाओं को हजारों करोड़ों की राशि दी गई है।

राजस्व बढ़ाने पर होगा जोर

चुनावी घोषणाओं और वादों के कारण सरकार का बजट गड़बड़ाया हुआ है। अब 5 सालों में सरकार को एक करोड़ नौकरी रोजगार भी देना है। कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी करना है। ऐसे में सरकार के लिए राजस्व बढ़ाना मजबूरी है और यह प्रयास उसी दिशा में माना जा रहा है।

काम में होगी आसानी

हालांकि सरकार के फैसले का कितना असर राजस्व बढ़ाने में होता है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल सरकार के फैसले पर रजिस्ट्री करने वाले कातिब सुभाष सिंह का कहना है कि लोगों को इससे लाभ मिलेगा और सरकार का भी राजस्व बढ़ेगा, क्योंकि छुट्टी के दिन जब खुलेगा तो लोग आसानी से अपना रजिस्ट्री का चालान कटा सकते हैं। हालांकि पहला संडे होने के कारण पटना रजिस्ट्री निबंधन कार्यालय के पास इक्के-दुक्के लोग ही दिखाई दिए।

कांग्रेस चलाएगी 45 दिनों तक मनरेगा बचाओ अभियान

ARARIA : कांग्रेस पूरे देश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात मनरेगा को बचाने को लेकर 45 दिनों का अभियान चलाएगी, जिसके तहत प्रेस कांफ्रेंस, धरना प्रदर्शन से लेकर संवाद और रैली तक आयोजित होगी। 8 जनवरी से पीसीसी सत्र की तैयारी को लेकर बैठक कर इसका आगाज किया जाएगा। जबकि हर राज्य में 7 से 15 फरवरी तक विधानसभा घेराव के साथ 16 से 25 फरवरी तक एआईसीसी जोनल मेगा रैलियां आयोजित की जाएगी। जानकारी अररिया सदर कांग्रेस विधायक अबिदुर रहमान ने रविवार को दी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के संगठन के महासचिव वेणुगोपाल के हवाले से विधायक ने बताया कि मनरेगा भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा है।

आपदा पीड़ितों के लिए हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम, दी गई जानकारी

AGENCY NAVADA : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश के आलोक में रविवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिल्पी सोनीराज के मार्गदर्शन तथा श्री धीरेन्द्र कुमार पाण्डेय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के निदेर्शानुसार नवादा जिले के वारिसलीगंज प्रखंड के मोहीउद्दीनपुर ग्राम पंचायत स्थित सामुदायिक भवन परिसर में आपदा पीड़ितों को विधिक सहायता एवं उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला विधिक सेवा प्राधिकार, नवादा के लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल अमन जैन, पी०एल०वी० अश्विनी कुमार, मोहीउद्दीनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से किया ।अपने संबोधन में लीगल एड डिफेंस कॉन्सिल अमन जैन ने बताया कि आपदा पीड़ितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु विधिक सेवा प्राधिकार का गठन नालसा के निदेर्शानुसार किया गया है। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से मुआवजा एवं अन्य कानूनी सहायता का प्रावधान है, जिसका लाभ पात्र आपदा पीड़ित प्राप्त कर सकते हैं।

NEWS BOX

सरौनी मुखिया ने सैकड़ों जरूरतमंदों में किया कंबल वितरण

AGENCY NAVADA : नवादा जिले के कौआकोल प्रखण्ड के सरौनी पंचायत भवन में रविवार को सरौनी पंचायत के मुखिया पंकज कुमार यादव के द्वारा सैकड़ों गरीब व असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। सादे समारोह में शिविर लगाकर मुखिया ने पंचायत के विभिन्न गांवों के 500 से अधिक जरूरतमंद लोगों को कंबल मुहैया कराया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उनके द्वारा निजी खर्च से जरूरतमंदों के बीच कम्बल का वितरण किया गया। भीषण ठंढ में कम्बल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे एवं लोगों ने मुखिया के प्रति आभार जताया। मौके पर मौजूद समाजसेवी विकास सम्राट उर्फ विकास यादव ने कहा कि पीड़ित मानवता की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उन्होंने इस कार्य के लिए मुखिया पंकज यादव की सराहना भी किया। मौके पर सुधीर यादव, सुरेश प्रसाद यादव, मुद्रिका यादव, दानीलाल पंडित, शमीम अंसारी, मंटू यादव, विकास पण्डित, रामजतन कुमार, रौशन मियां आदि मौजूद थे।

मवेशी तस्करी की बड़ी कोशिश नाकाम, पिकअप वैन जब्त

AGENCY BUXAR : सिमरी प्रखंड के तिलक राय के हाता थाना क्षेत्र के बड़का राजपुर गांव के पास तटबंध पर शनिवार देर शाम ग्रामीणों ने मवेशी तस्करी की एक बड़ी कोशिश को विफल कर दिया। तस्करी के लिए ले जाए जा रहे मवेशियों से लदे तीन पिकअप वाहनों को ग्रामीणों ने घेर लिया। इस दौरान दो वाहन डायल 112 के सामने से होते हुए थाने की ओर भाग निकलने में सफल रहे, जबकि एक पिकअप को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए वाहन में चार मवेशी लदे थे, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। मवेशियों को अमानवीय तरीके से ठूंस-ठूंसकर लादे जाने की बात सामने आई है। घटना की सूचना मिलते ही काफी ग्रामीण मौके पर जुट गए और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने मवेशी तस्करी में पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगाया। उनका कहना है कि थाना क्षेत्र से प्रतिदिन कई वाहन गोवंश को कथित रूप से बुचड़खानों की ओर ले जाते हैं, लेकिन शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। उल्टे, विरोध करने पर ग्रामीणों को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है। आरोप है कि थाना से मात्र दो किलोमीटर दूर घटनास्थल पर पुलिस करीब एक घंटे बाद पहुंची, जिससे दो वाहन फरार हो गए। थानाध्यक्ष पूजा कुमारी ने बताया कि पिकअप चालक ब्रह्मानंद पासवान को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है और अन्य आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की प्रक्रिया जारी है।

अररिया में निकली तिरंगा यात्रा शामिल हुए हजारों लोग

AGENCY ARARIA : जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा मुख्य बॉर्डर से एसएसबी 56 वीं बटालियन की ओर से रविवार को तिरंगा यात्रा निकाला गया जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे सहित एसएसबी के अधिकारी, जवान, जनप्रतिनिधि समेत स्थानीय लोगों ने तिरंगा के साथ हिस्सा लिया और कदमताल करते हुए शिरकत की। 77 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर एसएसबी 56वीं की ओर से निकले तिरंगा यात्रा में भारत माता की जय और वंदे मातरम का जमकर नारे लगे। कार्यक्रम का नेतृत्व कमांडेंट आईपीएस शाश्वत कुमार जी ने किया और तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य एक्सेस टू जस्टिस को बढ़ावा देना बताया। तिरंगा यात्रा में स्थानीय विधायक मनोज विश्वास,नरपतगंज विधायक देवयंती यादव,जोगबनी नगर परिषद मुख्य पार्षद रानी देवी,उप मुख्य पार्षद अनीता देवी,रोहित यादव, बिट्टू चौधरी,राहुल चौधरी, अनवर राज, खुर्शीद खान, रजनीकांत झा, संजय कुमार, जावेद खान, गुड्डू कुमार, मेराज खान, राजेश कुमार शर्मा, वरुण मिश्रा, अशोक कुमार झा समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया।

हिजाब विवाद : क्रिया से खतरनाक प्रतिक्रिया

देश में पिछले दिनों उस समय हिजाब को लेकर फिर एक बहस छिड़ गई ,जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गत 15 दिसंबर को पटना में एक सरकारी कार्यक्रम में नव नियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित करते समय एक मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत परवीन जोकि चेहरा ढकने वाला हिजाब पहने हुई थीं, का हिजाब सार्वजनिक मंच से उसके चेहरे से खींच कर उतारने की कोशिश की। उस समय डॉक्टर नुसरत परवीन स्टेज पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों नियुक्ति पत्र ग्रहण करने हेतु आमंत्रित की गई थीं। इस घटना ने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। इस घटना से संबंधित वायरल वीडीओ में देखा जा सकता है कि घटना के समय जहां डॉक्टर नुसरत असहज दिखीं, वहीं उसी मंच पर मौजूद बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी न केवल घटना से हतप्रभ नजर आए, बल्कि उन्होंने नीतीश की ओर हाथ बढ़ाते हुए उन्हें हिजाब खींचने से रोकने की कोशिश भी की। उसी मंच पर मौजूद कुछ लोग हंसते हुए भी दिखाई दिए। इस घटना से एक बात तो साबित हो ही गई कि नितीश कुमार जैसे अनुभवी राजनेता लगभग 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसी वजह से वे पहले भी महिलाओं को लेकर की गई एक अत्यंत अभद्र टिप्पणी के लिए आलोचना का पात्र बन चुके हैं। कभी कभी सार्वजनिक मंचों पर उनकी बेतुकी बातें व उनकी असामान्य हरकतें भी यही संकेत देती कि अब वे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें सार्वजनिक सक्रिय राजनैतिक जीवन से सन्यास ले लेना चाहिये, परंतु इस घटना के बाद जिस तरह से इसे परिभाषित करने की कोशिश की गई, वह और भी हैरान करने वाली बात थी। हिजाब खींचने की बहस को नीतीश कुमार की मनोदशा से जोड़कर देखने के बजाय हिजाब धारण करने न करने को लेकर ही बहस छिड़ गई। इस्लाम व मुस्लिम विरोध की राजनीति पर अपनी दुकानें चलाने वाले कुछ नेता तो बेशर्मी की सभी हदें पार करते हुए, नीतीश कुमार के बचाव में उतर आए। कांग्रेस, आरजेडी व अन्य कई विपक्षी दलों ने इसे महिलाओं और मुस्लिम समुदाय का अपमान बताया। किसी ने नीतीश से माफी की मांग की तो किसी ने इस्तीफा मांगा, जबकि कुछ ने नीतीश की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए। इस विषय पर सबसे घटिया, ओछी अपमानजनक प्रतिक्रिया देने वाले दो नेता ऐसे भी हैं, जो केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जैसे संवैधानिक पदों पर बैठकर इस मुद्दे पर जहर उगल रहे हैं तथा अपनी अशिष्ट शब्दावली से देश की संवैधानिक मयार्दाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। इनमें नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर अपनी पहली प्रतिक्रिया संसद भवन में देने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार का खुलकर बचाव करते हुए कहा कि नीतीश ने कुछ भी गलत नहीं किया है। नियुक्ति पत्र लेने आए व्यक्ति को चेहरा दिखाना चाहिए। क्या भारत कोई इस्लामिक देश है। एयरपोर्ट, पासपोर्ट या वोटिंग के समय चेहरा दिखाना पड़ता है, तो यहां क्यों नहीं। जब उनसे सवाल किया गया कि महिला डॉक्टर नुसरत परवीन के नौकरी छोड़ने की खबर है, इस पर गिरिराज सिंह गुस्से में यह कहते सुनाई दिए कि नौकरी करे या जहन्नुम में जाए। उनका यह बयान सबसे ज्यादा विवादित रहा और इसे सांप्रदायिक व अपमानजनक बयान के रूप में देखा गया। ऐसा ही निम्नस्तरीय बयान उत्तर प्रदेश सरकार में मत्स्य पालन मंत्री संजय निषाद द्वारा दिया गया। उन्होंने भी नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि अरे वो भी तो आदमी हैं न... नकाब छू दिया तो इतना बवाल। कहीं और छू देते तो क्या हो जाता। संजय निषाद के इस बयान को भी महिला गरिमा को आहत करने की नजरों से देखा गया। जेडीयू के नेता व बिहार के अल्पसंख्यक मंत्री जमा खान ने नीतीश के प्रति अपनी वफादारी का सुबूत देते हुए यह कहा कि यह पिता जैसा स्नेह था, तो कुछ मुस्लिम व महिला संगठनों द्वारा इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने व कई जगह नीतीश के विरुद्ध प्रदर्शन करने व उनका पुतला जलाने की भी खबरें हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय तो यही है कि इस घटना को लेकर नीतीश के मानसिक स्वास्थ पर चर्चा होने के बजाय जिस तरह हिजाब पर ही बहस छेड़ दी गई और वह भी अपने कुतर्कों के द्वारा, इससे यह साबित होता है कि सांप्रदायिकता की राजनीति करने वाले मुस्लिम विरोध या इस्लामी प्रतीकों के विरोध का कोई भी अवसर गंवाना नहीं चाहते अन्यथा किसी केंद्रीय मंत्री के इस बेहूदे कुतर्क का क्या अर्थ कि एयरपोर्ट, पासपोर्ट या वोटिंग के समय चेहरा दिखाना पड़ता है, तो यहां क्यों नहीं। संविधान की शपथ लेने वाले इस केंद्रीय मंत्री गिरिराज को पता नहीं कि एयरपोर्ट, पासपोर्ट या वोटिंग के समय महिला सुरक्षा कर्मियों द्वारा किसी महिला की स्वेच्छा से उसके अपने हाथों से हिजाब या पर्दा हटाने को कहा जाता है न कि नीतीश कुमार की तरह बदतमीजी से किसी के चेहरे से हिजाब खींचा जाता है। ऊपर से पीड़िता को ही यह कहना कि वह नौकरी करे या जहन्नुम में जाए, इस तरह की शब्दावली देश का एक केंद्रीय मंत्री इस्तेमाल कर रहा है। बुर्का या हिजाब को लेकर खुद विश्व मुस्लिम जगत में ही बड़ा घमासान है। दुनिया के कई अलग-अलग इस्लामी देश अलग अलग तरह के परदे या हिजाब की पैरवी करते रहे हैं, जबकि विश्व का एक बड़ा उदारवादी व प्रगतिशील वर्ग ऐसा भी है, जो इस तरह की बंदिशों को गैरजरूरी समझता है। कोई इसे इस्लामिक व शरिया से जुड़ी व्यवस्था बताता है, तो कोई इसे सामाजिक या भौगोलिक जरूरतों का हिस्सा बताता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर संकट

ANALYSIS

✍ पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

साल 1971 के युद्ध के पीछे पाकिस्तान की नेशनल आर्मी के सैनिक स्थानीय बंगाली आबादी के साथ बलात्कार, मारपीट और दूसरे अपराध थे, जिससे तंग लोग भारत भाग गए। इतने बड़े पैमाने पर पलायन और अमानवीय गतिविधियों को देखते हुए भारत सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तानी शासन से आजाद कराकर नया देश बनाने का फैसला किया। मुख्य संघर्ष के दौरान भारत द्वारा प्रशिक्षित बांग्ला मुक्ति वाहिनी ने खुफिया जानकारी इकट्ठा की और कुछ इलाकों में पाकिस्तान से सप्लाई बंद करने में मदद की। भारतीय सेना ने ज्यादातर सैनिक ट्रेनिंग, उपकरण और मैनपावर सप्लाई की। युद्ध की आधिकारिक शुरूआत से बहुत पहले भारतीय सेना, मुक्ति फौज से मिलकर लड़ रही थी। पहली झड़प 01 जुलाई 1971 में हुई जब 57 आर्टिलरी ब्रिगेड ने कर्नल पीके गौतम के ऑपरेशन बांग्लादेश के तहत आतग्राम और चग्राम में पाकिस्तानी ठिकानों को नष्ट कर दिया। ऐसी मुठभेड़ें दिसंबर तक जारी रहीं, जिसके दौरान मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला युद्ध, तोड़फोड़ और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का काम किया। हालांकि वे सीधे मुकाबले में भारतीय सेना पर निर्भर थे, क्योंकि वे सीधे मुकाबले में कमजोर लड़ाके थे। दिसंबर 1971 में भारत ने 3900 सैनिक खो दिए। पाकिस्तान से आजादी मिलने के बाद भारत ने उन्हें घर लौटने में मदद की, ट्रांसपोर्टेशन दिया और सड़कों एवं पुलों की मरम्मत में सहायता की। भारत ने बांग्लादेश को जो लगभग 232 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता का वादा किया था, वह दे दिया गया। साल 1972 में बांग्लादेश को खाद्यान्न मदद का सबसे बड़ा हिस्सा भारत का था। भारत-बांग्लादेश व्यापार समझौते से बांग्लादेश को बहुत फायदा हुआ। 28 मार्च 1972 को 5 करोड़ रुपये की ब्याज मुक्त स्विंग लिमिट के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे बांग्लादेश को कोयला और अन्य जरूरी सामान और संसाधन खरीदने की अनुमति मिली। भारत में लाखों बांग्लादेशी प्रवासियों का स्वागत किया गया और देश के आम नागरिकों ने स्वेच्छा से वित्तीय बोझ साझा किए। देश के नागरिकों ने पूर्वी पाकिस्तानी प्रतिरोध बलों का जोरदार समर्थन किया और एक युद्ध कर लगाया गया। हालांकि पाकिस्तानी सेना के लगातार अत्याचारों के कारण स्थिति और खराब होने की आशंका थी, इसलिए भारत को आखिरकार सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। असल में भारत ने अमेरिका को नाराज करने का भी खतरा मोल लिया जो एक सुपरपावर था और याह्या खान की तानाशाही का खुलेआम समर्थन कर रहा था। भारतीय लोगों ने शरणार्थियों की बाढ़ और उसके बाद हुए संघर्ष का भारी वित्तीय बोझ उठाया, यह दूसरे देशों के लोगों की दुर्दशा के प्रति भारत की दृढ़ता और करुणा का सबूत है। भारत ने 1971 का युद्ध किसी साम्राज्यवादी सपने या किसी खास राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए नहीं लड़ा था। भगवान राम ने हजारों साल पहले रावण को लंका पर कब्जा करने के लिए नहीं, बल्कि नैतिकता और धर्म का शासन फिर से स्थापित करने के लिए हराया था। अपनी जीत के बाद राम ने लंका उसके निवासियों और राजा विभीषण को वापस सौंप दी थी। इसी तरह भारत ने कट्टर राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता और नरसंहार के खिलाफ युद्ध लड़े। हम सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि करुणा और दूसरों के साथ एकता जैसे ऊँचे विचारों से भी जीते। सवाल यह है कि अच्छे और बुरे दोनों समय में बांग्लादेश में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद हिंदुओं को क्यों सताया जा रहा है। हाल के वर्षों में कई बांग्लादेशियों के बीच धार्मिक पहचान ज्यादा आम हो गई है और कई लोग नैतिक और भाषाई हैंगओवर से थक चुके हैं। अगर मजहब कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है तो आप बस उस देश का समर्थन नहीं कर सकते जिसने कुछ दशक पहले ही आपके देश में सबसे भयानक नरसंहारों में से एक किया था। आपको भारत जैसे देश से खुलेआम नफरत करने के लिए क्या प्रेरित करता है, जिसने आपको आजादी दिलाने में मदद की और आपकी संप्रभुता को मान्यता देने वाले पहले कुछ देशों में से एक था। साल 2024 के विद्रोह के बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, जिसने न केवल देश के आंतरिक राजनीतिक माहौल को बिगाड़ा, बल्कि इसके आसपास के क्षेत्र में भी रणनीतिक बदलाव किए। इसके अलावा चरमपंथी यूनुस के अंतरिम प्रशासन के तहत पूरे देश में कट्टरपंथ और धार्मिक उग्रवाद में चिंताजनक वृद्धि हुई है।बांग्लादेश में पिछले साल से कट्टरपंथी संगठन और विचारधाराएं ज्यादा प्रचलित हो गई हैं। उदाहरण के लिए जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी संगठनों को यूनुस प्रशासन के तहत पिछले प्रशासन की तुलना में ज्यादा जगह मिली है। ये समूह अब सार्वजनिक तौर पर हिंदू विरोधी बातचीत और सड़कों पर ज्यादा दिखाई देते हैं। मस्जिदों और धार्मिक स्कूलों के जरिए इस्लामी समूहों ने आबादी के एक बड़े हिस्से, खासकर युवाओं को कट्टरपंथी बनाया है। देश में बढ़ते कट्टरपंथ के कारण बांग्लादेश में अल्पसंख्यक, खासकर हिंदू ज्यादा खतरनाक स्थिति में हैं। दुख की बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की संपत्ति, निजता और जीवन असुरक्षित हैं। ऐसे जघन्य कृत्यों को या तो राज्य द्वारा नजरअंदाज किया जाता है या उसे बढ़ावा दिया जाता है। अमानवीय इस्लामी क्रूरता के अधिकांश शिकार महिलाएं और बच्चे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान, दोनों में हिंदू आबादी में तेजी से गिरावट आई है। उन देशों में रहने वाले हिंदुओं के लिए मानवाधिकार अभी भी दिवास्वप्न है। मूर्तियों और मंदिरों को अक्सर अपवित्र किया जाता है या नष्ट कर दिया जाता है और उनके धार्मिक विश्वास को निशाना बनाया जाता है। इन देशों के नेताओं द्वारा इस्लाम में धर्मांतरण ही एकमात्र रास्ता बताया जाता है। यह 1922 और 1946 में भी लागू था। लक्षित हमलों, भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या और सांप्रदायिक हिंसा के कारण डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। आवासीय घरों पर हमला किया गया है, पूजास्थलों को तोड़ा गया है और संपत्ति नष्ट की गई है। अल्पसंख्यकों को किसी आपराधिक गतिविधि के बजाय उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया जा रहा है। ऐसी हिंसा सरकार पर लोगों का भरोसा कम करती है और यह संदेश देती है कि इंसानियत से ज्यादा इस्लामिक धार्मिक कट्टरता जरूरी है। पिछले कुछ महीनों में भीड़ द्वारा उत्पीड़न और लिंचिंग की कई घटनाएं सामने आई हैं, जो हिंसा में चिंताजनक बढ़ोतरी का संकेत देती हैं। ऐसी ही एक घटना में चंद्रदास नाम के 25 साल के एक हिंदू दलित व्यक्ति को कथित तौर पर ईशनिंदा के झूठे आरोप में बर्बर तरीके से जलाकर मार डाला गया। हालांकि सांप्रदायिक हमलों में मुख्य रूप से हिंदुओं को निशाना बनाया गया है लेकिन हिंदू ही हिंसा के एकमात्र शिकार नहीं हैं।

ठाकरे बंधुओं की एकता का महाराष्ट्र की राजनीति पर असर

तकरीबन दो दशकों की राजनैतिक रस्साकशी के बाद आखिरकार ठाकरे बंधुओं ने एकजुट होकर महाराष्ट्र की राजनीति में जोर आजमाने का एलान किया है। शिवसेना से अलग होकर अपनी नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) बनाने वाले राज ठाकरे तमाम कोशिशों के बावजूद अपनी कोई राजनैतिक हैसियत बनाने में नाकाम रहे तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने की चाह में भाजपा से गठबंधन तोड़ वैचारिक प्रतिद्वंदियों के खेमे में गए उद्धव ठाकरे के पास न तो शिवसेना बची है और न ही हिंदुत्व का भगवा ध्वज लहराने वाले शिवसैनिक। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में करारी हार के बाद अब नगर निकाय के चुनाव में भी शिवसेना (उद्धव) की दुर्गति ने ठाकरे परिवार के राजनैतिक अस्तित्व पर गहरे प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। अब अगर ठाकरे की पार्टी की जीवनरेखा कही जाने वाले बृहन्मुम्बई नगर निगम (बीएमसी) चुनाव में भी उनका प्रदर्शन खराब रहता है, तो उन्हें अपना राजनैतिक भविष्य बचा पाना दुश्कर हो जाएगा। बीएमसी चुनाव से ठीक पहले ठाकरे बंधुओं का एक मंच पर आकर एकजुटता का एलान करना कुछ लोगों को उत्साहित कर रहा है तो एक बड़ा वर्ग उन लोगों का भी है, जिनका मानना है कि महाराष्ट्र की राजनीति में हाशिए पर पहुंच चुके ठाकरे बंधुओं के सियासी गठबंधन का कोई खास राजनैतिक असर नहीं होगा। मराठा राजनीति पर इस नए गठजोड़ के असर का वास्तविक आकलन करने के लिए बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना से लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उसके शिवसैनिकों की मनःस्थिति को समझना होगा। साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा के क्रमिक उभार को भी सामने रखना होगा, तभी ठाकरे बंधुओं की एकजुटता का महाराष्ट्र की भावी राजनीति पर पड़ने वाले असर को समझा जा सकता है। भाजपा और शिवसेना के बीच राजनैतिक समझौते का दौर वर्ष 1984 से शुरू हुआ, तब शिवसेना उम्मीदवार भाजपा के चुनाव चिह्न पर चुनाव मैदान में उतरे थे। इसके बाद साल 1989 का विधानसभा चुनाव भाजपा और शिवसेना में मिलकर लड़ा, जिसका दोनों दलों को लाभ हुआ। इसी तरह का लाभ उन्हें साल 1995 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ और शिवसेना-भाजपा गठबंधन ने महाराष्ट्र में सरकार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली। इसके बावजूद महाराष्ट्र में भाजपा-शिवसेना का गठबंधन सहज नहीं रहा। दोनों दल मौका मिलते ही एक-दूसरे के खिलाफ न सिर्फ बयानबाजी करते, बल्कि चुनावों में भी खुले तौर पर आपस में टकराते दिखाई दिए। इसका सबसे बड़ा कारण महाराष्ट्र की राजनीति में भाजपा का सतत उभार था। भाजपा और शिवसेना दोनों ही दलों की राजनीति का आधार हिंदुत्व है। ऐसे में शिवसेना के नेता भाजपा के बढ़ते कद को अपनी राजनीति के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते रहे थे। साल 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव दोनों दलों ने अलग-अलग लड़ा हालांकि बाद में शिवसेना सरकार में शामिल हो गई, लेकिन कटुता लगातार बनी रही। नतीजतन साल 2018 में उद्धव ने भाजपा से अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बाद में समझौता होने पर दोनों दलों ने मिलकर साल 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र की राजनीति के जानकारों का मानना है कि मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी मजबूत करने के लिए भाजपा से अधिक सीटें जीतने की चाह में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से अंदरखाने हाथ मिला लिया और कई सीटों पर भाजपा को नुकसान भी पहुंचाया। इसके बावजूद जब चुनाव नतीजे आए तो भाजपा 105 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी रही जबकि शिवसेना 56, एनसीपी 54 और कांग्रेस 44 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर पाई। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के गुप्त समझौते का इतना असर जरूर हुआ कि 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में भाजपा बहुमत के जादुई आंकड़े 145 से काफी दूर रह गई। महाराष्ट्र में किंग मेकर की भूमिका से हटकर खुद किंग बनने को लालायित उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने की जिद पर अड़ गए। इधर, महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार आधार खोते जा रहे शरद पवार ने इस मौके का फायदा उठाने में कोई चूक नहीं की। उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति करने वाली भाजपा और शिवसेना के बीच दरार को चौड़ा करके भविष्य का राजनैतिक पथ निष्कंटक बनाने का भरोसा देकर कांग्रेस को भी विश्वास में ले लिया। मुख्यमंत्री बनने की चाह में पिता बाला साहेब ठाकरे की वैचारिक विरासत को दरकिनार कर उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के साथ महागठबंधन में शामिल हो गए। कुर्सी पर बने रहने के लिए राममंदिर, अनुच्छेद 370 जैसे हिंदुत्व के कोर मुद्दों पर भी वह एनसीपी और कांग्रेस की छद्म पंथनिरपेक्ष राजनीति के साथ ही खड़े नजर आए। इसके चलते कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा वाले शिवसैनिकों में लगातार असंतोष बढ़ता गया और अंततः एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह कर दिया। तब से हिंदुत्व की विचारधारा वाली शिवसेना का नेतृत्व एकनाथ शिंदे के पास है, जबकि उद्धव ठाकरे एक नया दल शिवसेना (यूबीटी) बनाकर सेक्यूलर राजनीति कर रहे हैं। इधर, साल 1988 से अपने राजनैतिक जीवन की शुरूआत करने वाले राज ठाकरे का शिवसैनिकों पर खासा असर था। सिर्फ उनका रंग-रूप ही बाला साहेब ठाकरे से नहीं मिलता था बल्कि कार्टून बनाने की कला, आक्रमता और भाषण शैली में भी शिवसेना प्रमुख की छाप स्पष्ट दिखाई देती थी। उनका राजनैतिक कद तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन साल 1996 में रमेश किनी की मौत के मामले में राज ठाकरे का नाम आने की वजह से उनके राजनैतिक जीवन पर जैसे ग्रहण लग लग गया।

Social Media Corner

सच के हक में...

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस साफ तौर पर 3 मांगें करती है- 'वीबी जी राम जी' कानून वापस लिया जाए। मनरेगा को अधिकार आधारित कानून के तौर पर बहाल किया जाए। काम के अधिकार और पंचायतों के अधिकार को बहाल किया जाए इसीलिए हमने देशव्यापी मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू किया है। मनरेगा कोई चैरिटी नहीं है। यह एक कानूनी गारंटी है। करोड़ों सबसे गरीब लोगों को उनके अपने गांवों में काम मिला, भूख और मजबूरी में पलायन कम हुआ, ग्रामीण मजदूरी बढ़ी, और महिलाओं की आर्थिक गरिमा मजबूत हुई। 'वीबी जी राम जी' इस अधिकार को खत्म करने के लिए बनाया गया है। कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है क्योंकि काम अब गारंटी वाला अधिकार नहीं रहेगा, बल्कि चुनी हुई पंचायतों में सिर्फ.एक अनुमति होगी। बजट सीमित कर दिया जाएगा, इसलिए संकट के समय भी पैसा खत्म होने पर काम बंद हो जाएगा। दिल्ली फंड और काम तय करेगी, जिससे ग्राम सभाएं और पंचायतें बेकार हो जाएंगी। 60 दिन के काम के ब्लैकआउट से सबसे ज्यादा जरूरत के समय काम न देने को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। मजदूरी एक सुरक्षित हक होने के बजाय अनिश्चित और कम की जा सकेगी।

(मल्लिकार्जुन खड़गे का 'एक्स' पर पोस्ट)

कोई भी राष्ट्र केवल संसाधनों, तकनीक या आर्थिक सामर्थ्य से महान नहीं बनता। राष्ट्र की वास्तविक शक्ति इस बात में निहित होती है कि वह किन आदर्शों को अपने जीवन-मूल्यों का आधार बनाता है और किन व्यक्तित्वों को अपना आदर्श मानता है। आदर्श केवल स्मरण की वस्तु नहीं, बल्कि वे दिशा देने वाली प्रेरक शक्ति होते हैं। आदर्श अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा होते हैं। इसीलिए हमारे आदर्शों की परंपरा में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर के साथ-साथ महामना मालवीय जी और श्रद्धेय अटल जी भी सम्मिलित हैं।

(राजनाथ सिंह का 'एक्स' पर पोस्ट)

समान संवेदना और न्याय की जरूरत

बांग्लादेश से आईं दो तस्वीरों ने आज पूरे दक्षिण एशिया को झकझोर कर रख दिया है। एक तस्वीर हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की है, जिसे कथित तौर पर ब्लासफेमी के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। दूसरी तस्वीर छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोनों हत्याएं निंदनीय हैं, दोनों पर समान संवेदना और समान न्याय की जरूरत थी। लेकिन, यहीं पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस का दोगलापन खुलकर सामने आ गया। उस्मान हादी की मौत के बाद मोहम्मद यूनुस खुद उसके जनाजे में पहुंचे। शोक व्यक्त किया, तस्वीरें खिंचवाईं और यहां तक कि यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का नामकरण हादी के नाम पर कर दिया। जब बात हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या की आई, तो यूनुस असंवेदनशील बन गए। उन्होंने उसके परिवार से मिलने की जहमत तक नहीं उठाई। उन्होंने केवल अपने शिक्षा सलाहकार को भेजकर औपचारिकता निभा दी। यही दो तस्वीरें एक में यूनुस खुद मौजूद और दूसरी में उनका प्रतिनिधि उनकी दोहरी नीति का सबसे बड़ा सबूत बन गईं। एक राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख से देश की जनता को यह अपेक्षा होती है कि वह धर्म, जाति और वोट बैंक से ऊपर उठकर पीड़ितों के साथ खड़ा हो। लेकिन, यूनुस के व्यवहार ने यह साफ कर दिया कि बांग्लादेश में आज इंसाफ नहीं, बल्कि पहचान के आधार पर संवेदना बांटी जा रही है। हिंदू परिवार के लिए दूरी और औपचारिकता, जबकि मुस्लिम पीड़ित के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति यही है यूनुस का दोगलापन। दीपू चंद्र दास की हत्या में करीब 140 लोगों की भीड़ शामिल बताई जाती है, लेकिन एफआईआर में महज 6 नाम दर्ज हुए। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि एक सोच का प्रतिबिंब है। दूसरी ओर, उस्मान हादी की हत्या के बाद पूरे सिस्टम की सक्रियता दिखाई दी। यह अंतर सवाल खड़ा करता है कि क्या बांग्लादेश में कानून सभी के लिए समान है यूनुस को अक्सर उनके नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के कारण मानवीय चेहरा बताया जाता रहा है, लेकिन आज वही व्यक्ति कट्टरपंथ के खिलाफ खड़ा दिखने के बजाय उस पर चुप्पी साध कर उसे बढ़ाता नजर आता है। उनके शासनकाल में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों के आंकड़े लगातार बढ़े हैं। मंदिरों की तोड़फोड़, घरों में आगजनी और हत्याएं आम हो गई हैं। अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टें भी चेतावनी दे चुकी हैं कि कट्टरपंथी तत्व कानून-व्यवस्था की कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। यहां एक अहम सवाल उठता है अगर किसी व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिला हो, तो क्या वह वापस लिया जा सकता है इसका जवाब साफ है- नहीं। नोबेल फाउंडेशन के नियमों के अनुसार, एक बार दिया गया नोबेल पुरस्कार वापस नहीं लिया जा सकता, चाहे बाद में उस व्यक्ति के आचरण पर कितने ही गंभीर सवाल क्यों न उठें। इतिहास में कई उदाहरण हैं, जहां नोबेल विजेताओं के फैसलों या नीतियों की आलोचना हुई, लेकिन पुरस्कार कभी वापस नहीं हुआ। यानी यूनुस का नोबेल उनके पास रहेगा, भले ही अब उनकी राजनीति और कार्यों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मगर यहां सवाल पुरस्कार का नहीं, नैतिकता का है। क्या एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता से यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि वह हर पीड़ित के साथ समान व्यवहार करेगा क्या शांति का मतलब सिर्फ एक समुदाय तक सीमित रह गया है आज बांग्लादेश जल रहा है सिर्फ हिंदू नहीं, मुसलमान भी। कट्टरपंथ की आग किसी एक धर्म को नहीं छोड़ती। लेकिन, जब सत्ता ही तटस्थ न रहे, तो आग और भड़कती है। यूनुस का दोगलापन यही साबित करता है कि बांग्लादेश अब संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान वाला बांग्लादेश नहीं रहा और यही सबसे बड़ी चिंता है।

सामाजिक सुरक्षा का सवाल

यह ठीक है कि खाने-पीने की सामग्री के साथ अन्य सामान की डिलीवरी करने वाले अस्थायी कामगारों यानी गिग वर्करों की ओर देश का ध्यान गया, लेकिन ऐसा तब हो पाया, जब विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले इन लोगों को हड़ताल करनी पड़ी। गिग वर्करों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिए, क्योंकि उनकी कार्यदशाएं काफी कठोर हैं। आज जब क्विक कामर्स और फूड डिलीवरी कंपनियों का कारोबार बढ़ता जा रहा है, तब उनके लिए काम की बेहतर दशाएं सुनिश्चित की ही जानी चाहिए। यह संतोषजनक तो है कि केंद्र सरकार गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा का एक प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन बात तब बनेगी, जब इस प्रस्ताव के प्रविधानों को सही तरह लागू करने में सफलता मिलेगी। गिग वर्करों की समस्या यह है कि वे जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं, उनके वे कर्मचारी नहीं माने जाते। उनके काम के घंटे भी तय नहीं हैं। वे जितने समय काम करते हैं, उतने ही वक्त का उन्हें पैसा मिलता है। उन्हें कभी भी काम से हटाया जा सकता है। चूंकि उनकी स्थिति असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसी है, इसलिए उनकी कार्यदशाओं पर किसी का ध्यान नहीं है। यदि उनके साथ कुछ अनहोनी जाए तो संबंधित कंपनी की जवाबदेही नहीं होती। यह समझा जाना चाहिए कि गिग वर्कर आधारित उद्योग बेहतर नियमन की मांग कर रहा है। गिग वर्करों की समस्याएं इसलिए और बढ़ गई हैं, क्योंकि दस मिनट में भी सामान की डिलीवरी करने का चलन जोर पकड़ गया है। इस चलन पर फिर से विचार होना चाहिए, क्योंकि इससे गिग वर्करों के साथ दुर्घटनाएं होने का जोखिम बढ़ गया है। कई बार गिग वर्कर शीघ्र सामान पहुंचाने के फेर में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते दिखते हैं। निःसंदेह गिग वर्कर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें मिलने वाले मेहनताने को आकर्षक नहीं कहा जा सकता।

Printed and Published by Fahim Akhtar on behalf of MAA MEDIA VENTURE and Printed at SHIVA SAI PUBLICATION PVT.LTD, Ratu, Kathitand, Near Tender Bagicha, H.P. Petrol Pump P.O.+P.S.- Ratu, Dist.-Ranchi, 835222, Jharkhand And Published at Roshpa Tower, 5th Floor, Main Road, Ranchi, Jharkhand-834001. R.N.I Number - JHABIL/2022/85899, Editor- Fahim Akhtar. Mob - 9431311669, E-mail : thephotonnewsjharkhand@gmail.com

The case for consensus politics in 2026

After more than a quarter century of confrontational politics, the deteriorating security and economic environment around India calls for more consensual politics. When external challenges to India pose serious threats, it is important to close ranks internally. More so when internal political, economic and social challenges are also multiplying.The BJP has had two terms of majority rule, and even this time, despite being reduced to 240 seats from 303 in the 2024 General Election, it has re-consolidated political power by winning many Assembly elections after June 2024. However, it has not moved significantly towards building consensus on crucial issues. 2026 is the ideal year in which to begin this process as most of the state Assembly elections due this year — Assam, Kerala, Tamil Nadu and West Bengal — will not have a significant impact on its predominance.Internally, we face huge economic and political challenges. They include the coming Census and delimitation of parliamentary constituencies, the need to reduce communal antagonisms, legislating economic reforms (especially in agriculture) to speed up growth with jobs, ensuring a fairer distribution of tax and other resources between rich and poor states and dousing down regional, linguistic and other animosities.The rise and rise of the BJP, first with the Vajpayee-led coalition, and since 2014, under Narendra Modi, is making political consensus harder as parties seeking to regain relevance feel compelled to oppose everything the government does.The fact that Parliament seldom functions in a democratic manner, with the government repeatedly having to push through important legislation without much discussion, is indicative of fraying political tempers and increasing confrontations over everything. This cannot be good for the country against the backdrop of the challenges we face externally and internally, both economically and geopolitically.In its third term, the BJP has occasionally tried to use a bit more of consensus — we have seen some contentious Bills (like Waqf Amendments, for example) being sent to joint parliamentary panels — but its decisive victories in Haryana, Maharashtra, Delhi and Bihar now give it less reason to build consensus on contentious issues. More so since the NDA's position in the Rajya Sabha is more favourable to the government than before.

However, this would be short-sighted on the part of the BJP. It does not mean everything has to be done by consensus — the Budget and some economic policies, for example, can be exceptions — but in most other cases, the government should seek as wide a consensus as possible so that there is less internal heartburn. An internal consensus is not going to be easy when caste- and community-based polarisations are a reality, with the minorities broadly backing opposition parties and significant chunks of Hindus shifting towards the BJP after 2014. But this is precisely why the BJP has to look beyond mere electoral gains.

It has to begin discussions with major opposition parties on everything — from electoral and economic reforms to delimitation of constituencies and sharing of resources between the Centre, states and local bodies. The last is particularly important as our cities, which ought to be drivers of growth and jobs, are poorly governed and disempowered. Air and water quality, garbage management and traffic congestion are only some of the problems cities are yet to find effective solutions to. This happens because state-level politicians use urban wealth to accumulate personal riches and build up electoral muscle, starving cities of resources for effective governance. These are not problems that can be solved only through finance commission devolutions, which, anyway, tend to be influenced by Union government priorities.

Reforms must go the distance

Onus on the govt to prioritise deregulation so that the high growth path is sustained

It's time to ring in everything new. This is true of the economy too. The masses are hoping for a better life that goes beyond the basics of food, shelter and clothing. Viksit Bharat — a developed economy — is now the dream of large swathes of a population that seeks ease of living.The prospect of achieving it is brighter than ever right now, given that economic growth has been rising more rapidly than predicted in the past year. The 7.4, 7.8 and 8.2 per cent growth rates recorded successively in the first three quarters of the calendar year give rise to optimism that a higher growth path is now on the horizon.Yet, the outlook for this year is not uniformly positive. Much will depend on the trajectory of geopolitical tensions as well as the fate of bilateral trade pacts being negotiated with the US and the European Union (EU).As far as the Russia-Ukraine war is concerned, there is a glimmer of hope for a peaceful resolution to the conflict. However, numerous stakeholders have to agree on the terms and conditions before concrete progress can be made. This includes not just the principal players — Ukraine and Russia — but also the US, which is seeking to broker a truce, as well as European nations such as the UK, France and Germany. In case these efforts succeed, life will be easier for a country like India which continues to import Russian oil despite punitive American tariffs.Even without peace on this front, considerable strain on the economy will be eased by finalising trade agreements with the US and the EU. The volume of bilateral trade annually is roughly at the same level with both entities — about $132 billion (India-US) and $136 billion (India-EU). The difference is that US tariffs have been hiked to a mind-boggling 50 per cent by President Donald Trump, ostensibly on account of India's oil purchases from Russia.While the negotiations are still underway, latest trade data has shown a surprising surge in exports to the US. These were projected to decline after the tariff blow. Instead, exports to the US market rose by over 22 per cent in November, while overall exports also recorded a 15 per cent spurt. In other words, efforts to diversify export markets have succeeded more quickly than expected, especially in areas where North America has been viewed as a focal market.Exports of gems and jewellery goods, for instance, have risen by 28 per cent during the same month, according to Commerce Ministry data. This means that concerns over widespread job losses in this labour-intensive sector can be laid to rest.

At the same time, it cannot be denied that the speedy conclusion of the India-US trade pact will bring relief to several export industries that rely on supply to the world's biggest market. Europe is an equally significant destination, but non-tariff barriers — especially environment-linked regulations — could affect the pace of export growth. It is time, however, for the EU to recognise that its drive to deepen relations with India is dependent on greater flexibility on the trade front. It must draw a lesson from the UK, which wrapped up a mutually advantageous trade deal by looking at the larger picture rather than retaining a rigid stance.

The outlook on trade is inextricably linked to the rupee, which is now at its lowest level against the dollar. Contrary to worries being voiced over this issue, the rapid currency depreciation has come as a shot in the arm for exporters at a time of declining competitiveness in global markets due to tariff and non-tariff barriers. The precipitous fall of the rupee over the past year will definitely raise the cost of imports, but the current account deficit has been contained at 1.3 per cent of the GDP compared to 2.2 per cent a year ago. The positives of a declining rupee clearly remain greater than the negatives.China has shown the way in boosting competitiveness of its exports by currency depreciation over the years. Thus, a sanguine approach should be taken to any further fall of the rupee in 2026. The Reserve Bank of India needs to ensure that the fall is not too rapid and should avoid drastic measures to prop up the currency.The rupee depreciation has been accompanied by a flight of foreign capital from the stock markets. Net selling by foreign portfolio investors (FPIs) is reported to have been the highest in a calendar year. In contrast, domestic investors have taken up the slack, ensuring that stock markets have been more reflective of the actual state of the economy. Despite the sell-off of FPIs in response to better valuations elsewhere, the economy has been going through a Goldilocks period with multiple elements supporting higher growth.A significant aspect has been the control on inflation while global crude oil prices have remained soft, ensuring that the import bill is kept in check. Revenue collections have continued to mount, even as both exports and industrial growth are showing an uptick.There is every reason to believe that these trends will continue in 2026. The doom and gloom scenario that was prevalent after Trump's imposition of punitive tariffs has been replaced by the recognition of enhanced resilience in the economy in recent times. This has been aided by the reforms in the Goods and Services Tax (GST) that prompted a spurt in consumption during the festival season. The hope that this would spark a virtuous cycle of investments has grown deeper with industrial production rising in November to the highest level in two years.

The economy has thus moved into the new year with the expectation that the momentum of the past 12 months is likely to continue at the same pace. It is now for the government to use this environment to push through much-needed reforms in terms of deregulation so that the high growth path is sustained.

Gig workers

Their demands need serious consideration

The strike by a section of gig workers on New Year's Eve may not have caused major disruptions across the country, but it has done enough to turn the spotlight on their key demands — better payouts and improved working conditions. The contrast could not have been starker: leading food delivery aggregators recorded a massive surge in orders on December 31, even as exhausted bikers aired their myriad grievances. Gig workers — those who make a living outside the traditional employer-employee ambit — have become integral to urban convenience. With over 12.7 million such workers in India today — the number is projected to reach 23.5 million by 2030 — the sector is no longer peripheral. Yet, for many delivery partners, the promise of flexibility has been eclipsed by falling payouts, algorithmic penalties, long working hours and the constant pressure of speed-driven models like 10-minute deliveries.The muted impact of the strike reveals a harsh truth: the gig economy is now so deeply embedded in daily life that platforms can often ride out worker protests with incentives and surge pay. However, workers' claims — earning Rs 700-800 after 14-hour workdays, being denied insurance after accidents — point to structural flaws that incentives alone cannot fix.

This is where the recent labour reforms assume critical importance. For the first time, gig and platform workers have been formally defined under the law. Mandatory contributions of 1-2% of aggregator turnover to a social security fund and Aadhaar-linked universal account numbers signal an overdue shift towards legal recognition. However, implementation will determine whether these reforms become transformative or merely symbolic. Notably, MPs such as Raghav Chadha and Manoj Kumar Jha have flagged the exploitation of gig workers. India's gig economy has shown its prowess to generate jobs. Its success should ultimately be measured not just in terms of the minutes saved, but also the gains shared and jobs as well as lives made less insecure.

The ethics of attention on ordinary lives

Perfect Family and The Great Shamsuddin Family remind us that in an age saturated with noise, the most radical act may be to look closely at what lies in front. As the dramas refuse to provide redemption or spectacle, the viewer is forced to recognise social realities

Cinema is a medium made for spectacular, extraordinary and even grotesque narratives. In contrast, what is striking about Perfect Family, a web series produced by Pankaj Tripathi, and Anusha Rizvi's film The Great Shamsuddin Family is that they turn their gaze towards a realm often neglected in cinema—the uncelebrated ordinariness of everyday lives, marked by pain, endurance and muted anguish.

In foregrounding this ordinariness, both these works compel us to train our attention to images we tend to unsee and glaze over. In depicting conflict and suffering without theatrical escalation, these works unsettle us with issues we are deeply familiar with. These narratives mirror a social reality we do not always acknowledge, making us realise beautifully how the ordinary, when honestly rendered, can be profoundly disturbing.

Perfect Family exemplifies this aesthetic and ethical choice. Whatever Tripathi's characters lack in overt theatrical intensity, he allows them to compensate for by showing the rhythms of a life shaped by small accommodations, unspoken contestations and daily negotiations. Gestures and even silences acquire meaning as much as the words uttered. Witnessing the emotional economy of a family that appears functional, even content, one realises that the missed conversations, deferred desires, fragile compromises have quietly fractured it. I was impressed that the revelations in the series were not dramatic, yet the 'perfection' of the family is exposed as a social performance sustained through denial. We often mistake endurance for genuine harmony.Anusha Rizvi's The Great Shamsuddin Family operates through a similar trope, though its political implications are more explicit. The members of the Shamsuddin family are neither heroic victims nor symbolic constructs designed to elicit easy empathy. They are ordinary, but in the most unsettling sense. I found it unsettling because they endure, adapt and persist without the promise of transformation. Their lives unfold within systems that constrain choice while demanding compliance. Surviving is shown to require a form of labour even when no path towards liberation might be available.What binds these two works is their refusal to aestheticise suffering or romanticise resilience. Their narratives dwell in a moral grey zone where dignity is negotiated daily. Even ethical clarity is compromised by necessity. The viewer is denied the comfort of catharsis and, as a result, these works compel a more honest engagement with social reality experienced intimately. We are not allowed to leave reassured by redemption or uplifted by spectacle; we are burdened by recognition.

The images these works present are uncomfortably close to home. They mirror lives that resemble our own or those we witness daily without realising. Cramped living rooms, hesitant conversations, humiliation endured are shown as structural features of our society organised around inequality and silence. As the audience, we are called to confront our own complicity in normalising this unequal and unjust order. The discomfort these works generate is the source of their moral force.In this sense, both works challenge what may be called the politics of visibility in contemporary cinema. Visibility is often mistaken for representation, but representation itself can become another form of erasure when it relies on spectacle or over-simplified exposure. Rizvi and Tripathi seem to be rooting for sustained attention and to be able to resist the impulse to categorise characters neatly as victims or villains. This resistance makes these works significant because they come at a time when films rarely provide an ethical compass in our society, which is paradoxically reeling from deepening polarisation while it's dangerously fatigued by it.I also notice that both narratives unfold slowly, refusing the accelerated pacing that dominates films these days. The slow pacing mirrored the lived temporality of waiting—for work, recognition, relief, or change that may perhaps never arrive. This is perhaps what allowed for giving importance to lives that are otherwise dismissed as uneventful, unproductive or inconsequential.From an analytical perspective, these works can be read through the lens of everyday life theory, according to which the quotidian is a site where power is both reproduced and subtly contested. The ordinary, far from being apolitical, is where social norms are internalised, negotiated and sometimes resisted. In The Great Shamsuddin Family, moments of domestic routine reveal the pressures of communal identity, surveillance and economic precarity. In Perfect Family, rituals of middle-class respectability expose the emotional costs of conformity and repression. These ethically-charged negotiations are, of course, a more accurate depiction of lived realities than moments of dramatic rupture that stories tend to be about.

After watching these works, what lingered was a bit of ache, not some striking image or a line of dialogue. It was the ache of seeing lives reduced to footnotes in national narratives of progress and pride. It was the ache of realising how easily ordinariness becomes a justification for neglect.Ultimately, Perfect Family and The Great Shamsuddin Family remind us that in an age saturated with noise and spectacle, the most radical act may be to look steadily at what lies before us with full attention. They insist that dignity does not always announce itself, and that injustice often resides not in dramatic cruelty but in routine indifference. In doing so, they reclaim cinema's ethical vocation, which is not merely to entertain or provoke, but to bear witness and to lead to contemplation.These works do not ask us to pity their characters; they ask us to consider whether we see our own reflection in their lives. Recognition, unlike sympathy, demands both empathy and accountability. To see these lives clearly is to accept that the ordinary is not outside politics; it is where politics lives most intimately. Rizvi and Tripathi have done a great service by disrupting our habits of seeing, reminding us that what we choose not to acknowledge often defines who we are.

Inside the gig economy: The real cost of your 10-minute deliveries

New Delhi.(Agency)

On New Year's Eve, as cities lit up and orders surged, India's gig economy found itself at the centre of a public confrontation. Delivery partners across platforms called for protests over pay, safety, and working conditions, even as quick-commerce and food delivery apps raced to meet peak demand.For consumers, the debate briefly interrupted the promise of 10-minute groceries and late-night meals. For workers, it reopened a deeper question: what does convenience really cost, and who bears it?The flashpoint came as delivery partners associated with quick commerce platforms such as Blinkit, Instamart, and Zepto raised concerns over falling incentives, algorithmic pressure, and road safety.Worker groups argued that ultra-fast delivery timelines incentivise risk-taking, while the absence of guaranteed wages or job security leaves riders exposed to sudden loss of income through account deactivations.

OTHER SIDE OF THE STORY

The protests were countered by a strong defence from Deepinder Goyal, founder and CEO of Eternal, the parent company of Zomato and Blinkit. In a series of posts on X, Goyal said operations on New Year's Eve were unaffected by strike calls, with more than 4.5 lakh delivery partners completing over 75 lakh orders for 63 lakh customers—an all-time high.

He credited support from local law enforcement for keeping operations running and said no additional incentives were offered beyond what is typically seen on New Year's Eve.More broadly, Goyal rejected the idea that the gig economy is inherently exploitative, arguing that banning or over-regulating platform work would erase livelihoods rather than fix inequality.

According to Goyal, the discomfort around gig work stems from visibility. The gig economy, he argued, has forced a direct confrontation between the consuming class and the working poor.

"The doorbell is not the problem," he wrote. "The question is what we do after opening the door."

GIG ECONOMY DILEMMA

India's gig economy has expanded far faster than the laws meant to regulate it. Government estimates cited in labour ministry documents and policy reports suggest India has over nearly 80 lakh gig and platform workers, a number expected to rise sharply as food delivery, ride-hailing, and quick-commerce platforms continue to scale.By the end of this decade, gig workers are projected to form a sizeable share of India's non-agricultural workforce.

A NITI Aayog study on platform work has highlighted the high income volatility faced by gig workers. While gross monthly earnings can appear stable during peak demand periods, net incomes fluctuate significantly once fuel costs, vehicle rentals, downtime and frequent changes in incentive structures are factored in.The report warned that the absence of guaranteed wages or predictable working hours makes gig work especially vulnerable to economic shocks.

FPIs pull out 7,608 crore from Indian equities in just 2 days of Jan

New Delhi.(Agency)

Foreign portfolio investors have started 2026 on a cautious note, extending their selling streak from last year by withdrawing Rs 7,608 crore ($846 million) from Indian equities in the first two trading sessions of January.The withdrawal of funds followed the largest outflow of ?1.66 trillion ($18.9 billion) recorded in 2025, triggered by volatile currency movements, global trade tensions and concerns over potential US tariffs, and stretched market valuations.

This sustained selling pressure by foreign portfolio investors (FPIs) has significantly contributed to the nearly 5 per cent depreciation of the rupee against the dollar during 2025.However, market experts believe the tide could turn in 2026.

VK Vijayakumar, Chief Investment Strategist at Geojit Investments, said the year is likely to witness a shift in FPI strategy, as improving domestic fundamentals may start attracting net foreign inflows.A robust GDP growth and the prospects of a recovery in corporate earnings bode well for positive FPI flows in the coming months, he added.

Echoing similar views, Vaqarjaved Khan, Senior Fundamental Analyst at Angel One, said normalisation in India-US trade relations, a benign global interest rate environment and stability in the USD-INR pair could create a favourable backdrop for foreign investors.He noted that equity valuations have become relatively comforting compared to last year, which could further support a revival in inflows.Despite these positive expectations, FPIs have begun 2026 on a cautious note, and according to data from NSDL, they pulled out nearly Rs 7,608 crore from Indian equities between January 1 and 2.

This trend is not unusual, as foreign investors have historically remained guarded in January, having withdrawn funds in eight out of the past ten years, Khan said.Consequently, FPI flows are likely to remain highly sensitive to global cues and macroeconomic developments. While high valuations were a key concern over the past year, that pressure appears to have eased for now, offering some room for optimism going ahead, he added.

Macroeconomic data, FII trading activity likely to drive markets this week

New Delhi.(Agency)

Macroeconomic data announcements, global trends and trading activity of foreign investors would be major driving factors for market movement this week, analysts said.Unabated capital infusion by domestic institutional investors have supported the positive trend in the stock market last week, traders said."This week is expected to be data-heavy, both domestically and globally, as markets enter the early phase of the earnings season. In India, investors will track the final readings of the HSBC Services PMI (Purchasing Managers' Index) and Composite PMI. Globally, key US macro data and releases from China will be closely watched for signals on growth, demand, and inflation trends," Ajit Mishra -- SVP, Research, Religare Broking Ltd -- said.

Last week, the BSE benchmark jumped 720.56 points, or 0.84 per cent, and the NSE Nifty climbed 286.25 points, or 1.09 per cent. The 50-share Nifty hit its all-time peak of 26,340 on Friday."Market's focus is set to shift toward the Q3 earnings season, with traders likely to build positions selectively ahead of results from key index heavyweights. Domestically, Services and Composite PMI data will provide further insights into business momentum and employment trends...," Ponmudi R, CEO -- Enrich Money, an online trading and wealth tech firm, said.Globally, attention will remain on US non-farm payrolls and unemployment data, which could shape expectations around the Federal Reserve's rate path and overall risk appetite, he said.

SUV demand holds steady in used market despite GST-led price cuts

Mumbai.(Agency)

Despite small cars becoming affordable under the revised GST regime, India's used-car market continues to tilt decisively towards SUVs, which are clocking faster inventory turnover and holding on to stronger residual values than hatchbacks, according to industry executives. Data from used-car platforms suggest that buyer preferences have remained broadly stable post-GST, with SUVs retaining their dominance even as price adjustments played out across segments. While hatchbacks saw a moderation of about 21 per cent following pricing changes, SUVs recorded a sharper adjustment of around 29 per cent but managed to preserve demand more effectively. "Buyer preference continues to favour larger vehicles, reflecting the importance placed on space, comfort and road presence," said Abhishek Patodia, President – Used Cars at CarWale, adding that SUVs continue to move faster in the secondary market despite higher ticket sizes. Executives point out that SUVs offer a blend of aspiration and practicality that resonates strongly with used-car buyers. Many vehicles entering the resale pool are relatively new and well-equipped, allowing customers to access premium features at attractive prices. This has helped SUVs and premium sedans maintain stronger residual values, while hatchbacks have needed steeper pricing adjustments to sustain transaction momentum. "SUVs continue to witness faster inventory turnover and stronger residual values, reflecting sustained buyer confidence even at higher price levels," Patodia added.Pricing dynamics also vary by geography. As per CarWale's data, the top 30 cities have seen price adjustments of roughly 28 per cent, compared with about 17 per cent in smaller markets, driven largely by differences in demand composition rather than structural shifts.

Venezuela Crisis May Drive Safe-Haven Demand For Gold, Silver

Investor focus has shifted sharply to safe-haven assets like gold and silver, while oil prices are expected to move higher amid fears of supply disruptions.

New Delhi.(Agency)

Global markets are set to begin the first full trading week of 2026 on edge after a major geopolitical shock involving Venezuela, a country with the world's largest oil reserves. Investor focus has shifted sharply to safe-haven assets like gold and silver, while oil prices are expected to move higher amid fears of supply disruptionsMarkets turned cautious after US forces captured Venezuelan President Nicolás Maduro and his wife during a military operation over the weekend.The US has charged them with drug trafficking, escalating tensions in an already fragile region. The development is being seen as a major geopolitical event that could unsettle energy markets and increase demand for safe assets at the start of the year.Gold began 2026 on a strong note, rising over 1 percent to trade near USD

4,370 per ounce, supported by geopolitical risks and expectations that US interest rates may ease later this year.Silver also gained more than 2 per cent, moving close to USD 73 per ounce, helped by dollar softness, supply deficits and rising industrial demand.However, on a weekly basis, both metals saw profit booking after last year's sharp rally. COMEX gold slipped nearly 5 per cent, while silver dropped over 8 percent as higher margin requirements forced some traders to cut positions.In the domestic market, MCX Gold futures saw a sharp fall at the start of the week, marking their steepest single-day decline in two months.Since then, prices have moved in a narrow range. Analysts say gold may recover if prices hold above key support levels, but a sustained fall below these levels could trigger further correction.Oil prices also opened the year on a positive note, with WTI crude ending the week near USD 57.3 per barrel. Oil had a tough 2025, falling nearly 20 per cent due to oversupply concerns.However, rising tensions involving Venezuela and renewed Russia–Ukraine strikes on energy infrastructure have increased the risk premium.Markets are now watching the upcoming OPEC+ meeting on January 4, where the group is widely expected to maintain its pause on additional supply increases.Base metals showed strength at the start of the year, extending their year-end momentum. Copper prices moved closer to record highs, while aluminium crossed USD 3,000 per tonne for the first time since 2022. Strong demand on Asian exchanges helped support prices globally.

Devyani, Saphhire merger: A recipe for growth

New Delhi.(Agency)

The merger of two leading brands -- Sapphire Foods India Ltd (SFIL) and Devyani International Ltd (DIL) - is all set to create a fast-food giant with more than 3,000 stores, a consolidated turnover of more than Rs 7,800 crore and operations in markets such as India, Nigeria, Nepal, Thailand and Sri Lanka. Besides retailing the American multinational fast-food corporation Yum! Brands' offerings such as KFC, Pizza Hut and Taco Bell, the merged entity will also hold licenses for other global QSR brands, including Costa Coffee, Tea Live, New York Fries, and Sanook Kitchen, in their respective markets.

Sapphire will merge with Devyani, consolidating the Indian franchise operations of Yum! Brands-owned chains under one listed entity. As part of the deal, DIL will issue 177 shares for every 100 shares held in SFIL. Once the merger is complete, Sapphire shareholders will cease to hold SFIL shares and will instead receive Devyani International shares in the specified swap ratio.

Rationale for merger

The merger between two large players is happening at a time when QSR chains in India are witnessing sluggish growth, lower margins, and almost flat demand growth as consumers are holding on to discretionary spending. QSR sales are down also due to intense competition (cloud kitchens, food delivery apps like Zomato/Swiggy) and evolving consumer tastes. This has led to softer demand and fragmented market share, with companies resorting to discounts to maintain volumes which in turn is impacting profitability.

From McDonald's, Burger King, Pizza Hut to KFC, same-store sales are declining and footfalls are falling. Sapphire Foods and Devyani International's recent quarterly earnings numbers also indicate a growing concern. DIL slipped into the red in the September quarter (Q2FY26), posting a net loss of Rs 21.8 crore, compared with a marginal profit of Rs 0.02 crore in the same period last year. The company's expansion also slowed as it added only 39 net new stores during the quarter, taking the total store count to 2,184 at the end of September 2025. The Average Daily Sales (ADS) for Devyani stood at Rs 94,000 per store in March 2025, down from Rs 105,000 per store a year ago, translating into a 6.4% drop in Same Store Sales Growth.

Sapphire Foods also reported a net loss of Rs 12.7 crore for the quarter ended September 2025, widening from a loss of Rs 3 crore in the same period last year. Revenue rose by just 7% year-on-year to Rs 742.7 crore. In FY25, average daily sales from KFC stores for Sapphire Foods came down to Rs 114,000 from Rs 125,000 a year ago. For Pizza Hut stores, the average daily sales remained stagnant at Rs 46,000. In FY23, the average sales were Rs 58,000.

Aravallis, a new turn in the ecology battle

New Delhi.(Agency)

There are some twists in the legal battle to save the Aravalli Hills. In a surprise development, on 20 November, the Supreme Court accepted a special committee's definition that only hills above a 100-meter elevation above the surrounding land would be recognized as protected 'hills'.Following an outcry from the scientist community and grassroot movements, a vacation bench of the apex court, on 29 December, last year, paused its own judgement and said the issue warranted re-examination.By and large, the higher courts, especially the Supreme Court, have been consistent sentinels against ecological degradation. The 20 November judgment marks a change in that approach when a bench led by the former Chief Justice of India BR Gavai signaled mining and infrastructure development would take precedence over environmental defenses.The flip side has been greater citizen activism, especially from urban areas; something the government had not bargained for. When pausing the November judgment, Chief Justice Surya Kant mentioned public dissent as one of the factors that had nudged the court into staying its earlier judgment.

The stakes are highThe possible destruction of the Aravalli Range is a big deal. It is one of the oldest mountain systems, stretching through 800 kilometers covering the 4 states of Delhi, Haryana, Rajasthan and Gujarat. For eons it has formed a crucial ecological barrier separating the arid sands of the Thar Desert from the fertile plains in the south. As an acquifier it has prevented desertification while creating a vast green lung for the region.

For an old mountain system that has low peaks, the 100-meter height definition was a clever death sentence. The government's own Forest Survey of India (FSI) report has noted that of the 12,081 documented Aravalli hills of heights measuring 20 meters or more, only 1,048, or just 8.7% exceed 100 meters.Another survey by the Ashoka Trust for Research in Ecology and the Environment (ATREE), says more than 70 per cent of Rajasthan's current Aravallis — covering 18,092 villages and spanning 83,380 square kilometres — are likely to be delisted under the new notification. In the case of Gujarat and Haryana, 82% of the hills risk denotification, while Delhi may lose its entire Aravalli buffer.The rolling back of the protection the Aravalli Hills, enjoyed under the old Environment Protection Act and other state legislation, isn't an isolated aberration.The government had set their eyes on the mining deposits in the region particularly atomic minerals such as uranium and thorium, as well as rare earth elements such as tantalum and tungsten.The Union government has recently in January 2025 launched the National Critical Mineral Mission aimed at developing "sustainable, resilient and self-reliant" mineral supply chains. No doubt, this is of economic importance. However, as the definition and the future of the Aravalli Hills goes back for re-examination.

India's Economic Interests In Venezuela Minimal, Not Dependent For Oil: Industry Watchers

The bilateral trade between the nations was USD 1.175 billion in 2023-24, according to information available on the website of the Embassy of India in Caracas.

New Delhi.(Agency)

As several countries across the globe criticised the US military attack on Venezuela on Saturday, industry watchers said that India's economic interests in the South American country are minimal and it is not dependent on Venezuela for oil.The bilateral trade between the nations was USD 1.175 billion in 2023-24, according to information available on the website of the Embassy of India in Caracas.The main items of India's exports to Venezuela are mineral fuels and oils and products of their distillation; bituminous substances, pharmaceutical products, cotton, nuclear reactors, boilers, machinery and mechanical appliances,

electrical machinery and equipment; sound recorders and reproducers, television image and sound recorders and reproducers, articles of apparel and clothing accessories and miscellaneous chemical products.According to industry experts, the bilateral trade is very minimal, and the country is now dependent on Venezuela for crude oil imports.The main items of India's imports from Venezuela are mineral fuels and oils and products of their distillation, bituminous substances, mineral waxes, iron and steel, aluminium, edible vegetables and certain roots and tubers, copper and articles thereof, lead and articles thereof, zinc and articles thereof, wood and articles of wood, among others, according to the Embassy.

ONGC Videsh Limited (OVL) and Corporacion Venezolana del Petroleo (CVP) (subsidiary of PdVSA) have a joint venture called "PetroleraIndovenezolana SA" for the production and exploration of oil in the San Cristobal field, in which OVL has a 40 per cent stake, while PDVSA has 60 per cent of the remaining stake.

The OVL investment in the San Cristobal project is approximately USD 200 million.An international consortium comprising ONGC Videsh Limited (OVL), Indian Oil Corporation (IOC), Oil India Limited (OIL), Repsol of Spain and Petronas of Malaysia was declared the winner of an international bidding process in April 2008 to develop a multi-million-dollar oil project integrated in Carabobo in the Orinoco belt of Venezuela.

Meanwhile, Venezuela Vice President Delcy Rodriguez on Saturday said that the whereabouts of the country's President Nicolas Maduro and his wife, Cilia Flores, are unknown following the US attacks in Caracas, Miranda, Aragua and La Guaira in the early hours of Saturday (local time).

Earlier, US President Donald Trump claimed that the Venezuelan President and his wife had been "captured" and "flown out" of the country.

Exercise extreme caution: India's advisory for citizens in Venezuela after US strikes

India has advised its nationals in Venezuela to exercise extreme caution and restrict movement following US military strikes and escalating tensions after US President Donald Trump claimed Venezuelan President Nicolas Maduro was captured.

New Delhi.(Agency)

India on Saturday issued an advisory asking its nationals in Venezuela to exercise "extreme caution" and restrict their movements following US military strikes on the country and claims by US President Donald Trump that Venezuelan President Nicolas Maduro and his wife have been captured by US forces.In a press release, the Ministry of External Affairs (MEA) said all Indians currently in Venezuela should remain in close contact with the Embassy of India in Caracas. "All Indians who are in Venezuela for any reason are advised to exercise extreme caution, restrict their movements, and remain in contact with Embassy of India in Caracas," the statement said.

The advisory shared the embassy's email address, cons.caracas@mea.gov.in, and an emergency phone number, +58-412-9584288, also available for WhatsApp calls.

The advisory comes amid rapidly escalating tensions in Venezuela after Trump claimed that US forces carried out "large-scale airstrikes" on Caracas and captured Maduro and his wife, Cilia Flores, during an early-morning operation.

Trump said the couple had been taken into US custody and flown out of the country, with Maduro facing charges in Manhattan federal court, including narco-terrorism conspiracy, cocaine importation conspiracy and weapons-related offences.While Venezuelan authorities have not acknowledged Trump's claims, multiple explosions were reported in Caracas in the early hours of Saturday, with residents describing low-flying aircraft, fires, power outages and thick plumes of smoke over parts of the capital.

VENEZUELA MOBILISES FORCES, DECLARES EMERGENCY

Venezuelan Defence Minister Vladimir Padrino Lopez announced the deployment of military forces across the country shortly after the strikes, calling the US action "the worst aggression" Venezuela has ever faced. He urged unity and calm, warning against unrest and disorder, and said all armed forces would be mobilised.

Venezuela's government accused Washington of attacking civilian and military facilities and declared a "state of external disturbance," a form of emergency rule that expands the role of the armed forces and allows the suspension of certain rights. Authorities also called on supporters to mobilise and take to the streets.

RISING UNCERTAINTY FOR FOREIGNERS IN VENEZUELA

The MEA advisory reflects growing uncertainty on the ground as the US steps up pressure on Maduro, whom Washington has accused of running a "narco-state" and facilitating drug trafficking. Trump has said the United States is engaged in an "armed conflict" with drug cartels and has warned repeatedly of military action on Venezuelan soil.

With security conditions volatile and communications disrupted in parts of Caracas, Indian authorities have urged nationals to remain indoors, avoid non-essential travel and stay in touch with the Indian mission for assistance.

Over 130 held last year amid crackdown on visa, passport fraud in Delhi: Police

New Delhi.(Agency)

The Indira Gandhi International Airport unit of the Delhi Police has arrested more than 130 people in 2025 as part of a crackdown on visa and passport frauds, including agents and facilitators allegedly involved in illegal immigration, police said.According to the police, for the first time, investigators have focused on tracing the financial trail linked to such frauds. "The challenge with this was that in most of the cases, a huge part of the money was said to be paid in cash. Yet, there was scope to work on this line of investigation. Working on it, more than 100 bank accounts of the agents have been frozen so far. Assets of the agents, suspected to have been derived from the proceeds of criminal activity, are being identified," said DCP (IGI) Vichitra Veer.

Further, police said 140 lookout circulars (LOCs) were issued in 2025 against absconding accused to prevent them from fleeing abroad. During the year, 119 proclaimed offenders – including accused people wanted in decade-old cases – were also arrested.The airport unit has also intensified action against touts and thefts from passenger baggage and cargo. Police said over 300 cases were registered against touts, leading to the arrest of more than 400 people, while around 60 persons were arrested in cases related to theft from baggage and cargo. Ground-handling staff of airlines were questioned during investigations into baggage thefts.

Rs 50,000 each to first 1,000 retrofitted vehicles: Delhi govt plans incentive to change old cars to EVs

According to officials, the Transport department has also proposed these recommendations in the draft EV Policy 2.0, under which the government is targeting a significant increase of electric vehicles in new vehicle registrations in the coming years.

New Delhi.(Agency)

Don't want to scrap your old car or sell it outside the city? Amid the fight against air pollution, the Delhi government is planning to incentivise retrofitting of old petrol and diesel cars and converting them into electric vehicles (Evs), said officials, adding that the move is expected to encourage more people to use EVs.According to officials, the Transport department has also proposed these recommendations in the draft EV Policy 2.0, under which the government is targeting a significant increase of electric vehicles in new vehicle registrations in the coming years. "Under this proposal, the government is planning to provide an incentive of Rs 50,000 for the first 1,000 old vehicles for retrofitting into EVs. The plan is under consideration,

and a final decision will be taken after Cabinet approval," an official said.

Retrofitting basically allows vehicle owners to remove and replace internal combustion engines (ICEs) with battery-operated electric kits.

However, the proposal has been explored earlier. The previous AAP government also introduced measures to make the retrofitting of vehicles easy, transparent, and accessible to the public. But the plan could not take off as the retrofit kits are costly – one of the key challenges that came in the way of the proposal.

"Many people do not go for retrofitting of vehicles because it is very expensive and comes at different prices for different models. Thus, the government is planning to propose these incentives so that a large number of people can re-use their vehicles instead of scrapping them or selling them at a lower price," said a senior official.

Strict posting rules issued for traffic clerks and ministerial staff in Delhi

New Delhi.(Agency)

The Delhi Police has said that no individual posted as Chittha Munshi (roster clerk), duty officer, BHM, CHM, or MHC (in the traffic division) of any rank or designation engaged in the deployment of staff should continue for more than one year under any circumstances.According to a standing order issued by Delhi Police Commissioner Satish Golcha, after completion of this stint, they should be assigned some field duties and not any static or mud duty in the same setup.

Chittha Munshi should be appointed from the rank of head constable, assistant sub-inspector (ASI), or sub-inspector (SI) (promotee) only. After completing the tenure as Chittha Munshi in a police station, he or she should not remain posted in the same police station or subdivision, the order mentioned.

The ministerial staff posted in sensitive branches such as HAG and the admin branch (HAA) must be strictly rotated after every 2 years and should not be re-posted to the same assignment during their tenure in the same district or unit. In case of transfer to another district or unit, there should be a gap of a minimum of five years before an individual is posted to a similar assignment.An entry should be made in the character rolls and intra-DP bio-data of the staff concerned regarding their posting as Chittha Munshi, duty officer, BHM, CHM, or MHC. Similar entries should be made for ministerial staff posted in branches such as HAG, HAA, HAE, and SIP or for duties involving the purchase of articles, posting, and transfer of staff, the order stated.

All Deputy Commissioners of Police should ensure compliance with the orders. Officers formally inspecting police stations and offices should also check whether these instructions are being implemented. A Police Establishment Board (PEB) is to be established at the district and unit level for intra-district and intra-unit transfers to ensure a transparent and equitable transfer, posting, and rotation policy. The order also stated that police personnel retiring within the next 24 months shall not be transferred in a general transfer.

A sweet deal: Delhi Cabinet nod to free 1 kg packs of sugar every month for AAY beneficiaries

New Delhi.(Agency)

In a major initiative for the poor and marginalised sections of society, the Delhi Cabinet has approved free distribution of sugar to all beneficiaries under the Antyodaya Anna Yojana (AAY). The scheme, to be implemented this month, will be valid till March 2027.

Chief Minister Rekha Gupta said that under this initiative, all AAY beneficiaries in Delhi will be provided 1 kg sugar per month, free of cost, in branded and standardised packets."The initiative marks another concrete step in the Delhi government's pro-poor policies, ensuring both food security and access to quality supplies," she said.

Currently, loose sugar is distributed at fair price shops that often leads to accumulation of dust and moisture, contamination and weighing issues.

Distribution in packets will ensure hygiene, safe storage, ease of handling and accurate measurement, said officials.

As per official estimates, 65,883 AAY families in Delhi will benefit from the scheme, with each eligible household receiving 1 kg sugar per month.Until the finalisation and approval of a new tender for branded packaging, distribution will continue under the existing system to ensure uninterrupted supply to beneficiaries, said officials.

"The Delhi government is working in line with the vision of Prime Minister Narendra Modi, who has consistently placed the welfare of the poor at the centre of governance. The Delhi government remains committed to translating this vision into tangible outcomes through sustained efforts for the upliftment of the poor and disadvantaged," Gupta said.

Admin targeting students over library surveillance protests, claims JNUSU

The FIR relates to protests opposing the installation of facial recognition cameras and magnetic entry gates at the B R Ambedkar Central Library.

New Delhi.(Agency)

The Jawaharlal Nehru University Students' Union said Delhi Police served enquiry notices to current and former union office bearers over protests against surveillance measures in the university library.In an official statement, JNUSU said the notices followed an FIR by the administration against student leaders, including JNUSU president Aditi Mishra, vice president Gopika, general secretary Sunil, joint secretary Danish, and former JNUSU president Nitish Kumar. The FIR relates to protests opposing the installation of facial recognition cameras and magnetic entry gates at the B R Ambedkar Central Library.

Mishra said, "JNUSU office bearers and a former JNUSU president have been called for questioning," describing the move as an attempt to intimidate student representatives.

The union said the notices were issued for raising objections to what it called "invasive surveillance infrastructure" inside the library. It said the administration's actions aimed to silence dissent and restrict voices critical of campus policies.JNUSU added that students have long highlighted the "disastrous condition" of the Central Library, including fund cuts, limited books, inadequate seating, and restricted library hours. "Instead of addressing these demands, the administration spent resources on surveillance measures that infringe on students' privacy," the statement further said."The magnetic entry gates were first installed in August last year without consulting students," it said. Following protests led by the then JNUSU, the gates were removed, and officials promised future decisions would involve student representation.However, the union said the administration reinstalled the gates during JNUSU elections in November 2025, leading to protests, proctorial notices, and police complaints.

What Delhi teacher suspended after sharing WhatsApp video amid row over stray dog issue said in clip

On December 31, Sant Ram was suspended by the Directorate of Education's (DoE) Vigilance Branch.

New Delhi.(Agency)

"Assigning teachers to keep records of stray dogs is not appropriate," Sant Ram, a trained graduate teacher (Hindi) posted at Sarvodaya Bal Vidyalaya (SBV) in West Delhi's Subhash Nagar, is heard saying in a video that he posted on a WhatsApp group for teachers earlier this week. "Whenever the nation has needed us… whether during an emergency or during the COVID-19 pandemic… we have served. But I never imagined that teachers in Delhi would be used for such tasks," the government school teacher further says in the clip, adding that such tasks, with exams round the corner, "doesn't align with the position or dignity" of the teachers.

On December 31, Sant Ram was suspended by the Directorate of Education's (DoE) Vigilance Branch. The suspension order invokes Rule 10(1) of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965, and states that "a disciplinary proceeding… is contemplated" against him, without specifying the charges or reasons.

His suspension came amid a controversy over a directive issued by the DoE on December 5 to educational institutions, including government and private schools, offices and stadiums in the city to nominate a nodal officer to cater to issues related to stray dogs. The directive was issued in compliance with Supreme Court directions on campus safety. Simultaneously, letters were sent to civic and land-owning agencies, including the Municipal Corporation of Delhi (MCD), New Delhi Municipal Council (NDMC), Delhi Cantonment Board (DCB), Sports Authority of India (SAI) and Delhi Development Authority (DDA), to implement safety measures within their jurisdiction.

After the circular was published, however, speculation arose if the school teachers would be deployed to count stray dogs. In response, the DoE issued a press note on December 29, clarifying that no specific duties have been assigned to teachers, countering misinformation circulating in sections of the print media. The row, however, did not end there. Later, the Delhi Police's Cyber Cell registered an FIR following a complaint filed by the DoE regarding an alleged "false, misleading, and malicious" post claiming that "teachers will count stray dogs". This also led to political sparring between the ruling BJP and the AAP.

Sant Ram's video, he told The Indian Express on Saturday, was posted in response to a report about the role of teachers in managing stray dogs at government schools and a directive issued by the Deputy Director of Education (North West). He said he did not intend to take a political stance but wanted to spread information.

In the video, Sant Ram can be heard saying that it came to his notice that teachers were being assigned duties linked to stray dog-related work. Claiming that an order and a list was circulated in the North West district, he said teachers had been designated as nodal officers for three zones and that 118 teachers had been named overall. Calling the situation "thought-provoking and condemnable", he added, "For the sake of the children, let us focus on teaching in our schools."

NEWS BOX

'This Is Not About Drugs Or Democracy, But Oil': Kamala Harris Slams Trump Over Maduro's Capture

ADEN, Yemen. (Agency)

Former US Vice President Kamala Harris on Saturday slammed US President Donald Trump over the capture of former Venezuelan dictator Nicolás Maduro and his wife, Cilia Flores. She said the operation was driven by oil interests, not concerns over drugs.In a post on X, Harris said Trump's actions in Venezuela would not make the United States safer. She warned that forced regime change could destabilize the region, putting American lives at risk.Donald Trump's actions in Venezuela do not make America safer, stronger, or more affordable. That Maduro is a brutal, illegitimate dictator does not change the fact that this action was both unlawful and unwise. We've seen this movie before—wars for regime change or oil that are sold as strength but turn into chaos, and American families pay the price," she wrote.Harris said the American public did not support such military actions and accused Trump of misleading people."The American people do not want this, and they are tired of being lied to. This is not about drugs or democracy. It is about oil and Donald Trump's desire to play the regional strongman. If he cared about either, he wouldn't pardon a convicted drug trafficker or sideline Venezuela's legitimate opposition while pursuing deals with Maduro's cronies," she added.Harris, who contested the recent presidential election against Trump, also warned that the operation could put US troops at risk and lacked any legal basis or exit plan.The President is putting troops at risk, spending billions, destabilizing a region, and offering no legal authority, no exit plan, and no benefit at home. America needs leadership whose priorities are lowering costs for working families, enforcing the rule of law, strengthening alliances, and—most importantly—putting the American people first," she wrote.

Soon after the US strike on Venezuela in the early hours of Saturday, President Donald Trump held a news conference at his Mar-a-Lago residence. There, he announced that the United States would take control of Venezuela's vast oil reserves.

Four Killed As Private Helicopter Crashes In Remote Arizona Canyon

world . (Agency)

A private helicopter crashed in a rugged, mountainous region of central Arizona on Friday, killing all four people on board, local authorities confirmed.

According to the Pinal County Sheriff's Office, the victims included the 59-year-old pilot, two women aged 21, and another woman aged 22. The identities of those killed have not yet been made public, pending notification of their families, reported Kens5.The crash occurred at approximately 11 a.m. near Telegraph Canyon, a remote area located about 64 miles east of Phoenix. Preliminary information indicates the helicopter may have struck a recreational slackline stretched across the canyon. Authorities said the line extended more than half a mile across the mountainous terrain.The sheriff's office said an eyewitness contacted emergency services after observing the helicopter collide with part of the slackline before plunging into the canyon below. The impact caused the aircraft to fall into a difficult-to-access area, complicating rescue and recovery efforts.The helicopter had reportedly departed earlier in the day from an airport in Queen Creek, a town located around 29 miles west of the crash site. Due to the isolated location and rough terrain, emergency crews had to walk for several hours to reach the wreckage.As a precautionary measure, temporary flight restrictions were imposed over the area to ensure the safety of response teams and to prevent further incidents, the sheriff's office said.Federal authorities have launched a formal investigation into the crash. The Federal Aviation Administration (FAA) and the National Transportation Safety Board (NTSB) will jointly examine the circumstances leading up to the incident, including the aircraft's flight path, mechanical condition, and the placement of the slackline, reported Kens5.

Saudi Finance Minister approves SR217 ($57.9) billion borrowing plan for 2026

world. (Agency)

Saudi Arabia is laying out its financing roadmap for the year ahead. With a sizeable budget deficit forecast and major debt repayments due, the Kingdom has approved a detailed borrowing plan for 2026 that aims to balance funding needs with long-term debt sustainability, while continuing to deepen local markets and tap global investors.

Borrowing plan approved and scope defined

Saudi Arabia's Minister of Finance, Mohammed Al-Jadaan, who also serves as Chairman of the National Debt Management Centre, has approved the Kingdom's annual borrowing plan for the 2026 fiscal year.The plan provides a comprehensive overview of public debt developments during 2025 and outlines initiatives designed to strengthen the local debt market. It also sets out the financing plan and guiding principles that will govern borrowing activities in 2026. A key component of the document is the issuance calendar for the Local Saudi Sukuk Issuance Program, which will be conducted in Saudi riyals throughout the year.

Maduro now in New York jail as Trump says US to 'run' Venezuela

The surprise advance by the separatists in early December shifted power in Yemen, which has been at war for more than a decade, fracturing the coalition against the Houthis and laying bare divisions between Gulf allies Saudi Arabia and the UAE.

world . (Agency)

First visuals released by US authorities show Venezuelan President Nicolás Maduro in handcuffs, flanked by armed personnel, walking through a corridor inside the US Drug Enforcement Administration headquarters in New York City, hours after he was captured in a dramatic US military operation and flown out of Venezuela along with his wife, Cilia Flores.According to AP, the visuals were released after Maduro and Flores were brought to New York following what U.S. officials described as a swift, highly coordinated operation that unfolded early Saturday and ended Maduro's rule within hours. Both are expected to be held in federal custody and face criminal charges linked to a long-standing U.S. Justice Department indictment accusing them of involvement in a narco-terrorism conspiracy.

According to the latest reports Maduro was in a New York jail.A Reuters report said the operation, named Operation Absolute Resolve, had been planned and rehearsed for months. Once launched, it was completed in under 30 minutes. US forces carried out air raids on multiple targets in and around Venezuela's capital Caracas before detaining Maduro and his wife and flying them out of the country. At least 40 people were killed during the airstrikes in Caracas, a Venezuelan official told The New York Times, according to Reuters.

Speaking after the capture, U.S. President Donald Trump said the United States would run Venezuela "at least temporarily" until a transition could be put in place. "We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition," Trump said at a press conference, adding that Washington would

tap Venezuela's vast oil reserves and sell "large amounts" to other countries, reported AP.Maria Corina Machado, the US-backed opposition leader and last year's Nobel Peace Prize recipient, posted on social media that "the hour of freedom has arrived" and called for the opposition's 2024 election candidate, Edmundo Gonzalez Urrutia, to "immediately" assume the presidency.But Trump was notably cool about expectations that Machado could become Venezuela's new leader, saying she did not have "support or respect" inside the country. Instead, Trump publicly praised Vice President Delcy Rodríguez , appointed acting president by Venezuela's Supreme Court saying "she's essentially willing to do what we think is necessary to make Venezuela great again," reported AP.The court had said it would debate the legal framework required to guarantee the continuity of the state, governance and national defence in light of the "forced absence" of the president, reported Reuters.The US military action has triggered widespread international reaction. The United Nations Security Council is scheduled to meet on Monday at the request of Colombia, backed by Russia and China, to discuss the situation. UN Secretary General Antonio Guterres has expressed concern that the U.S.

US will run Venezuela until safe transition: Donald Trump at presser following Maduro capture

world. (Agency)

For decades, China was synonymous with birth control, enforced, incentivised and institutionalised under its infamous one-child policy. Now, in a striking reversal, the Xi Jinping-led country has made contraception costlier, signalling just how desperate the country has become to reverse its demographic declineFrom January 1, China scrapped a long-standing tax exemption on contraceptive drugs and devices, subjecting condoms and oral contraceptive pills to a 13 percent value-added tax, the standard rate for consumer goods. The move is part of a broader, increasingly aggressive push to nudge couples towards parenthood as the world's second-largest economy grapples with a shrinking and ageing population.

WHY CHINA WANTS MORE BABIES, FAST?

China's population declined for the third consecutive year in 2024, a trend demographers warn is likely to persist. People aged 60 and above now make up over 20 percent of the population, a share projected by the United Nations to swell dramatically in the coming decades.The fear haunting policymakers is that China may "get old before it gets rich", an outcome

that would strain public finances, shrink the workforce and undermine long-term economic growth. Unlike Japan or South Korea, which face similar ageing challenges with far richer economies, China's social security and healthcare systems remain underprepared.Besides, China's fertility rate has plunged to among the lowest in the world, far below the replacement level of 2.1. By 2021, it stood at around 1.16, well below the OECD benchmark for a stable population.The implications go beyond numbers. Fewer births today mean fewer workers tomorrow — threatening productivity, consumption and China's global economic standing. With youth unemployment high and economic growth slowing, Beijing sees reversing the fertility slump as a strategic necessity, not just a social goal.

HAUNTING ONE CHILD POLICY

January 2026 will mark ten years since China officially scrapped its one-child policy, which had been in force since 1980. Introduced to rein in runaway population growth, the policy fundamentally reshaped Chinese society, delaying marriages, normalising small families and embedding state control into reproductive choices.ut the rollback of birth limits, first to two children, then three, has failed to deliver a baby boom. The habits, costs and social expectations shaped by decades of restriction have proved far harder to undo.

US 'military operation' in Venezuela disrupts Caribbean travel, hundreds of flights canceled

world . (Agency)

The US military operation that captured Venezuelan President Nicolás Maduro and flew him out of the country early Saturday also disrupted Caribbean travel at a busy travel time for the region.

No airline flights were crossing over Venezuela that day, according to FlightRadar24.com. And major airlines canceled hundreds of flights across the eastern Caribbean region and warned passengers that disruptions could continue for days after the Federal Aviation Administration imposed restrictions.

Flights were canceled to and from Puerto Rico, the Virgin Islands, Aruba and more than a dozen other destinations in the Lesser Antilles island group north of Venezuela. Airlines waived change fees for passengers who had to reschedule flights.

But US Transportation Secretary Sean Duffy said Saturday night that the restrictions would end at midnight EST and airlines would be able to resume normal operations Sunday.Southwest Airlines said in a statement that it added six extra round-trip flights to Puerto Rico on Sunday's schedule and another eight round-trips on Monday to help get travelers home from their vacations. It also added two additional Sunday flights to Aruba.At the Queen Beatrix airport in Aruba, a popular holiday destination for US vacationers just 15 miles (24 kilometers) off Venezuela's coast, officials said they expected a return to normal Sunday after a day of canceled flights that stranded travelers or blocked them from flying to the island.In Barbados, Prime Minister Mia Mottley said at a news conference that "the consequences of the conflict have been exceedingly disruptive to both of our ports of entry," an airport as well as a seaport from which cruise ships sail.

In Puerto Rico, Lou Levine, his wife and their three children were due to return to the Washington, DC, area Saturday morning, but he woke up to his wife saying their flight was canceled. He found out why when he checked his phone.They first tried calling JetBlue to reschedule. The airline called back about two hours later, but the agent was not able to help them. Levine and his wife saw others messaging JetBlue on social media and did the same. The airline responded and booked them on a flight Saturday, turning their weeklong New Year's holiday into a two-week sojourn.Levine, a manager at a software company, said he is fortunate to have a flexible and understanding employer. But his daughter will be missing a week of high school. And then there are the unexpected expenses."I love it here. But we have dog-sitting and cat-sitting and car rental. It's fine. It's just really painful on the wallet," Levine said.

Venezuela's 'hour of freedom' has arrived: opposition leader Machado

Machado said that opposition candidate Edmundo Gonzalez Urrutia, whom the opposition says won the vote, "must immediately assume his constitutional mandate" as president.

CARACAS. (Agency)

Venezuelan opposition leader and Nobel Peace Prize laureate Maria Corina Machado said Saturday the "hour of freedom" had arrived for her country after the United States seized strongman Nicolas Maduro.

Machado, who has been mostly in hiding since Maduro's disputed reelection in July 2024, said in a statement that opposition candidate Edmundo Gonzalez Urrutia, whom the opposition says won the vote, "must immediately assume his constitutional mandate" as president."Venezuelans, the HOUR OF FREEDOM has arrived!" she posted on social media after an early-morning US military strike on Caracas.Machado is abroad in an unknown location after traveling

under cover to Oslo in December to receive her Nobel, which she dedicated to US President Donald Trump as she welcomed US intervention in her country.

"Today we are ready to enforce our mandate and take power. Let us remain vigilant, active, and organized until the Democratic Transition is realized. A transition that needs ALL of us," she said on Saturday."We are going to restore order," she stated, adding Gonzalez Urrutia must now be "recognized as Commander in Chief of the National Armed Forces by all officers and soldiers."Machado was barred from running in the 2024 election by institutions loyal to Maduro, and was replaced on the ticket by Gonzalez Urrutia, a little-known diplomat.She has been hailed for her fight for democracy, but also criticized for aligning herself with Trump.

She was awarded the Nobel prize for "her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy."Gonzalez Urrutia wrote on X on Saturday that "these are decisive hours, know that we are ready for the great operation of the reconstruction of our nation."

'Serious affront': US strike on Venezuela triggers condemnation, calls to uphold international law

world .(Agency)

Tensions sparked in the Western Hemisphere after the United States hit Venezuela with a "large-scale strike" on Saturday and said President Nicolás Maduro and his wife were captured and flown out of the country.The attack was condemned by Venezuela's allies and left-wing governments across Latin America, while the EU and UK said that international law must be respected.At a pro-Maduro protest in Caracas, Mayor Carmen Meléndez joined a crowd that demanded that Maduro be returned immediately.

"Maduro, hold on, the people are rising up!" the crowd chanted. They also said: "We are here Nicolás Maduro. If you can hear us, we are here!" Elsewhere, residents were still taking in the events."How do I feel? Scared, like everyone," said Caracas resident Noris Prada, who sat on an empty avenue looking down at his phone."Venezuelans woke up scared, many families couldn't sleep. I have been on the street, I just got back from Maracay, everything is blocked, everything is bad, very bad.""They impose the law," electrician Alfonso Valdez said about the US government. "They are the police of the world … they are assassins."However, Venezuelan opposition leader Maria Corina Machado's spokespeople declined to comment on the US operation.Machado was last seen in public last month, when she emerged from 11 months in hiding and traveled to Norway, where she was honored with the Nobel Peace Prize.Reacting to the attacks, Mexico's left-wing government condemned the US strikes saying any form of military action In a statement released by the foreign ministry, the southern neighbour of the US said that they "strongly condemns and rejects the military actions carried out unilaterally in recent hours by the armed forces of the United States of America against targets on the territory of the Bolivarian Republic of Venezuela".Echoing similar criticism, Brazilian President Luiz Inacio Lula da

Silva also slammed the attacks as a "serious affront" to the country's sovereignty.

"The bombings in Venezuelan territory and the capture of its president cross an unacceptable line" the left-wing Lula wrote on X, saying they threaten "the preservation of the region as a zone of peace."He urged the international community, through the United Nations, to "respond vigorously" to the attacks.

Amid rising tensions, British Prime Minister Keir Starmer said that all the countries should "uphold international law".

Calling the situation "fast-moving", Starmer added that "the UK was not involved in any way in this operation" as he urged patience in order to "establish the facts".

"I want to speak to President Trump, I want to speak to allies," the British leader said in brief comments aired on UK television hours after the US attack."I can be absolutely clear that we were not involved in that. And as you know, I always say and believe we should all uphold international law."Starmer added that "hopefully more information will come out" about the situation when Trump holds a press conference later Saturday.

NEWS BOX

After rewriting Indian sprinting in 2025, Animesh Kujur wants more

NEW DELHI. (Agency)

I want to hit 10-flat in 2026," sprinter Animesh Kujur told India Today during his off-season. It is not something he has spoken about publicly before. But after the kind of year he has had, Animesh knows that dreaming quietly is no longer enough.

2025 was the breakthrough year for Animesh Kujur. His speed turned heads, his times rewrote record books, and suddenly the conversation around Indian sprinting had a new name at its centre. Last season, Animesh became the fastest man in India. He clocked 10.18 seconds in the 100 metres and 20.32 seconds in the 200 metres, his preferred event. At various points through the year, he simply kept stepping up — race after race,

meet after meet.Despite being introduced to sprinting later than most, the 22-year-old's rise has been steady rather than sudden. Those who have followed his journey closely know that 2025 was not a freak spike.From breaking national records multiple times to competing on the U23 Diamond League circuit and running the heats at the World Athletics Championships, Animesh did most things an Indian sprinter dreams of in a single season. There were moments of awe too — meeting his idol Usain Bolt, watching the world's best from close quarters — moments that stayed with him long after the spikes came off.Now, as 2026 approaches, Animesh wants more."The revelling part is done," he says. "Now I want to stamp my authority."

"I want to become the first Indian to do 10-flat and 20-flat in the 100 and 200," Animesh said. "I'm heavily invested in it. I want to get it done at the Senior Federation meet (May, 2026) itself."With the Asian Games set to take place in September, Animesh believes that he will be a medal contender in at least two of the events that he will participate in — the 200m sprint and the 4x100m men's relay.

"This time, when I go to the Asian Games, I'll go as a medal contender, not just to participate," he said. "Asian Games and Commonwealth Games are my main targets."

Ruturaj Gaikwad over Rishabh Pant vs NZ was a straight decision: R Ashwin

RANCHI. (Agency)

Former India spinner Ravichandran Ashwin has questioned the logic behind India's ODI squad selection for the upcoming three-match series against New Zealand, stating that picking Ruturaj Gaikwad over Rishabh Pant should have been a "clear and logical" decision. Ashwin felt Gaikwad's omission, despite his strong recent performances, did not align with form or team balance.

Ashwin explained that Gaikwad had earned his place after delivering when given the opportunity and would also have fitted better into India's ODI combination. Speaking on his YouTube show Ash ki Baat, Ashwin said the decision came down to choosing between a specialist batter and a second wicketkeeper, and in his view, the answer was obvious."Could Gaikwad have been kept in the squad? I think that was a real possibility," Ashwin said.The only spot of

contention is between Pant and Gaikwad. It was a straight decision. Shreyas Iyer deserved to come back after the injury, so no discussion there. It is his rightful position."Ashwin further elaborated on why he felt Gaikwad was the more suitable option in the current setup.

"Between a second wicketkeeper and a batter, you can get a keeper from anywhere to cover," he added."At four or five, I'm sticking my neck out, his batting against spin, his running between the wickets and his ability to close out an innings is phenomenal."India's squad announcement on January 3 saw the return of captain Shubman Gill and vice-captain Shreyas Iyer, along with Mohammed Siraj. To accommodate these inclusions, Gaikwad was left out despite scoring his maiden ODI century against South Africa in Raipur and continuing his good form in the Vijay Hazare Trophy with a century and a fifty in his last two matches.Ashwin also touched upon Pant's role in white-ball cricket, suggesting that the left-hander is better suited to the top order rather than the middle. In contrast, he believes Gaikwad's skill set makes him a natural fit for the middle overs in ODIs.

BCCI hasn't done anything wrong: Former India captain on Mustafizur Rahman issue

Former India captain Mohammed Azharuddin praised BCCI for its swift action in dropping Mustafizur Rahman from IPL 2026. The decision has sparked tensions, with Bangladesh seeking to move its T20 World Cup matches out of India.

New Delhi. (Agency)

Former India captain Mohammed Azharuddin has praised the BCCI (Board of Control for Cricket in India) for their swift action regarding the controversy surrounding Mustafizur Rahman's participation in the upcoming Indian Premier League 2026 (IPL 2026). Several politicians had openly expressed their displeasure with the Bangladeshi fast bowler's inclusion in the tournament, citing repeated incidents of violence against Hindus in the neighbouring country.Amid widespread criticism, the BCCI acted promptly and asked Kolkata Knight Riders (KKR) to release Rahman from their squad, who had acquired him for Rs 9 crore at the mini-auction in December.

The decision was welcomed by a large section of citizens, in light of ongoing reports of targeted killings of Hindus in Bangladesh.

Mohammed Azharuddin also condemned the tragic state of affairs in Bangladesh and commended the BCCI for their swift response.The board hasn't done anything wrong. What's happening in Bangladesh is not good. But in sports, it's different. However, whatever decision the board has taken, they must have taken it after consulting with the Ministry of External Affairs and the Ministry of Home Affairs," Azharuddin told ANI.After being released by KKR, Mustafizur Rahman also commented on the matter, saying, "What else can you do if you are dropped?"Meanwhile, in the aftermath of the incident, Bangladesh's interim government has instructed the Bangladesh Cricket Board to seek a change of venue for the team's matches at the ICC Men's T20 World Cup 2026, requesting that they be

moved out of India.The decision was confirmed by Bangladesh's sports adviser, Asif Nazrul, who announced the development in a social media post on Saturday, 3 January. Nazrul stated that the interim government has directed the BCB to formally inform the International Cricket Council and propose Sri Lanka as an alternative venue for Bangladesh's matches in the tournament.

Bangladesh to stop broadcast of IPL matches

The issue was also discussed at an emergency Bangladesh Cricket Board meeting on Saturday, sources told India Today. Nazrul further revealed that he has asked the Minister of Information and Broadcasting to stop the broadcast of IPL matches in Bangladesh. Strained diplomatic ties between India and Bangladesh now appear set to impact cricketing relations as well, with bilateral engagements likely to be put on hold. While the Bangladesh Cricket Board has announced plans for a limited-overs series in September and even released a proposed itinerary, the BCCI is understood to be unwilling to tour Bangladesh at this stage.The series, which includes three ODIs followed by three T20Is, was originally scheduled for last year but was postponed indefinitely after the Indian board raised security concerns.

Amid IPL snub row, Mustafizur Rahman scripts history with 400 T20 wickets

NEW DELHI. (Agency)

Amid the ongoing controversy surrounding his ouster from the Indian Premier League (IPL), Bangladesh pacer Mustafizur Rahman scripted history on Friday, January 2. The left-arm seamer became the fastest pacer to reach the landmark of 400 wickets in T20 cricket.The 30-year-old achieved the feat in his 315th match during a Bangladesh Premier League (BPL) clash against the Sylhet Titans at the Sylhet International Cricket Stadium.Turning out for the Rangpur Riders, Mustafizur returned figures of 4-0-24-3 to guide his side to a six-wicket victory. He reached the milestone by dismissing Mehidy Hasan Miraz and later added the wickets of Afif Hossain Dhrubo and Khaled Ahmed to his tally.Mustafizur now has 402 wickets from 315 T20 matches at an impressive economy rate of 7.43 with six four-wicket hauls and four five-wicket hauls.

MUSTZFIZUR REMOVED FROM IPL

On Saturday, Kolkata Knight Riders released Mustafizur from their squad ahead of the IPL 2026 season, acting on a directive issued by the Board of Control for Cricket in India. The franchise confirmed the decision in an official statement, stating it had complied with instructions from the

BCCI in its role as the governing body of the Indian Premier League.

The development was confirmed exclusively to India Today by BCCI secretary Devajit Saikia, bringing clarity to days of uncertainty over the left-arm pacer's future in the league. Saikia said KKR had been formally asked to part ways with the Bangladesh international, while adding that the board had assured the franchise of a replacement option.

Mustafizur had been signed by KKR for Rs 9.20 crore at the IPL 2026 mini-auction in December 2025. While the move initially drew attention for cricketing reasons, it soon became controversial, with opposition emerging from sections of the political spectrum and certain religious groups. The backlash intensified in the days following the auction, ultimately culminating in the franchise's decision to release the bowler.

Reacting to the development, Mustafizur said there was little he could have done, noting that his exclusion was an IPL decision and beyond his control.

BANGLADESH MINISTRY LASHES OUT

Meanwhile, the episode has coincided with rising tensions off the field. Bangladesh's interim government has instructed the Bangladesh Cricket Board to seek a change of venue for the team's matches at the ICC Men's T20 World Cup 2026, requesting that they be moved out of India.

ISL return explained: How Indian football's return from the dead might look

NEW DELHI. (Agency)

After months of limbo, Indian football finally has a pulse again. The All India Football Federation (AIFF) has confirmed that the 2025–26 season of the Indian Super League will go ahead, with the official schedule expected to be announced next week. While the green light has brought relief across the football ecosystem, one major question still hangs in the air: what will the ISL actually look like when it returns?The delay stemmed from uncertainty off the pitch rather than on it. The expiry of the Master Rights Agreement with the league's former commercial partner in December 2024 left the ISL without a clear financial roadmap.

Following an Emergency Committee meeting,

AIFF reviewed the AIFF–ISL Coordination Committee's report, submitted on January 2, and formally decided to conduct the season. What remains undecided is the format — and that is where two distinct proposals come into play.

Return first, criticism later

Both formats reflect the same reality: survival first, perfection later. With no commercial partner in place following the end of the Football Sports Development Limited era, cost efficiency has overtaken ambition. Centralised venues, reduced travel, fewer fixtures and leaner operations are seen as unavoidable short-term trade-offs.

The ISL's return itself is the bigger victory. Format debates can wait, but getting India's top-tier football back on the pitch is the immediate priority. For now, the league is alive again — and in the current climate, that alone feels like a small win for Indian football.

Mohammed Shami's comeback doors to team India still open: Irfan Pathan

Irfan Pathan believes Mohammed Shami still has a chance to return to the Indian cricket team, despite not playing international cricket since March 2025. Shami has been toiling hard in domestic cricket, having bowled over 200 overs in the ongoing season.

CHENNAI. (Agency)

Former India all-rounder Irfan Pathan feels the doors are still open for Mohammed Shami to make a comeback to the Indian team. Shami was once again left out of the Indian squad for the upcoming three-match ODI series against New Zealand, beginning on January 11.The fast bowler last played for India during their victorious campaign in the ICC Champions Trophy 2025 and has found himself out of the team since then. However, despite being out of the side for several months, Pathan feels Shami still has it in him to break back into the national team."The biggest talking point is Mohammed Shami. What is his future? He's not someone who came yesterday, played a few matches and left. He has taken 450–500 international wickets, which is a huge number. If you have taken more than 400 wickets and then you get dropped and questions are raised about your fitness — that happens with everyone. As long as you play cricket, you have to keep proving yourself," said Pathan on his YouTube channel.Pathan further suggested that Shami should perform at his best in the upcoming Indian Premier League 2026 (IPL 2026) season to get back into contention.Ever since being dropped from the national side, Shami has been toiling hard in domestic cricket. The speedster has bowled over 200 overs in the ongoing season across the Ranji Trophy, Syed Mushtaq Ali Trophy and the Vijay Hazare Trophy (VHT), taking 47 wickets in total.

In the ongoing Vijay Hazare Trophy, India's premier 50-over domestic tournament, Shami is the leading wicket-taker for Bengal with 15 wickets to his name from seven innings, at an average of 14.93 and an economy rate of 8.90. After the VHT, Shami will feature in the remainder of the Ranji Trophy season, followed by the IPL, where he will be playing for Lucknow Super Giants (LSG) after being bought by them at the IPL 2026 auction for Rs 10 crore.

Declan Rice is one of the best: Mikel Arteta praises Arsenal star in Bournemouth win

Declan Rice delivered another statement performance as Arsenal beat Bournemouth 3–2. Mikel Arteta hailed the midfielder as one of the world's best, praising his influence, growth and match-winning impact in a crucial title push.

NEW DELHI. (Agency)

Declan Rice earned glowing praise from Mikel Arteta after delivering a match-winning performance in Arsenal's hard-fought 3–2 victory over AFC Bournemouth. Rice scored twice in the second half to turn the game on its head, helping Arsenal consolidate their position at the top of the Premier League table.Arteta was unequivocal in his assessment, insisting Rice now belongs among the very best midfielders in world football. Speaking after the match, the Arsenal manager highlighted not only Rice's decisive goals but also his continued evolution and growing importance within the team.For me, the ones that we have are the best and Declan is constantly adding things to his game, constantly adding things to his role in the team."Arteta went on to stress that Rice's development is far from complete.

"I don't see where he can stop because he can still improve in a lot of areas and he wants to improve," he added.

"He is such a pivotal player for us."

The match itself was anything but straightforward for Arsenal. Bournemouth struck first inside 10 minutes when Gabriel Magalhes' loose pass gifted Evanilson a simple finish with David Raya caught out of position. Gabriel

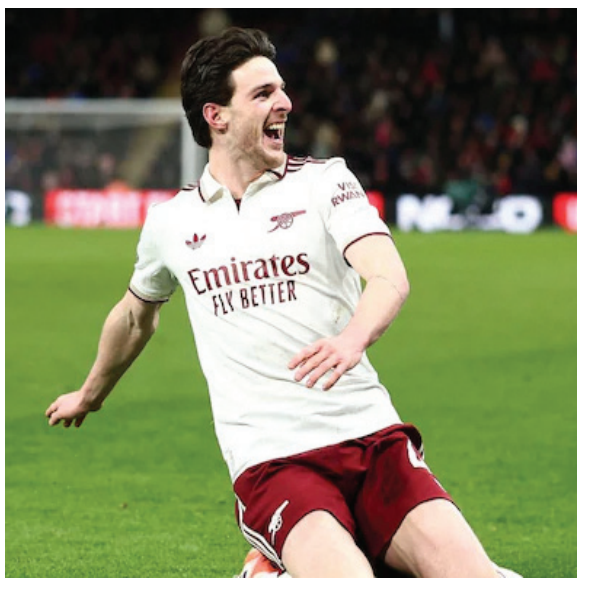

responded quickly, however, scoring the equaliser six minutes later to steady the visitors.After the break, Rice took control. His first goal put Arsenal ahead before a second, finished from a Bukayo Saka cutback, appeared to seal the contest. Junior Kroupi's superb long-range strike in the 76th minute set up a tense finale at the Vitality Stadium, but Arsenal showed resilience to see out the win and move six points clear of Manchester City at the summit.

Rice's display was particularly notable given he had missed Arsenal's midweek win over Aston Villa due to a knee issue. Arteta later revealed that the midfielder sent a "big message" to the squad by making himself available and then producing a man-of-the-match performance.

Since arriving from West Ham United in 2023 for a club-record £105 million, Rice has steadily reshaped his game. Once seen primarily as a holding midfielder, the 26-year-old has flourished in a more advanced role, blending goals, leadership and control.

Uorfi Javed's

Black-And-White Outfit Gives 2026 An Oversized Welcome

Uorfi Javed continues to be one of the internet's most talked-about style icons. Known for her fearless experimentation and unconventional fashion choices, Uorfi once again grabbed attention by unveiling her first self-designed outfit of 2026, proving that she never shies away from pushing creative boundaries.Taking to Instagram, Uorfi shared a reel giving fans a behind-the-scenes look at how she conceptualised and styled her latest creation. The video showcased not just the finished look but also the effort and struggle involved in wearing the statement outfit.She captioned the post with her signature wit and wrote, " New year ki nahi guys new Janak ki zaroorat hai."

Inside Uorfi Javed's Bold Black-and-White Avant-Garde Outfit

The outfit itself is a dramatic black-and-white ensemble defined by a strong geometric pattern and a highly unconventional silhouette. The design features a form-fitting bottom paired with an exaggerated, sculptural top, creating a powerful visual contrast.The monochrome pattern is composed of vertical, horizontal, and diagonal lines, forming a striking optical illusion that adds depth and movement to the outfit. One of the most eye-catching elements is the extremely wide, structured shoulders and oversized collar, lending the look an architectural and avant-garde appeal.

Underneath the structured outer layer, Uorfi wore a black tank top, adorned with circular, embellished detailing across the chest. She completed the look with large light pink or white drop earrings, which softened the sharp edges of the outfit while maintaining its dramatic flair.

Uorfi Javed Spotted in Andheri, Poses for Paparazzi

Later, Uorfi was spotted stepping out in Andheri, confidently wearing the same statement outfit. As expected, she posed for the paparazzi with ease, turning heads and commanding attention with her bold fashion choice.

Uorfi Javed Steps Out With Sisters Asfi and Dolly

During the outing, Uorfi was joined by her sisters, Asfi Javed and Dolly Javed. The trio posed together for photographers, transforming a casual appearance into a full-fledged style moment.

Interestingly, Uorfi later switched up her look by ditching the structured suit and opting for a more relaxed combination. She paired a black sleeveless top with the high-waisted, patterned midi skirt from her earlier outfit, offering a fresh yet cohesive styling twist.

Uorfi Javed's Professional Update: The Traitors Win

On the work front, Uorfi Javed was most recently seen on the reality show The Traitors, where she impressed viewers with her sharp gameplay and ultimately emerged as the winner of the show.

Sara Ali Khan

Shares Glimpses Of Her New Year Vacation, Wishes 'Hamesha Naseeb Ho Aisi Jannat'

Bollywood actress Sara Ali Khan, who was recently seen in 'Metro… In Dino', has shared glimpses from her recent trip.On Saturday, the actress took to her Instagram and shared a series of pictures from her vacation amidst the snow. The pictures also featured her sibling, Ibrahim Ali Khan.

She wrote in the caption, "Meri Mannat, hamesha naseeb ho aisi Jannat (My wish, I always get such a heaven)".Sara is the daughter of Saif Ali Khan and actor Amrita Singh. She belongs to the Pataudi family, her paternal grandfather was Mansoor Ali Khan Pataudi, former captain of the Indian cricket team and the Nawab of Pataudi. Her paternal grandmother is actor Sharmila Tagore. Sara's parents separated in 2004, and she was raised primarily by her mother.

Ibrahim is her younger brother, and she has two half-siblings, Taimur Ali Khan and Jeh Ali Khan, from Saif Ali Khan's marriage to Kareena Kapoor Khan. Sara completed her schooling in Mumbai and graduated from Columbia University, New York, with a degree in History and Political Science. She made her foray in cinema with 'Kedarnath' opposite Sushant Singh Rajput, earning recognition for her debut performance.

The same year, she appeared in 'Simmba', which was commercially successful. Her subsequent films include 'Love Aaj Kal', 'Atrangi Re', 'Gaslight', and 'Zara Hatke Zara Bachke'. Her career has seen mixed critical and commercial outcomes. She continues to work across theatrical and streaming platforms and remains an active figure in mainstream Hindi cinema.

Meanwhile, on the work front, the actress was recently seen in 'In Metro… In Dino' in which she plays a young, urban woman navigating relationships,

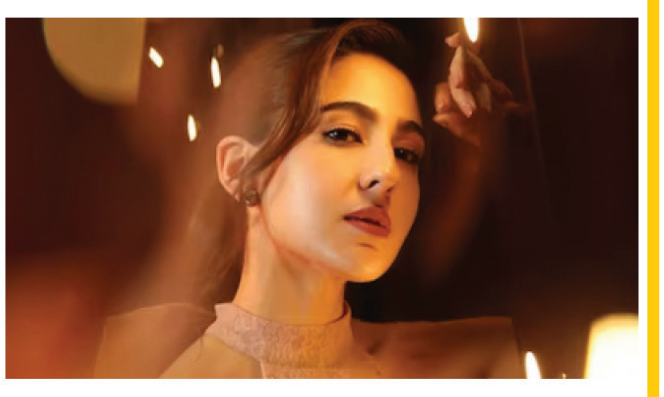

ambition, and emotional uncertainty in a contemporary city setting.

Her character represents the modern generation dealing with commitment issues, career pressure, and evolving definitions of love. Her storyline intersects with others to reflect how personal choices impact relationships in today's fast-paced urban life. The film, directed by Anurag Basu, focuses on layered human emotions rather than plot-driven drama, and Sara's role contributes to this mosaic by portraying vulnerability, confusion, and self-reflection. The character is grounded in realism, aligning with the film's slice-of-life theme.

Who Is Stebin Ben? Meet Singer Who Just Got Engaged To Kriti Sanon's Sister Nupur

Actor-entrepreneur Nupur Sanon, sister of Kriti Sanon, surprised fans this weekend by announcing her engagement to singer Stebin Ben. Nupur shared a series of pictures from the proposal, giving followers a glimpse into the intimate moment. One of the photos shows Stebin down on one knee, with placards in the background reading, "Will you marry me?" Other pictures capture Nupur smiling as she shows off her diamond ring."In a world full of maybes, I found the easiest YES I've ever had to say," Nupur wrote, alongside the photos.For the proposal, Nupur opted for a floral dress, while Stebin kept things classic in a white shirt paired with a blue blazer and matching trousers.

Who Is Stebin Ben?

Born and raised in Bhopal, Stebin Ben discovered his love for music early in life. His first brush with performing came at school, where he realised that singing was more than just a hobby. College fests and local competitions followed, slowly building his confidence.

In 2016, Stebin moved to Mumbai to chase a full-time career in music. Like many newcomers, the early days were far from glamorous. He performed at cafés and clubs across the city, relying on small gigs while trying to get noticed.That breakthrough came when his cover of Mera Dil Bhi Kitna Pagal Hai went viral online. The attention helped him land his first major break with Zee Music, making his base for a steady rise in the industry.

From Viral Covers To Chart-Topping Songs

Over the years, Stebin has lent his voice to songs picturised on actors like Sidharth Malhotra, Akshay Kumar, Rajkummar Rao, Emraan Hashmi, Vijay Deverakonda, Tiger Shroff and Shahid Kapoor. He has also collaborated with composers and singers, including Shreya Ghoshal, Himesh Reshammiya, Sachin-Jigar, Jeet Gannguli and Mohit Suri.His song Sahiba emerged as a breakout hit, dominating streaming platforms and cementing his place as one of the most recognisable voices in the current pop-playback space. Tracks like Baarish Ban Jaana, Rula Ke Gaya Ishq and Baarish Aayi Hai later turned into social media favourites.

'First Time I Pushed Myself This Hard': Bigg Boss 19's Shehbaz Badesha Shares BTS Video From Upcoming Song

Bigg Boss 19's Shehbaz Badesha has shared a glimpse of his upcoming song shoot, revealing that he has been working with full dedication.

Bigg Boss 19 came to an end last month with Gaurav Khanna emerging as the winner. Many contestants have already landed exciting opportunities post the reality show. A few days ago, Shehbaz Badesha shared a video revealing that he is shooting for a new music video, his first project after Bigg Boss 19. Now, Shehbaz has shared another video giving a behind-the-scenes glimpse from the shoot of the music video. He revealed that he has been working with full dedication, and asked fans for their support when the song drops.

Bigg Boss 19's Shehbaz Badesha Says He's Never Worked This Hard

On Saturday, Shehbaz shared a BTS video on Instagram that shows him running with a blanket wrapped around his face. His hair looked drenched, and as he ran, he said that he has never worked so hard in his entire life. In his caption, he further added, "5 a.m. shoots, cold water, and pure dedication. First time I pushed myself this hard. Hope you all support me when my song drops." Check out the video below!

Meanwhile, last month, Shehbaz Badesha opened up about his future projects. When asked by the media, "Kuch new aa raha hain bhai?", he replied enthusiastically, "Gaana aa raha hain mera jaldi se jaldi aur ek show ayega jaldi se jaldi… comedy show hain".

Shehbaz Badesha is known for his pranks and hilarious antics in the Bigg Boss 19 house. He shared a great friendship with Amaal Mallik on the reality show. During an interview with Screen, Shehbaz reflected on his bond with Amaal Mallik and shared, "I don't mind if people are saying that I played the game in Amaal's shadow; he is like a brother to me. People can take a bullet for their friend, so this was just a game. And I accept it if people are calling me Amaal's sidekick."

He went on to add, "We will continue our friendship outside too. We bonded in the game where the situations were tough, so this friendship will stay for life."